चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

मूल्य 5 रुपये

1986 से प्रकाशित | 28 दिसंबर, 2015–03 जनवरी, 2016 | हर शुक्रवार को प्रकाशित | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

फोटो : प्रभात पाण्डेय

विदेशियों के हवाले उच्च शिक्षा

संस्कृत में एक श्लोक है, जिसका अर्थ है कि विद्या से विनय, विनय से पात्रता, पात्रता से धन, धन से धर्म और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है. लेकिन, यह कल की बात थी. अब जो तैयारी चल रही है, उसके मुताबिक विद्या अब सिर्फ़ धन कमाने का ज़रिया भर बनेगी. शिक्षा अब सिर्फ़ कौशल (स्किल) देने भर का माध्यम होगी. जैसे, आप अंग्रेजी बोलना तो सीख जाएंगे, लेकिन अंग्रेजी साहित्य को समझना-पढ़ना आपके वश की बात नहीं होगी. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अगर भारत डब्ल्यूटीओ से की गई अपनी प्रतिबद्धता पूरी करता है, तो यकीन मानिए, इस देश में शिक्षा तब दान की नहीं, व्यापार की वस्तु बनकर रह जाएगी.

शशि शेखर

शिक्षा अधिकार है, शिक्षा राष्ट्र निर्माण का आधार है, लेकिन दुनिया की नज़र में यही शिक्षा व्यापार है. भारत की 125 करोड़ की आबादी दुनिया के लिए महज एक बाज़ार है. यहां के खेत, यहां के किसान, यहां की हर चीज दुनिया के लिए एक व्यापारिक वस्तु भर है. नतीजा यह कि पिछले 25 वर्षों में धीरे-धीरे सब कुछ वैश्विक बाज़ार के हाथों में चला गया. बाकी रह गई थी शिक्षा. अब विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ ने जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज (गैट्स) के तहत शिक्षा को भी व्यापारिक सेवा के अंतर्गत शामिल कर लिया है. इसका अर्थ यह हुआ कि जिस तरह से दुनिया भर की कंपनियों के लिए भारत के खेत-खलिहानों के रास्ते खोल दिए गए थे, अब उसी तरह से भारत का उच्च शिक्षा क्षेत्र भी विदेशी कंपनियों को मुनाफ़ा कमाने के लिए खोल दिया जाएगा. ज़ाहिर है, जब बात मुनाफ़ा कमाने की होगी, तो फिर कैसी और कितनी शिक्षा आपके बच्चों को मिलेगी, इसका सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है. विश्व व्यापार संगठन के तीन बहुपक्षीय समझौते हैं, जिनमें एक प्रमुख समझौता है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज (गैट्स). गैट्स के तहत शिक्षा को भी एक सेवा माना गया है. इसका अर्थ यह हुआ कि विश्व व्यापार संगठन में शामिल देश, एक-दूसरे के यहां शिक्षा का व्यापार कर सकते हैं, अपने कॉलेज-यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं और अपने हिसाब से पाठ्यक्रम तय कर सकते हैं. वे यह तय कर सकते हैं कि इस देश के बच्चों को क्या पढ़ाना है और क्या नहीं पढ़ाना है. अब सवाल यह है कि इस सबके बीच भारत की क्या भूमिका है और इससे वह कैसे प्रभावित होगा? भारत की शिक्षा व्यवस्था कैसे प्रभावित होगी और भारत के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से वंचित वर्ग कैसे इस पूरी प्रक्रिया से प्रभावित होंगे?

इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है वर्ष 2001 में कतर की राजधानी दोहा में आयोजित विश्व व्यापार संगठन के मंत्री स्तरीय सम्मेलन से. इस सम्मेलन में उच्च शिक्षा के दरवाजे व्यापार करने के लिए खोलने पर बातचीत हुई. कहा गया कि इस चर्चा को हम आगे जारी रखेंगे और इस पर सहमति बनाने की कोशिश करेंगे कि विश्व व्यापार संगठन में शामिल देश अपने यहां उच्च शिक्षा में व्यापार की अनुमति दें. इस प्रस्ताव पर भारत एवं चीन समेत क़रीब साठ देश सहमति दे चुके हैं. जबकि यह प्रावधान है कि भारत या कोई भी देश, चाहे तो इस समझौते से बाहर रह सकता है. जैसे, अफ्रीकन और यूरोपियन यूनियन ने साफ़ तौर पर इस समझौते को मानने से इंकार कर दिया और कहा कि हम अपने यहां की उच्च शिक्षा विश्व व्यापार संगठन के हवाले नहीं करेंगे. वैसे भारत एवं चीन द्वारा इस समझौते पर दी गई सहमति में अंतर है. भारत के मशहूर शिक्षाविद् अनिल सद्गोपाल बताते हैं कि जहां भारत ने गैट्स के सारे प्रावधानों को मानने की बात की है, वहीं चीन ने अनबाउंड (कोई बंधन नहीं) का विकल्प चुना है. फिलहाल यह जानना ज़रूरी है कि भारत द्वारा गैट्स के प्रावधानों को मानने और अपनी उच्च शिक्षा विश्व व्यापार संगठन के हवाले करने का अर्थ क्या है? गैट्स के मुताबिक, जो भी देश अपने यहां शिक्षा में व्यापार की अनुमति देगा, उसे अपने यहां उच्च शिक्षा में निवेश करने वाले कॉरपोरेट घरानों (विदेशी निवेश समेत) को समतामूलक ज़मीन मुहैय्या करानी होगी.

इसका अर्थ यह हुआ कि यदि भारत में कोई विदेशी कंपनी अपना विश्वविद्यालय खोलती है, तो उसे भारत के अन्य विश्वविद्यालयों से प्रतियोगिता करने के लिए समान अवसर, समान धरातल मुहैय्या कराना होगा. इस बात को समझाते हुए अनिल सद्गोपाल बताते हैं कि आज अगर भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिल्ली विश्वविद्यालय को सौ करोड़ रुपये का अनुदान भवन बनाने, नया ढांचा तैयार करने, रिसर्च और शिक्षा के लिए देता है, तो उसे निजी विश्वविद्यालयों को भी यह सुविधा देनी होगी. लेकिन चूंकि यह संभव नहीं है, इसलिए यूजीसी समान धरातल मुहैय्या कराने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय को भी यह सुविधा देना बंद कर देगा. अनिल सद्गोपाल बताते हैं कि आगे यह भी संभव है कि सरकारी कॉलेजों-विश्वविद्यालयों से अपना फंड खुद जुटाने के लिए कहा जाएगा. उनसे कहा जाएगा कि उनके पास

(शेष पृष्ठ 2 पर)

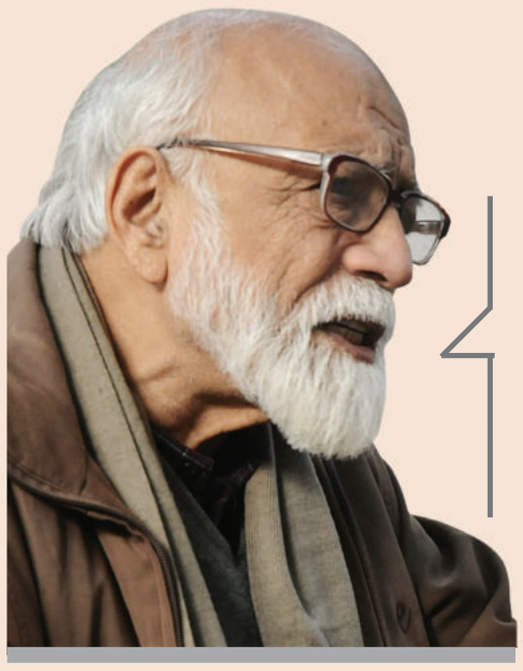

> दुनिया के बाज़ार को सस्ते कुशल-अर्द्धकुशल कामगार चाहिए. उसे ऐसे कामगार नहीं चाहिए, जो सवाल कर सकें. इसलिए हमारी सरकार कहती है, हम तुम्हें स्किल (कौशल) सिखाएंगे. ग़रीबों के बच्चे अभी भी उच्च शिक्षा नहीं हासिल कर पा रहे हैं, इसलिए ग़रीब बच्चों को स्किल्ड करके दुनिया के बाज़ारों की ज़रूरत पूरी की जाएगी. इस सबके लिए मनमोहन सिंह सरकार के समय से ही नीतियां बनाई जा रही थीं. अब नरेंद्र मोदी उन्हीं नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं. यह सब डब्ल्यूटीओ का एजेंडा पूरा करता है.
> ***-अनिल सद्गोपाल, शिक्षाविद्.***

यूपीए सरकार ने विश्व व्यापार संगठन के इन प्रावधानों के अनुसार देश के क़ानूनी ढांचे को बदलने के लिए उच्च शिक्षा से संबंधित छह विधेयक संसद में पेश किए थे, जिनमें विदेशी विश्वविद्यालयों को अनुमति देने से संबंधित विधेयक भी शामिल था. इसके अलावा उन विधेयकों में यूजीसी, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, एआईसीटीई, एनसीटीई एवं बीसीआई को हटाने की भी बात थी, ताकि इन नियामक संस्थाओं को ख़त्म करके विदेशी निवेशकों के लिए सुविधाजनक रास्ता तैयार किया जा सके. यह अलग बात है कि उनमें से एक भी विधेयक पारित नहीं हुआ. लेकिन, इस तरह के विधेयकों को मौजूदा सरकार द्वारा पारित कराए जाने की आशंका तब तक बरकरार रहेगी, जब तक कि सरकार खुद को ऐसे समझौते से पूरी तरह अलग न कर ले.

समाज पर असर

यदि हमारे देश के उच्च शिक्षा क्षेत्र में यह समझौता लागू हो जाता है, तो इसका समाज पर क्या असर पड़ेगा? इस सवाल के जवाब में अनिल सद्गोपाल कहते हैं कि पहले से ही हमारे देश में पिछड़े वर्ग के बमुश्किल दस प्रतिशत बच्चे बारहवीं तक पढ़ाई कर पाते हैं, आदिवासियों एवं अल्पसंख्यकों की संख्या इससे भी कम है. यदि उच्च शिक्षा में विदेशी घुसपैठ होती है, तो यह इतनी महंगी हो जाएगी कि इसका खर्च उठा पाना समाज के पिछड़े, ग़रीब एवं वंचित वर्ग के लिए और अधिक मुश्किल हो जाएगा. ज़ाहिर है, गैट्स प्रावधानों के मुताबिक, जब देश में सरकारी उच्च शिक्षण संस्थाओं के सामने भी स्ववित्त पोषित होने की मजबूरी होगी, तो फीस बढ़ेगी. अभी तो सरकारी अनुदान या कहें कि सब्सिडी की वजह से आम आदमी के बच्चे दिल्ली विश्वविद्यालय या जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ने की हिम्मत जुटा लेते हैं, लेकिन शिक्षा के पूर्ण व्यवसायीकरण और निजीकरण की स्थिति में उच्च शिक्षा उनकी हैसियत से बाहर की चीज हो जाएगी. ■

शिंजो अबे की भारत यात्रा : सफलताएं और आशंकाएं | P-4

यूपी में नई ग्राम सरकार | P-5

मोदी सरकार वक्फ बोर्ड को नहीं दे रही है पैसा | P-10

विदेशियों के हवाले उच्च शिक्षा

पृष्ठ 1 का शेष

जो अतिरिक्त ज़मीन है, उसे बेचकर, फीस बढ़ाकर अपना खर्च जुटाएं, ताकि गैट्स समझौते के तहत सभी संस्थाओं को आपस में प्रतियोगिता करने के लिए समान धरातल मिल सके.

ज़ाहिर है, यदि ऐसा होता है, तो कल यह संभव है कि सरकारी कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को वेतन के भी लाले पड़ जाएं. यदि कल को सरकारी संस्थाएं स्ववित्त पोषित हो जाती हैं, तो उनका पाठ्यक्रम भी बाज़ार नियंत्रित हो जाएगा. इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि आने वाले समय में इन संस्थाओं को बाज़ार की मांग के अनुसार आपूर्ति करनी पड़ेगी. ज़ाहिर है, बाज़ार को कुशल या अर्द्धकुशल कामगार चाहिए, न कि विद्वान. ऐसे में इन उच्च सरकारी शिक्षण संस्थाओं में आज जो रिसर्च आदि का काम होता है, उसके उलट सिर्फ़ बाज़ार की ज़रूरत के हिसाब से कामगारों की आपूर्ति करनी होगी. इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं. जैसे, बाज़ार को अंग्रेजी बोलने वाले लोग चाहिए, तो ये उच्च शिक्षण संस्थाएं अंग्रेजी साहित्य पढ़ाने की जगह ऐसे विद्यार्थी तैयार करेंगी, जो सिर्फ़ अंग्रेजी बोल सकें, न कि उन्हें अंग्रेजी साहित्य का ज्ञान हो. जीव विज्ञान की जगह सिर्फ़ बायो टेक्नोलॉजी पढ़ाने की मजबूरी होगी. अनिल सद्गोपाल बताते हैं कि शिक्षा के तीन मकसद होते हैं– ज्ञान, मूल्य और कौशल. आने वाले समय में यदि भारत सरकार गैट्स समझौते को अपना लेती है, तो शिक्षा में से ज्ञान एवं मूल्य ख़त्म हो जाएंगे और सिर्फ़ बचेगा कौशल. कौशल यानी कुशल और अर्द्धकुशल कामगार पैदा करना.

यूपीए सरकार ने विश्व व्यापार संगठन के इन प्रावधानों के अनुसार देश के क़ानूनी ढांचे को बदलने के लिए उच्च शिक्षा से संबंधित छह विधेयक संसद में पेश किए थे, जिनमें विदेशी विश्वविद्यालयों को अनुमति देने से संबंधित विधेयक भी शामिल था. इसके अलावा उन विधेयकों में यूजीसी, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, एआईसीटीई, एनसीटीई एवं बीसीआई को हटाने की भी बात थी, ताकि इन नियामक संस्थाओं को ख़त्म करके विदेशी निवेशकों के लिए सुविधाजनक रास्ता तैयार किया जा सके. यह अलग बात है कि उनमें से एक भी विधेयक पारित नहीं हुआ. लेकिन, इस तरह के विधेयकों को मौजूदा सरकार द्वारा पारित कराए जाने की आशंका तब तक बरकरार रहेगी, जब तक कि सरकार खुद को ऐसे समझौते से पूरी तरह अलग न कर ले. इस तरह की आशंका को और अधिक बल तब मिलता है, जब हम यह देखते हैं कि मौजूदा केंद्र सरकार दिल्ली विश्वविद्यालय या अन्य विश्वविद्यालयों पर च्वॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम थोपती है, एकल विश्वविद्यालय क़ानून बनाने की कोशिश की जाती है. ऐसा कहा जा रहा है कि एकल विश्वविद्यालय का प्रावधान विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ के एजेंडे का ही एक हिस्सा है. हाल में यूजीसी द्वारा ग़ैर नेट छात्रवृत्तियां बंद करने का फ़ैसला भी डब्ल्यूटीओ के नियमों के अनुसार शिक्षा पर सार्वजनिक खर्च घटाने के प्रावधानों के मुताबिक लिया गया फ़ैसला माना जा रहा है.

यह सब कबसे और कैसे लागू होता है, इस बारे में फिलहाल तो कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन डब्ल्यूटीओ की दोहा वार्ता के दौरान ही भारत ने अगस्त 2005 में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विदेशी कंपनियों के प्रवेश को लेकर अपनी प्रतिबद्धता ज़ाहिर कर दी थी. हालांकि, डब्ल्यूटीओ में व्यापार समझौता (व्यापार में ही शिक्षा भी शामिल है) प्रतिबद्धता अभी तक किसी अंतिम परिणाम तक नहीं पहुंची है, लेकिन 2005 के बाद से ही या कहें कि उससे भी पहले से सरकारें लगातार उच्च शिक्षा में विदेशी निवेश आए और विदेशी कंपनियां यहां कॉलेज–विश्वविद्यालय खोल सकें, इसके लिए काम करती रहीं. कई सारी कमेटियों ने भी इसकी वकालत की. मसलन, सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में बने नेशनल नॉलेज कमीशन (राष्ट्रीय ज्ञान आयोग) ने कहा था कि भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारी निवेश यानी क़रीब 190 बिलियन अमेरिकी डॉलर की ज़रूरत है, ताकि लक्ष्य पूरा किया जा सके और इसके लिए कमीशन ने एफडीआई के ज़रिये धन जुटाने का सुझाव दिया था. ज़ाहिर है, इस सबका मकसद यह था कि सरकार धीरे–धीरे सबको समान शिक्षा देने के अपने दायित्व से मुक्त होती चली जाए और उसकी जगह देशी–विदेशी निजी कंपनियां शिक्षा का व्यापार कर सकें.

बहरहाल, सरकार और डब्ल्यूटीओ के इस प्रयास का भारत समेत पूरी दुनिया भर में विरोध हो रहा है. भारत में इसके विरोध में विभिन्न धाराओं और विभिन्न विचारों के संगठन शामिल हैं. अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंच के बैनर तले विभिन्न राज्यों के सैकड़ों संगठन उच्च शिक्षा को डब्ल्यूटीओ के हवाले करने का विरोध कर रहे हैं. तेलंगाना से शुरू हुआ विरोध का स्वर दिसंबर में दिल्ली तक पहुंचा, जहां जंतर–मंतर पर देश भर से आए संगठनों ने सरकार से डब्ल्यूटीओ में उच्च शिक्षा के व्यापारीकरण के प्रति जताई गई अपनी प्रतिबद्धता तुरंत वापस लेने की मांग की. अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंच का मानना है कि यदि विदेशी विश्वविद्यालय यहां सिर्फ़ ज्ञान के प्रसार या फिर आदान–प्रदान के लिए आते और उनका मकसद सिर्फ़ आपस में शैक्षणिक–सांस्कृतिक संबंधों का विकास करना भर होता, तो किसी विरोध की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यह कहानी इतनी भर नहीं है, बल्कि इससे कहीं आगे की है. मंच का कहना है कि इस समझौते के तहत जो विदेशी विश्वविद्यालय भारत आएंगे, वे सिर्फ़ और सिर्फ़ मुनाफ़ा कमाने के लिए आएंगे, न कि समाज सेवा के लिए. ऐसे समझौते की आड़ में घटिया स्तर के विदेशी विश्वविद्यालय भी यहां अपनी शाखाएं खोलेंगे, मोटी फीस वसूलेंगे और मुनाफ़ा कमाएंगे. ■

विश्व व्यापार संगठन के तीन बहुपक्षीय समझौते हैं, जिनमें एक प्रमुख समझौता है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज (गैट्स). गैट्स के तहत शिक्षा को भी एक सेवा माना गया है. इसका अर्थ यह हुआ कि विश्व व्यापार संगठन में शामिल देश, एक-दूसरे के यहां शिक्षा का व्यापार कर सकते हैं, अपने कॉलेज-यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं और अपने हिसाब से पाठ्यक्रम तय कर सकते हैं. वे यह तय कर सकते हैं कि इस देश के बच्चों को क्या पढ़ाना है और क्या नहीं पढ़ाना है. अब सवाल यह है कि इस सबके बीच भारत की क्या भूमिका है और इससे वह कैसे प्रभावित होगा? भारत की शिक्षा व्यवस्था कैसे प्रभावित होगी और भारत के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से वंचित वर्ग कैसे इस पूरी प्रक्रिया से प्रभावित होंगे?

कैसे-कैसे प्रावधान

विश्व बैंक ने हाल में वैश्विक बाज़ार के लिए कई नियामकों एवं संस्थानों की जगह स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण (आईआरए) और सिंगल विंडो क्लियरेंस का विचार प्रस्तावित किया है. उदाहरण के लिए, भारत में उच्च शिक्षा से जुड़े संस्थानों एवं नियामक प्राधिकरणों में यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया आदि शामिल हैं. मतलब यह कि इतने सारे संस्थान होने की वजह से वैश्विक बाज़ार को अपना धंधा चलाने में मुश्किलें पेश आएंगी, इसलिए इन्हें ख़त्म करके एक अकेली संस्था बना दी जाए. इन्हें हटाने का दूसरा अर्थ यह भी है कि सरकारी संस्थानों से मुक़ाबला करने में विदेशी संस्थानों को आसानी होगी. सरकार एवं विभिन्न कमेटियों की तरफ़ से इस बारे में दुष्प्रचार भी शुरू हो चुका है. इसके अलावा यशपाल कमेटी ने कहा है कि इसकी जगह एक ही संस्था नेशनल काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्चेज बनाई जाए. नेशनल नॉलेज कमीशन ने भी इसी तरह की एक संस्था बनाने का सुझाव दिया है. 2014 के अपने चुनावी घोषणा-पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने भी उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए कई संस्थानों के बजाय एक उच्च अधिकार प्राप्त केंद्रीय संस्थान बनाने की बात कही थी. अनिल सद्गोपाल कहते हैं कि यह सब करना ख़तरनाक होगा और इससे उच्च शिक्षा की संप्रभुता के लिए ख़तरा पैदा हो जाएगा. ऐसी स्थिति में हमारी सरकार को उच्च शिक्षा के लिए कोई नई योजना लाने से पहले डब्ल्यूटीओ ट्रेड रेगुलेशन काउंसिल (व्यापार नियमन परिषद) के पास जाना होगा. एक व्यापार नीति समीक्षा तंत्र हर साल सदस्य देशों की नीतियों की समीक्षा करेगा और सुझाव देगा. ज़ाहिर है, इस सबका अर्थ सीधे-सीधे अपने देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था को डब्ल्यूटीओ के हाथों गिरवी रखने जैसा होगा. ■

shashishekhar@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 07 अंक 43
दिल्ली, 28 दिसंबर, 2015–03 जनवरी, 2016

RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)

सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना–800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के – 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–6451999, 6450888
विज्ञापन व प्रसार 022–42296060, +91–8451050786, +91–9266627379
फैक्स न. 0120–2544378

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

छापे पर राजनीति

दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय पर सीबीआई छापे को लेकर अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी सरकार के बीच तकरार कायम है. केजरीवाल का कहना है कि उनके कार्यालय पर छापा मारा गया, जबकि सीबीआई का कहना है कि छापा मुख्यमंत्री कार्यालय पर नहीं, बल्कि उनके प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के कार्यालय पर मारा गया. 1989 बैच के आईएएस अधिकारी राजेंद्र कुमार केजरीवाल के पिछले मुख्यमंत्रित्व काल में उनके सचिव थे. सीबीआई का कहना है कि राजेंद्र कुमार के ख़िलाफ़ वर्ष 2002 से 2005 के दौरान अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने के आरोप का मामला दर्ज किया गया है. यह आरोप वरिष्ठ नौकरशाह आशीष जोशी द्वारा लगाया गया था, जो उस समय दिल्ली डायलॉग कमीशन के सदस्य सचिव थे. इन सबके अतिरिक्त हाल के दिनों में दिल्ली सरकार के कुछ बाबू भी ख़बरों में छाए रहे. सीबीआई ने हाल में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजय प्रताप सिंह (अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अल्पसंख्यक विभाग के प्रधान सचिव) को रिश्वत लेने के जुर्म में गिरफ्तार किया. हालांकि, मुख्यमंत्री कार्यालय को घेरे में रखा गया और इस दौरान कोई कोहराम भी नहीं मचा. कुमार के मामले में भी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के प्रमुख एमके मीणा से शिकायत की गई थी. बहरहाल, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की तकरार में सीबीआई को राजनीतिक रंग दिया जा चुका है. ■

विदेश मंत्रालय का बढ़ता प्रभाव

पिछले वर्ष जब एस जयशंकर ने विदेश सचिव का पद संभाला, तबसे विदेश मंत्रालय घरेलू मोर्चे पर अपना प्रभाव बढ़ा रहा है. मंत्रालय दूसरे देशों के साथ तो व्यस्त रहा ही, उसने भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को सरकार के अन्य मंत्रालयों एवं विभागों में भी तैनात करना शुरू कर दिया. असल में यह एक पुरानी प्रथा है, खासकर पेट्रोलियम और वाणिज्य मंत्रालय में, जहां कुछ पद विदेश मंत्रालय के अधिकारियों–कर्मचारियों के लिए रखे जाते हैं. पिछले कुछ समय से आईएफएस अधिकारियों की कमी के चलते ऐसा नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है. रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ अब अपने जासूसी रैंक में संयुक्त सचिव स्तर के एक आईएफएस अधिकारी को जोड़ेगी, ताकि बाहर के कोवर्ट ऑपरेशंस को थोड़ा डिप्लोमैटिक बनाया जा सके. बाबू बिरादरी को जानने वाले बताते हैं कि 1986 बैच के आईएफएस अधिकारी एजी शर्मा इस नए पद के अहम दावेदार हैं. इसी तरह शंभु कुमारन भी रक्षा मंत्रालय में इंटरनेशनल को–ऑपरेशन देखने के लिए जाएंगे. इस पद पर पिछले एक दशक से आईएएस अधिकारी ही तैनात रहे हैं. ■

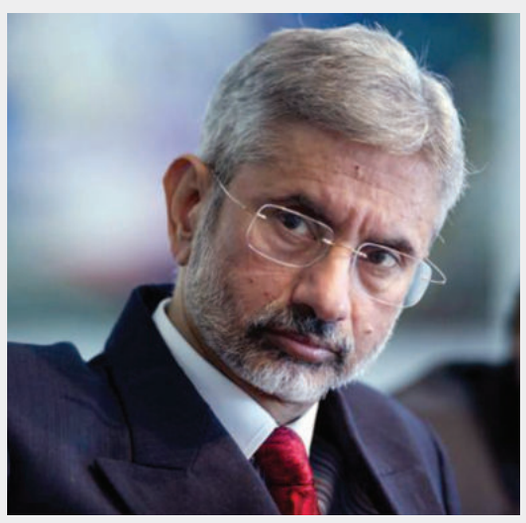

जावेद पर फडनवीस की कृपा

भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी एवं मुंबई पुलिस आयुक्त जावेद अहमद को सऊदी अरब में भारतीय राजदूत के रूप में ज़िम्मेदारी सौंपने जैसे मामले एक आईपीएस अधिकारी के तौर पर अपने आप में कम देखने को मिलते हैं. इससे पहले जूलियो रिबेरो को रोमानिया में भारतीय राजदूत बनाकर भेजा गया था. रिबेरो वर्ष 1982 से 1985 तक मुंबई के पुलिस आयुक्त रहे थे. पुलिस आयुक्त पद के लिए योग्य होने के बावजूद उन्हें राकेश मारिया के बाद इसके लिए लाइन में रखा गया. मारिया महाराष्ट्र की पूर्ववर्ती कांग्रेस–राष्ट्रवादी कांग्रेस सरकार के खास थे. यह अहमद का सौभाग्य था कि उन्हें भाजपाई मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस ने मारिया को बाहर कर मुंबई का पुलिस आयुक्त बनाया. ग़ौरतलब है कि सऊदी अरब में भारतीय राजदूत का पद बीते अप्रैल माह से रिक्त था. सूत्रों के अनुसार, उक्त पद के लिए फडनवीस ने अहमद के नाम का प्रस्ताव भेजा था. ■

सर्वोच्च न्यायालय ने 1978 में यह निर्णय दिया था कि देश के सामान्य व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री बनने का हक है. ऐसे में हरियाणा सरकार के फरमान को सही माना जाए तो अयोग्य व्यक्ति पंच भी नहीं बन सकता, लेकिन विधायक और सांसद बनकर प्रदेश और देश का कानून बना सकता है, जो कि हास्यास्पद है. गौर करने वाली बात यह भी है कि 60 प्रतिशत आबादी को शिक्षा तथा शौचालय के आधार पर शासन प्रक्रिया से प्रतिबन्धित करना संविधान के अनुच्छेद-14, 19 एवं 21 का उल्लघंन है.

हरियाणा पंचायत चुनाव

उच्चतम न्यायालय को फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए

सभी फोटो-*प्रभात पाण्डेय*

हमारे देश की सर्वोच्च अदालत आदर्श स्थिति को सामने रखकर के फैसले करती है, लेकिन देश की वास्तविकता को नज़रअंदाज कर देती है. देश में आज भी अशिक्षा है, लोगों के पास दो वक्त की रोटी नहीं है और कई तरह की सामाजिक समस्याएं हैं, दूसरी तरफ सरकारें अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही हैं, इसी वजह से कदम-कदम पर अदालतों को विधायिका के काम में दखल देना पड़ता है. यदि सरकारें देश के सभी गांवों का एक समान विकास पूरी जिम्मेदारी से करतीं तो उच्चतम न्यायालय के इस फैसले पर सवाल नहीं उठते. यदि हरियाणा में पंचायत चुनाव में मापदंड जारी हुए हैं तो यह कैसे हो सकता है कि आने वाले समय में विधानसभा और लोकसभा के लिए कोई मापदंड जारी न हो.

संविधान हमें देश का नागरिक होने के नाते कई अधिकार देता है, उन अधिकारों को सुरक्षित रखने का जिम्मा देश के सर्वोच्च न्यायालय का होता है. लेकिन जब देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले से देश का नागरिक लोकतंत्र में भागीदारी यानी चुनाव लड़ने के अधिकार से सिर्फ इसलिए वंचित हो जाता है, क्योंकि उसके पास चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता नहीं है, उसके पास शौचालय नहीं है तो क्या यह निर्णय भारतवर्ष की वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक स्थिति के अनुरूप है, वह भी तब, जब देश की सत्तर प्रतिशत आबादी दो डॉलर कम से कम आमदनी में जीवनयापन करने को मजबूर है, क्या यह निर्णय उन लाखों बेघरों के पक्ष में है, जो सीधे तौर पर दलितों और वंचितों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदार बनाने की जगह उन्हें वोटों की गिनती में परिवर्तित करना चाहती है.

साल 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की 0.15 प्रतिशत आबादी यानी लगभग 18 लाख लोगों के पास घर नहीं है. ऐसे में हरियाणा सरकार ने पंचायती राज कानून में संशोधन करके चुनाव लड़ने के लिए घर में शौचालय होना अनिवार्य कर दिया है. इसके अलावा हर वर्ग के लिए अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण भी इस कानून के तहत किया गया है. 2011 की जनगणना के अनुसार ही देश के घरविहीन लोगों में से 39.2 प्रतिशत शिक्षित हैं. घर न होने के कारण वे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं. ऐसे में ये लोग लोकतांत्रिक प्रणाली की मुख्यधारा से दूर हो जाते हैं और यह फैसला सीधे तौर पर उन्हें देश के दोयम दर्जे के नागरिक में तब्दील कर देता

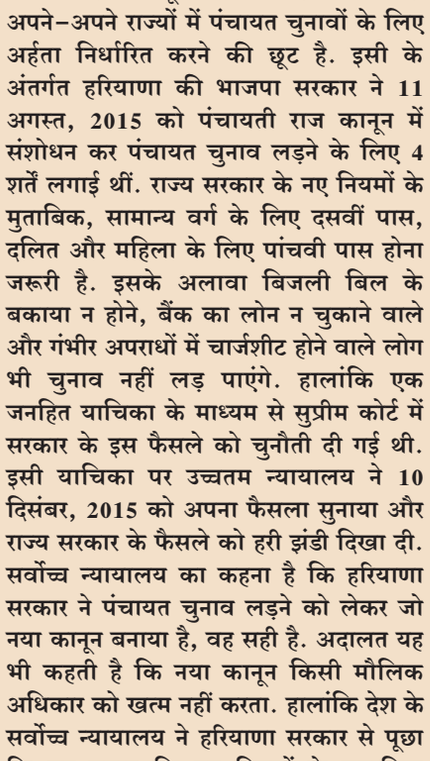

है. ऐसे में देश की सर्वोच्च अदालत राज्य सरकार के फैसले पर अपनी मुहर लगा दे तो सवाल पैदा होता है कि उन लोगों का क्या होगा, जो पैसा और संसाधन नहीं होने की वजह से पढ़ाई और शौचालय की सुविधा से वंचित रह गए हैं. घरविहीन लोगों में से 0.10 प्रतिशत आबादी ग्रामीण और 0.25 शहरी हैं. अकेले हरियाणा की कुल आबादी का 2.93 लोगों के पास घर नहीं है. इन आंकड़ों से यह बात साफ है कि हरियाणा सरकार के पंचायत चुनाव लड़ने के लिए अर्हता के प्रावधान तर्कसंगत नहीं हैं.

73वें संविधान संशोधन से लाए गए पंचायती राज कानून के अंतर्गत राज्यों के पास अपने-अपने राज्यों में पंचायत चुनावों के लिए अर्हता निर्धारित करने की छूट है. इसी के अंतर्गत हरियाणा की भाजपा सरकार ने 11 अगस्त, 2015 को पंचायती राज कानून में संशोधन कर पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 4 शर्तें लगाई थीं. राज्य सरकार के नए नियमों के मुताबिक, सामान्य वर्ग के लिए दसवीं पास, दलित और महिला के लिए पांचवी पास होना जरूरी है. इसके अलावा बिजली बिल के बकाया न होने, बैंक का लोन न चुकाने वाले और गंभीर अपराधों में चार्जशीट होने वाले लोग भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. हालांकि एक जनहित याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में सरकार के इस फैसले को चुनौती दी गई थी. इसी याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने 10 दिसंबर, 2015 को अपना फैसला सुनाया और राज्य सरकार के फैसले को हरी झंडी दिखा दी. सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि हरियाणा सरकार ने पंचायत चुनाव लड़ने को लेकर जो नया कानून बनाया है, वह सही है. अदालत यह भी कहती है कि नया कानून किसी मौलिक अधिकार को खत्म नहीं करता. हालांकि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार से पूछा कि वह बताए कि नए नियमों के मुताबिक कितने लोग पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा में टॉयलेट और स्कूलों की संख्या की भी जानकारी मांगी थी. हरियाणा की ओर से अदालत में पेश हुए अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने बताया कि नए नियमों के मुताबिक, 43 फीसदी लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि राज्य के 84 फीसदी घरों में टॉयलेट हैं, जबकि 20 हजार स्कूल हैं. हालांकि याचिकाकर्ता ने सरकार पर गलत आंकड़े पेश करने का आरोप लगाया और बताया कि हकीकत में यह संख्या 43 फीसद नहीं, बल्कि 64 फीसद है और अगर दलित महिलाओं की बात करें तो यह संख्या 83 फीसद तक पहुंच जाती है. उन्होंने दावा किया कि सरकार ने जो आंकड़े दिए हैं, वह प्राथमिक शिक्षा के आधार पर दिया है. यह भी कहा गया कि सरकार ने घरों की संख्या 2012 के आधार पर दी है, जबकि शौचालय की संख्या आज के आधार पर. इसी तरह राज्य सरकार ने 20 हजार स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों की भी गिनती की है, जबकि हकीकत यह है कि राज्य में दसवीं के लिए सिर्फ 3200 स्कूल हैं, यानी राज्य के लगभग आधे गांवों में दसवीं तक के स्कूल तक नहीं हैं.

अब सवाल यह उठता है कि ऐसे लोग, जिनके पास न शिक्षा है और न ही शौचालय ऐसे लोग कहां जाएंगे, इन लोगों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में वोट का अधिकार और चुनाव लड़ने के अधिकार को तवज्जो दी है, लेकिन हाल के फैसले से अन्य संवैधानिक अधिकार प्रभावित होते हैं. ध्यान देने योग्य बात यह है कि देश की संविधान सभा ने विधायकों और सांसदों की शिक्षा के बारे में कोई संवैधानिक प्रतिबन्ध नहीं लगाया था. ऐसे में हरियाणा या राजस्थान की पंचायतों के चुनाव पर संविधान में संशोधन के बिना किसी भी तरह का प्रतिबंध कितना मायने रखता है? एक बात और कि सर्वोच्च न्यायालय ने 1978 में यह निर्णय दिया था कि देश के सामान्य व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री बनने का हक है. ऐसे में हरियाणा सरकार के फरमान को सही माना जाए तो अयोग्य व्यक्ति पंच भी नहीं बन सकता, लेकिन विधायक और सांसद बनकर प्रदेश और देश का कानून बना सकता है, जो कि हास्यास्पद है. गौर करने वाली बात यह भी है कि 60 प्रतिशत आबादी को शिक्षा तथा शौचालय के आधार पर शासन प्रक्रिया से प्रतिबन्धित करना संविधान के अनुच्छेद-14, 19 एवं 21 का उल्लघंन है.

क्या हमारे देश में कोर्ट का यह फैसला कानूनी मदद से देश में उन लोगों के लिए सत्ता काबिज करने का रास्ता नहीं खोल देगा, जिन लोगों के पास पैसा और पढ़ने-लिखने की सुविधा है. हमारे देश के सरकारी आंकड़ों के हिसाब से बहुत बड़ी संख्या स्कूलों में जाती ही नहीं है. बहुत बड़ी संख्या में पांचवीं के बाद बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं. उससे भी बड़ी संख्या में बच्चे छठी-सातवीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके पास जीविका के साधन नहीं हैं. गरीब आदमी अपने बच्चे को स्कूल से इसलिए निकाल लेता है, क्योंकि वह चाहता है कि उसके परिवार की आय में वृद्धि हो सके. शिक्षा का अधिकार केवल 14 वर्ष की उम्र तक या कहें माध्यमिक शिक्षा तक ही यह अधिकार देता है, लेकिन जो प्रावधान हरियाणा के कानून में हैं, वे इस कानून के पूरक नहीं हैं. पहले सरकार 10वीं तक की शिक्षा की गारंटी दे, उसके बाद शिक्षा की अनिवार्यता लागू करे तो सबकुछ ठीक है, लेकिन हकीकत यह है कि साक्षर और शिक्षित होने में जमीन-आसमान का फर्क है. यदि देश की व्यवस्था को चलाने का जिम्मा डिग्री होल्डर के पास है तो सारी ताकत देश के पचास प्रतिशत लोगों के बीच केंद्रित हो जाएगी. देश की आधी आबादी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से दूर हो जाएगी, देश एक बार फिर दो ध्रुवों में बंट जाएगा. धीरे-धीरे देश में उनका शासन हो जाएगा, जिनके पास कुछ है. जिनके पास कुछ नहीं है, वो सत्ता से दूर हो जाएंगे और वंचित की श्रेणी में आकर वो अपना हिस्सा हासिल करने के लिए हिंसक आंदोलन कर सकते हैं.

हमारे देश की सर्वोच्च अदालत आदर्श स्थिति को सामने रखकर के फैसले करती है, लेकिन देश की वास्तविकता को नज़रअंदाज कर देती है. देश में आज भी अशिक्षा है, लोगों के पास दो वक्त की रोटी नहीं है और कई तरह की सामाजिक समस्याएं हैं, दूसरी तरफ सरकारें अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही हैं, इसी वजह से कदम कदम पर अदालतों को विधायिका के काम में दखल देना पड़ता है. यदि सरकारें देश के सभी गांवों का एक समान विकास पूरी जिम्मेदारी से करतीं तो उच्चतम न्यायालय के इस फैसले पर सवाल नहीं उठते. यदि हरियाणा में पंचायत चुनाव में मापदंड जारी हुए हैं तो यह कैसे हो सकता है कि आने वाले समय में विधानसभा और लोकसभा के लिए कोई मापदंड जारी न हो. यदि उनके लिए कोई मापदंड जारी होते हैं तो जाहिर है कि वह 10वीं से निश्चित रूप से अधिक होगा. इसका मतलब आप देश की 70 प्रतिशत जनता को शासन की प्रक्रिया से सीधे तौर पर बाहर कर देंगे.

ऐसा न हो कि इतिहास में कोर्ट के इस फैसले को आम आदमी, कमजोर आदमी, गरीब आदमी की लोकतंत्र में भागीदारी को समाप्त करने की दिशा में उठाए गए कदम के रूप में जाना जाए. ये देश या लोकतंत्र हर उस व्यक्ति के लिए है, जो इस देश में पैदा हुआ है या लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखता है और लोकतंत्र में विश्वास रखने का पहला लक्षण वोट देना है. जो व्यक्ति वोट दे सकता है, वह इस देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है. चाहे वो पढ़ा-लिखा हो या न हो. इस देश को अब तक बहुत से पढ़े-लिखे लोगों ने बर्बाद किया है. जिसकी वजह से यह देश विकास और नई आर्थिक व्यवस्था के दुष्चक्र में फंस चुका है. संपूर्ण देश की सत्ता का एकाधिकार सौंपेंगे तो आप विश्वास कीजिए कि राजसत्ता के खिलाफ बहुत सी ऐसी ताकतें खड़ी हो जाएंगी, जो संघर्ष का बिगुल बजाने लगेंगी. इसे रोकने की जरूरत जितनी आपकी और हमारी है, उतनी ही सरकार की है और उतनी ही सुप्रीम कोर्ट की है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पर अभी देश के लोगों का भरोसा है. इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार के जिस फैसले को उचित ठहराया है, उसे अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए.■

– (राजीव रंजन और नवीन चौहान)

> **जो व्यक्ति वोट दे सकता है, वह इस देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है. चाहे वो पढ़ा-लिखा हो या न हो. इस देश को अब तक बहुत से पढ़े-लिखे लोगों ने बर्बाद किया है. जिसकी वजह से यह देश विकास और नई आर्थिक व्यवस्था के दुष्चक्र में फंस चुका है. संपूर्ण देश की सत्ता का एकाधिकार सौंपेंगे तो आप विश्वास कीजिए कि राजसत्ता के खिलाफ बहुत सी ऐसी ताकतें खड़ी हो जाएंगी, जो संघर्ष का बिगुल बजाने लगेंगी.**

यह निर्णय देश की वास्तविकताओं से परे हैः के सी त्यागी

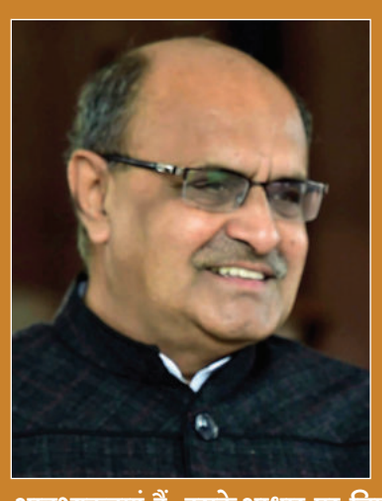

गांव में अगर अशिक्षा है तो यह किसकी गलती है. आजादी के 68 साल हो गए हैं तो यह शासक वर्ग की गलती है. देश का बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसके पास शौचालय नहीं है, आदिवासियों में आप जाइए, दूरस्थ इलाकों में जाइए, समाज केजो पिछड़े वर्ग हैं, वहां किसी केयहां टॉयलेट नहीं है. सभी खुले में शौच जाते हैं. आप फिनलैंड की बात कर रहे हैं, जर्मनी की कर रहे हैं, अमेरिका की कर रहे हैं. आप अपने देश की बात कीजिए. यहां की जो जरूरतें हैं, यहां की जो आवश्यकताएं हैं, उसके आधार पर निर्णय लीजिए. यहां कुछ पढ़े-लिखे लोग मिलेंगे, कुछ बिना पढ़े मिलेंगे, कुछ कम पढ़े-लिखे मिलेंगे. लेकिन कुछ बिना पढ़े लोगों के पास जीवन के बड़े अनुभव मिलेंगे. गांव में जो पंचायती व्यवस्था है, वहां सामूहिक विवेक (कलेक्टिव विजडम) के आधार पर जो निर्णय होते हैं, वे संभ्रांत लोगों से ज्यादा अच्छे और ज्यादा व्यवहारिक होते हैं. पढ़े होने से कढ़ा होना ज्यादा बेहतर है. यदि गांवों में शौचालय नहीं हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है. यह सब जो हो रहा है, यह संभ्रात लोगों का स्वांग है और जो समाज केकमजोर तबकेहैं, जो लोग अभी पिछड़े हैं, जिनके पास घर नहीं हैं, यह उनके साथ एक बुरा मजाक है. यह निर्णय देश की वास्तविकताओं से परे है, उनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है. हमारी पार्टी चाहती है कि चुनाव लड़ने में इस तरह की कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए. हमने संसद में इस मुद्दे को उठाया है और आगे भी उठाते रहेंगे.■

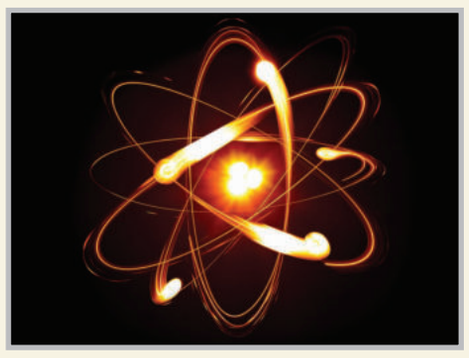

एमओयू से यह बात साबित हो गई है कि जापान भारत को एक परमाणु शक्ति संपन्न देश मानने के लिए तैयार हो गया है. ज़ाहिर है, यह मोदी सरकार के लिए एक कामयाबी है, जिसका अंदाज़ा इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए उस बयान से भी लगाया जा सकता है, जिसमें उन्होंने कहा, एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण विश्व के लिए आपसी विश्वास की यह एक बेहतरीन मिसाल है. मुझे जापान के इस फ़ैसले का महत्व मालूम है. बहरहाल, अमेरिका एवं फ्रांस के बाद जापान द्वारा अपनी नीति में बदलाव का एक और महत्वपूर्ण कारण यह भी कि परमाणु संयंत्र आपूर्ति करने वाली अमेरिकी कंपनी जीई एवं वेस्टिंग हाउस और फ्रांसीसी कंपनी अरेवा में जापान की हिस्सेदारी है.

शिंजो अबे की भारत यात्रा

सफलताएं और आशंकाएं

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

जापान और भारत के बीच सांस्कृतिक एवं व्यापारिक रिश्तों की एक पुरानी परंपरा रही है. जापान आधारभूत संरचना विकास (इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट) के क्षेत्र में हमेशा से भारत का एक महत्वपूर्ण सहयोगी रहा है. लेकिन, भारत द्वारा परमाणु परीक्षण के बाद दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों में खटास पैदा हो गई थी, नतीजतन दोनों देशों के बीच व्यापार के आंकड़े कोई उत्साहजनक तस्वीर पेश नहीं करते थे. पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के रिश्तों में हर दृष्टि से बेहतरी आई है और इसमें लगातार मजबूती आ रही है. जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे का तीन दिवसीय हालिया भारत दौरा दोनों देशों के बीच के रिश्तों को मज़बूती प्रदान करने की अगली कड़ी था. इसके अतिरिक्त दोनों देशों का साझा हित यह है कि जर्मनी और ब्राज़ील के साथ-साथ भारत और जापान भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जी-4 में विस्तार के पक्षधर हैं.

शफीक आलम

जापानी प्रधानमंत्री शिंजो अबे का यह भारत का तीसरा आधिकारिक दौरा था. इस दौरे के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों को अंतिम रूप दिया गया और कई मुद्दों पर आगे बढ़ने की बात कही गई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन परियोजना और आर्थिक महत्व के कई समझौतों के साथ-साथ रक्षा एवं ऊर्जा क्षेत्र में भी सहमति बनी. बहरहाल, अब सवाल यह उठता है कि जापानी प्रधानमंत्री के इस दौरे से भारत को क्या हासिल हुआ? क्या इस दौरे का चीन के लिए भी कोई मायने है? सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या भारत को बुलेट ट्रेन की आवश्यकता है? हालांकि, सिविल न्यूक्लियर डील पर अभी अंतिम समझौता नहीं हुआ है, लेकिन दोनों देशों के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसके मुताबिक़ जापान भारत के साथ असैन्य परमाणु सहयोग में परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) की शर्त नहीं रखेगा. लेकिन परमाणु डील पर पुराना सवाल अब भी बरक़रार है कि क्या भारत परमाणु ऊर्जा के बिना अपनी ऊर्जा ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकेगा? आज जब दुनिया के विकसित देश अपनी परमाणु ऊर्जा की खपत में कटौती की नीति पर काम कर रहे हैं, तो भारत इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है? और, क्या इस दौरे से दोनों देशों के बीच व्यापार में इजाफ़ा होगा?

बुलेट ट्रेन

सबसे पहले बुलेट ट्रेन एचएसआर (हाई स्पीड रेल) की बात करते हैं. स्मार्ट सिटी और मेक इन इंडिया की तरह बुलेट ट्रेन भी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्लैगशिप योजना है, जिसका ज़िक्र उन्होंने अपनी चुनावी सभाओं में भी किया था. यूं तो बुलेट ट्रेन परियोजना में जापान के साथ-साथ चीन भी दिलचस्पी ले रहा था, लेकिन जापान की शर्तें भारत को पसंद आईं और दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने इस परियोजना पर अपनी सहमति का ऐलान कर दिया. जापान इस परियोजना के लिए भारत को 50 वर्षों की अवधि के लिए कुल 98 हज़ार करोड़ रुपये का क़र्ज़ देगा. इस क़र्ज़ पर भारत को 0.1 प्रतिशत की दर से ब्याज देना होगा. जापान की तरफ़ से एक छूट यह दी गई है कि भारत को पहले 15 वर्षों तक कोई ब्याज नहीं देना होगा. इस समझौते के तहत पहली बुलेट ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलेगी, जो दोनों शहरों के बीच की 505 किलोमीटर की दूरी दो घंटे में तय करेगी. एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह ट्रेन 350 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से चल सकती है.

इस परियोजना के आलोचकों की पहली आपत्ति तो यह है कि इसका किराया हवाई जहाज़ से भी अधिक होगा. एक अनुमान के मुताबिक, अहमदाबाद से मुंबई का किराया तक़रीबन 2,800 रुपये होगा. जबकि दोनों शहरों के बीच हवाई जहाज़ का किराया 1,720 रुपये है, वहीं राजधानी स्तर की ट्रेनों की प्रथम श्रेणी का किराया 2,200 रुपये है. लेकिन, यह आपत्ति उचित नहीं लगती, क्योंकि हवाई जहाज़ का टिकट यात्रा तिथि की निकटता के लिहाज़ से बढ़ता है. 1,720 रुपये हवाई जहाज़ का न्यूनतम किराया है. कभी-कभी यह किराया कई गुना बढ़ जाता है. ऐसे में यात्रियों को 2,800 रुपये में बुलेट ट्रेन से यात्रा करने की सुविधा मिल जाती है और उनका कुछ समय भी बच जाता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है. हां, इस संबंध में दूसरा सवाल अहम है कि 98 हज़ार करोड़ रुपये का क़र्ज़ कैसे चुकाया जाएगा? क्या इस ट्रेन के चलने के बाद इससे इतनी आमदनी हो पाएगी कि उक्त क़र्ज़ निर्धारित समय पर अदा किया जा सके? कहीं इस क़र्ज़ की वजह से भारतीय रेलवे पर अतिरिक्त दबाव तो नहीं पड़ेगा, जिससे रेलवे के निजीकरण का एक मज़बूत बहाना मिल जाए?

ऐसा नहीं है कि सरकार की तरफ़ से इन सवालों का जवाब नहीं दिया गया. सरकार की तरफ़ से कहा गया है कि यह कर्ज़ भारतीय रेलवे के वर्तमान वित्त से अलग रहेगा. जापान की तरफ़ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक, इस कर्ज़ पर ब्याज दरों और सात वर्षों की निर्माण लागत का ख्याल रखा गया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि इस परियोजना से संबंधित रीयल एस्टेट से भी अच्छी-खासी आमदनी की उम्मीद है. जैसे-जैसे बुलेट ट्रेन का संचालन ज़ोर पकड़ेगा, यह स्वायत्तता हासिल कर लेगी. लेकिन, उक्त सारी बातें संभावनाओं पर आधारित हैं. अगर बुलेट ट्रेन के संचालन को सफलता नहीं मिलती है और इसके सफ़ेद हाथी बनने की भविष्यवाणी सच साबित होती है, तो क्या होगा? एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि बुलेट ट्रेन आख़िर किसके लिए है? क्या यह प्रोजेक्ट देश के सभी नागरिकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है या देश के 80 प्रतिशत ग़रीब-मज़दूर इसमें शामिल नहीं हैं? वजह, इसका किराया इतना ज़्यादा है, जो कि इस 80 प्रतिशत आबादी की पहुंच से बाहर है. यह दलील कि बुलेट ट्रेन के पूरी तरह संचालित हो जाने से रेलवे पर यात्रियों का दबाव कम हो जाएगा, आसानी से गले नहीं उतरती, क्योंकि रेलवे की असल भीड़ की पहुंच से यह ट्रेन बाहर रहेगी.

असैन्य परमाणु सहयोग

पांच वर्षों की बातचीत के बाद भारत और जापान ने असैन्य परमाणु सहयोग पर अपनी सहमति की मुहर लगा दी. अमेरिका और फ्रांस के बाद जापान के साथ यह समझौता इस लिहाज़ से बहुत अहम है, क्योंकि 1998 में परमाणु परीक्षण के बाद जापान ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया था. उसके बाद से जब भी असैन्य परमाणु क्षेत्र में सहयोग की बात होती थी, तो जापान परमाणु अप्रसार संधि पर भारत की रजामंदी की मांग करता था. लेकिन, अब ताजा एमओयू से यह बात साबित हो गई है कि जापान भारत को एक परमाणु शक्ति संपन्न देश मानने के लिए तैयार हो गया है. ज़ाहिर है, यह मोदी सरकार के लिए एक कामयाबी है, जिसका अंदाज़ा इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए उस बयान से भी लगाया जा सकता है, जिसमें उन्होंने कहा, एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण विश्व के लिए आपसी विश्वास की यह एक बेहतरीन मिसाल है. मुझे जापान के इस फ़ैसले का महत्व मालूम है. बहरहाल, अमेरिका एवं फ्रांस के बाद जापान द्वारा अपनी नीति में बदलाव का एक और महत्वपूर्ण कारण यह भी कि परमाणु संयंत्र आपूर्ति करने वाली अमेरिकी कंपनी जीई एवं वेस्टिंग हाउस और फ्रांसीसी कंपनी अरेवा में जापान की हिस्सेदारी है. भारत में परमाणु संयंत्र स्थापित करने में इन कंपनियों को जापान के सहयोग की आवश्यकता होगी. लेकिन, अभी इस समझौते को अंतिम रूप देना बाक़ी है. जैसा कि विदेश सचिव एस जयशंकर ने कहा कि इस मुद्दे पर बातचीत समाप्त हो गई है और तकनीकी एवं क़ानूनी पहलुओं पर ग़ौर करने के बाद इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा.

परमाणु ऊर्जा उत्पादक कंपनियों द्वारा सुरक्षा के लाख दावों के बावजूद इसके ख़तरे से किसी को इंकार नामुमकिन है. परमाणु हादसा कितना भयानक हो सकता है, इसकी मिसालें भी मौजूद हैं. 1986 में उक्रेन की चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना की भयावह तस्वीर आज भी लोगों के ज़ेहन में ताज़ा है. इसी तरह 1979 की थ्री-माईल आइलैंड परमाणु दुर्घटना ने परमाणु ऊर्जा के इस्तेमाल पर सवालिया निशान लगा दिया था. जापान की फुकुशीमा परमाणु दुर्घटना तो अभी हाल की है. अमेरिका की थ्री-माईल आइलैंड दुर्घटना के बाद परमाणु ऊर्जा रिएक्टर चलाने वाले अनेक देशों ने परमाणु ऊर्जा पर अपनी निर्भरता कम करने के प्रयास शुरू किए. ऐसे देशों में स्वीडन, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया एवं स्पेन आदि शामिल हैं. जापान की फुकुशीमा परमाणु दुर्घटना के बाद जर्मनी ने अपने कई रिएक्टर बंद कर दिए हैं. फ्रांस परमाणु ऊर्जा पर निर्भरता के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश है.

वहां के राष्ट्रपति फ्रांसुवा ओलांद ने तो परमाणु ऊर्जा पर निर्भरता में कटौती को अपना चुनावी मुद्दा बनाया था. हालांकि, अमेरिका परमाणु ऊर्जा उत्पादन में कटौती की बात आधिकारिक तौर पर नहीं करता, लेकिन वहां कुल विद्युत उत्पादन का केवल 19 प्रतिशत हिस्सा परमाणु ऊर्जा से हासिल होता है. अमेरिका में 1979 की थ्री-माईल आइलैंड परमाणु दुर्घटना के बाद कोई नया रिएक्टर कमीशन नहीं हुआ है. इन तथ्यों से यह नतीजा निकालना मुश्किल नहीं है कि एक तरफ़ दुनिया के विकसित देश परमाणु ऊर्जा पर अपनी निर्भरता लगातार कम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ़ भारत जैसे विकासशील देश में परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़ाने की जैसे होड़ लगी है.

रक्षा सहयोग और चीन की चिंता

भारत-जापान के बीच हुए आर्थिक और रक्षा संबंधी समझौतों से चीन चिंतित है. दरअसल, चीन की बढ़ती हुई आर्थिक और सैन्य क्षमता की वजह से जापान सहित दुनिया के दूसरे विकसित देश प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीन की शक्ति का संतुलन बनाने के लिए प्रयासरत हैं. अमेरिका और जापान कोशिश कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत भी इसमें शामिल हो. भारत पहले भी अमेरिका के साथ मालाबार (बंगाल की खाड़ी) में साझा युद्धाभ्यास कर चुका है, जिस पर चीन ने नाराज़गी भी ज़ाहिर की थी. अब भारत और जापान के बीच सैन्य तकनीक एवं जानकारी साझा करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिससे जापान रक्षा साज़-ओ-सामान भारत को बेच सकेगा. इस समझौते के तहत भारत के लिए यूएस-2 अम्फिबियन विमान खरीद के रास्ते भी खुल जाएंगे. भारत ने यह घोषणा भी की है कि जापान अब अमेरिका के साथ स्थायी रूप से मालाबार नवसेना युद्धाभ्यास का हिस्सा रहेगा. इसके साथ-साथ दोनों देशों के बीच परमाणु करार को भी चीन शक की निगाह से देखता है.

चीन की सबसे बड़ी आपत्ति भारत और जापान के विज़न 2025 पर है, जिसके तहत हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में शांति की बात कही गई है. चीन इसे भारत का हस्तक्षेप क़रार दे रहा है. चीन का मानना है कि भारत या जापान या अमेरिका का दक्षिणी चीन सागर से कोई लेना-देना नहीं है. उसका कहना है कि जापान पूर्वी चीन सागर में पड़ता है. अमेरिका और जापान इस क्षेत्र में उसके विरोधी देशों के साथ अपने संबंध बढ़ाने में लगे हैं तथा अब भारत भी उसमें शामिल हो गया है. लेकिन, भारत का मानना है कि यह चैनल उसका एक अहम व्यापारिक चैनल है. भारत वियतनाम, कंबोडिया एवं मलेशिया जैसे देशों को निर्यात करता है, जो इन्हीं समुद्री इलाक़ों से होकर जाता है. जापान के साथ चीन भी भारत की बुलेट ट्रेन परियोजना में दिलचस्पी ले रहा था. इंडोनेशिया में बुलेट ट्रेन की प्रतिस्पर्धा में चीन ने जापान को मात दे दी थी. जापान किसी भी हालत में भारत की बुलेट ट्रेन परियोजना गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए वह आसान शर्तों पर भारत को इस परियोजना के लिए क़र्ज़ देने पर राज़ी हो गया. हालांकि, चीन के लिए अब भी भारत की बुलेट ट्रेन परियोजना में अपनी दावेदारी पेश करने का मौक़ा है, लेकिन जापान के साथ नज़दीकियों की वजह से चीन का सिल्क इकोनॉमिक बेल्ट का सपना खटाई में पड़ सकता है.

इसके अतिरिक्त दोनों देशों के बीच दोहरी कर प्रणाली प्रोटोकॉल में संशोधन, रेलवे के संचालन-सुरक्षा, चिकित्सा, सतत विकास और स्वच्छ भारत अभियान आदि क्षेत्रों में सहयोग के समझौतों पर भी हस्ताक्षर हुए. कुल मिलाकर देखा जाए, तो यह जापान के लिए इस लिहाज से महत्वपूर्ण था, क्योंकि वह एशिया में चीन के प्रभाव से चिंतित था और भारत को किसी भी क़ीमत पर चीन के साथ जाने देने के हक़ में नहीं था. भारत भी चीन के साथ अपने संबंधों को लेकर कभी आश्वस्त नहीं रहा है. इसलिए जापान का साथ उसके हित में है. लेकिन, इस दौरे पर हुए समझौतों पर सवाल तो खड़े होते ही हैं, खासकर परमाणु सहयोग और बुलेट ट्रेन जैसे मसलों पर.■

यूं तो बुलेट ट्रेन परियोजना में जापान के साथ-साथ चीन भी दिलचस्पी ले रहा था, लेकिन जापान की शर्तें भारत को पसंद आईं और दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने इस परियोजना पर अपनी सहमति का ऐलान कर दिया. जापान इस परियोजना के लिए भारत को 50 वर्षों की अवधि के लिए कुल 98 हज़ार करोड़ रुपये का क़र्ज़ देगा. इस क़र्ज़ पर भारत को 0.1 प्रतिशत की दर से ब्याज देना होगा. जापान की तरफ़ से एक छूट यह दी गई है कि भारत को पहले 15 वर्षों तक कोई ब्याज नहीं देना होगा. इस समझौते के तहत पहली बुलेट ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलेगी, जो दोनों शहरों के बीच की 505 किलोमीटर की दूरी दो घंटे में तय करेगी.

feedback@chauthiduniya.com

शिवराज सिंह चौहान की एक पसंदीदा कहावत है, पांव में चक्कर, मुंह में शक्कर, माथे पर बर्फ और सीने में आग. इसे वह अक्सर दोहराते हैं और यही उनकी सफलता का मंत्र भी है. तभी तो हार के तुरंत बाद वह झाबुआ का रुख करते हैं और फिर से जनता की नब्ज साधने, ग़लती सुधारने की कोशिश में अपना पूरा प्रशासनिक अमला लगा देते हैं. भाजपा की हार और कांग्रेस की जीत कितनी स्थायी है, यह तो सतना ज़िले के मैहर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे बताएंगे. फिलहाल भाजपा में सब कुछ शिवराज सिंह के नियंत्रण में है और उन्हें केंद्र में भेजे जाने की अटकलें भी बंद हो चुकी हैं. कांग्रेस को भी एक बार फिर यह सीख मिली है कि अगर उसके नेता एक–दूसरे के ख़िलाफ़ गोल करने के बजाय भाजपा के ख़िलाफ़ लड़ें, तो मध्य प्रदेश में उसकी वापसी संभव है.

यूपी में नई ग्राम सरकार

अरुण तिवारी

भारतीय लोकतंत्र में विधायिका की सबसे निचली लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कड़ी कहे जाने वाले पंचायत चुनाव संपन्न हो गए हैं. हमेशा यह कहा जाता है कि पंचायत चुनाव और हिंसा पर्यायवाची शब्द हैं. बीते चुनाव भी इस बात को गलत साबित कर पाने में नाकामयाब रहे. प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद भी हत्या जैसे जघन्य अपराधों ने चुनावों का साथ नहीं छोड़ा. वोट लेने के लिए प्रत्यक्षर्शियों ने वाटरों के बीच गांजे, शराब और गोश्त की व्यवस्था करवाने में कोई कोर–कसर बाकी नहीं रखी. हालांकि कई बेहतर परिणाम भी आए, जिनमें नई उम्र के लोगों ने गांवों की तरफ रुख किया है और गांव वालों ने उन्हें जिताया भी है. यह एक अच्छा संकेत है. चुनाव नतीजों के बाद गांवों की जनता को यह उम्मीद है कि उनके ग्राम प्रधान उनकी बेहतरी के लिए सरकारी योजनाओं को लेकर आएंगे, न कि सिर्फ सरकारी खजाने को डकारते रहने का काम करेंगे.

महिलाओं की जीत के मायने

प्रधानपति के प्रचार का नमूना

बेहद खुशी की बात है कि प्रधानी चुनावों में 44 प्रतिशत महिला उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है, लेकिन दीवारों पर, पेड़ों पर और चौक–चौराहों पर चिपके पोस्टरों पर नजर जाते ही इस खुशी पर कई सवाल खड़े होने लगते हैं. पोस्टरों में महिला उम्मीदवारों की तस्वीरों की जगह उनके पति, ससुर यहां तक कि उनके बेटों की फोटो लगाई गई थी. अगर कुछ पोस्टरों में महिलाओं की तस्वीरें लगी भी थीं, तो वो घर के पुरुष मुखिया की फोटो के बाद ही लगी थी. यहां तक कि गांव में अपनी सरकार बनाने के लिए दावेदारी ठोंकने वाली महिलाओं के फोन नंबर तक पोस्टरों से गायब थे. उनमें दिए गए फोन नंबर घर के पुरुष मुखिया के थे. ऐसा सभी जगह नहीं हुआ, लेकिन कमोबेश यह स्थिति प्रदेश में कई जगहों पर थी. यही हाल तब भी दिखा, जब महिलाएं जीत कर आईं. जीतीं तो महिलाएं लेकिन माला पतियों के गले में डाली गई. बधाई भी उन्हें ही दी गई. महिलाएं उनके बगल में कठपुतली बनकर खड़ी दिखाई दे रही थीं. त्रासदी यह है कि अपने इलाके में महिला और अनुसूचित जातियों के लिए आवाज उठाने वाली शीलू निषाद चुनाव हार गईं. शीलू निषाद से दुष्कर्म के आरोप में नरेनी के पूर्व विधायक और बसपा नेता पुरुषोत्तम द्विवेदी उम्र कैद की सजा काट रहे हैं.

महिलाओं के रबर स्टांप बनने के पीछे दो वजहें हैं. पहली सामाजिक छवि और धारणा दूसरी सरकार की पल्ला झाड़ने की नीति. गांवों में घुसते ही अगर आप प्रधान का पता पूछेंगे तो किसी पुरुष का नाम ही सामने आता है. भले ही प्रधान महिला हो. सदियों से बनी इन मान्यताओं को तोड़ने के लिए ही पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गईं. मगर हर सरकारी योजना और घोषणा की तरह यहां पर भी नियम लाने के बाद सरकार ने अपना काम पूरा हुआ समझकर पल्ला झाड़ लिया. ज्यादातर सीटों पर महिलाओं का सरकारी मुखौटा लगाकर काम पुरुष ही कर रहे हैं. पुराने अनुभव सवाल खड़े करते हैं और संदेह पैदा करते हैं कि इन 44 प्रतिशत महिलाओं में कितनी महिलाएं अपने गांव की सरकार वास्तविकता में चलाएंगी या हमेशा की तरह इनकी आड़ में सत्ता की कमान प्रधानपतियों के हाथ में ही रहेगी.

युवाओं की जीत का असर

इस बार की चुनावी जीत में पूरे प्रदेश में 19 पीएचडी धारक युवा प्रधान बनकर आए हैं. कुल जीते युवा प्रधानों का प्रतिशत 35 रहा. देश में प्रधानी को लेकर चली आ रही पुरानी परिपाटी को तोड़ने की वास्तविक चुनौती नए लोगों के सामने ही है. गुजरात के पंसारी गांव के हिमांशु पटेल हों या फिर राजस्थान के सोडा गांव की छवि राजावत, यूपी के युवा ग्राम प्रधानों को भी अपने गांवों को भी बेहतर दिशा में ले जाने के लिए इनसे सीख लेनी होगी. शाहजहांपुर के गांव रोशर से चुनाव जीतने वाले 21 वर्षीय दीपक मिश्र का कहना है कि प्रधान गांव में आने वाली सरकारी योजनाओं को लागू करवाने की मुख्य कड़ी है, अगर वह अपना काम ईमानदारी से करें तो तस्वीवर बदल सकती है. उन्होंने अपने चुनाव लड़ने की प्रेरणा एक टीवी कार्यक्रम को दी. उस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के एक गांव का जिक्र था, जिसमें ग्राम प्रधान ने गांव के भीतर कूड़ा खोजने वाले को पुरस्कृत करने का प्रावधान किया था. वहीं अमेठी जिले की सरवन ग्राम सभा से जीतने वाली 23 वर्षीया मनीषा यादव अपने गांव को आदर्श गांव की तरह विकसित करने का विचार रखती हैं. उन्होंने अपने गांव में सरकारी योजनाओं को ठीक तरह से लागू करवाने के लिए कटिबद्धता जताई.

बेहद खुशी की बात है कि प्रधानी चुनावों में 44 प्रतिशत महिला उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है लेकिन दीवारों पर, पेड़ों पर और चौक-चौराहों पर चिपके पोस्टरों पर नजर जाते ही इस खुशी पर कई सवाल खड़े होने लगते हैं. पोस्टरों में महिला उम्मीदवारों की तस्वीरों की जगह उनके पति, ससुर यहां तक कि उनके बेटों की फोटो लगाई गई थी. कुछ पोस्टरों में महिलाओं की तस्वीरें लगी भी थीं, तो वो घर के पुरुष मुखिया की फोटो के बाद ही लगी थी.

दीपक मिश्र

मनीषा यादव

धनबल, नशा और हिंसा

प्रधानी चुनाव में प्रचार–प्रसार के लिए सरकारी की तरफ से तय राशि 75 हजार रुपये है, जबकि जिसने असल में प्रचार देखा होगा, वह आसानी से समझ सकता है कि इसमें तय राशि और आचार संहिता का माखौल बनाया जाना जाता है. नामांकन के समय में ही गाड़ियों की लंबी कतारें देखी जा सकती हैं. शराब के ठेके चुनाव के दौरान बंद तो थे, लेकिन शराब की बिक्री बदस्तूर जारी रही. ठेका मालिक बंद दुकानों के आगे–पीछे लगातार मंडराते रहे. बांदा जिले के एक गांव के देसी शराब ठेका मालिक ने बताया कि हर सरकारी ताले की चाबी होती है. ठेका बंद हुआ तो क्यों हुआ, दारू तो फिर भी बिक सकती है. जहां खुले ठेके में पच्चीस से तीस हजार की दारू रोजाना बिकती थी, वहीं चुनाव के दौरान आचारसंहिता के दौरान बंद ठेके से एक दिन में पचास से साठ हजार की दारू बेची. यूपी के सुल्तानपुर के एक गांव में चुनाव प्रचार करके वापस लौटे एक व्यक्ति ने बताया कि उसने इस बार चुनाव में कुछ नए प्रयोग किए. नए प्रयोग क्यों थे, यह सुनकर हैरानी हुई. प्रचार के दौरान के युवा मतदाताओं के बीच गांजे की पुड़िया और देशी दारू की जगह बियर बंटवाई गई. हालांकि उसने यह भी बताया कि ऐसा करना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि विपक्षी उम्मीदवारों ने साड़ियां, कंबल और जमकर देसी दारू बंटवा रखी थी.

भले ही चुनाव आयोग यह बोल रहा हो कि चुनाव शांतिपूर्ण रहे, लेकिन चुनावी हिंसा में लगभग एक दर्जन लोगों की जान चली गई. कई जगहों पर हंगामा हुआ, पत्थरबाजी हुई और खासतौर पर पश्चिमी यूपी के कई जिलों में जमकर गोलियां चलीं. पूर्वांचल कई मौतों का गवाह बना. बलिया में एक प्रत्याशी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, वहीं आजमगढ़ जिले में तीन मौतें हुईं. मेरठ में भी एक मौत चुनावी रंजिश का ही नतीजा है. दरअसल, प्रधानी चुनावों में वोटों की संख्या सांसद और विधायक के चुनाव से बहुत कम होती है. मतदाताओं ने कहां वोट दिया है, यह पता लगाने में प्रत्याशियों को ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता, जिसकी वजह से रंजिश बढ़ती जाती है.

योजनाएं और उनके क्रियान्वयन में घपले

अक्सर बड़े–बड़े सरकारी घोटालों की नींव किसी गांव में हो रहे छोटे–छोटे गड़बड़झाला और घपलों पर रखी जाती है. मनरेगा के महाघोटाले के पीछे भी इस योजना के हर चरण में छोटे–छोटे घोटाले शामिल थे. इंदिरा आवास योजना, पेंशन योजनाएं, खड़ंजे की योजनाएं, हैंडपंप की योजनाएं जैसी कुछ ऐसी प्रमुख योजनाएं हैं, जिनमें घोटाले की आशंका बनी रहती है. एक पंचायत का बजट चालीस से पचास लाख रुपये तक हो गया है, जो प्रधान के पास पहुंचता है. अब भावी प्रधानों के कंधों पर यह जिम्मेदारी है कि वे इनमें होने वाली गड़बडियों को रोकने के लिए प्रयास ही न करें, बल्कि आवाज भी उठाएं, जिससे भविष्य में उन्हें रोका जा सके. सुल्तानपुर जिले के पतिपुर गांव से जीते जीतेंद्र प्रताप इस संबंध में कहते हैं कि योजनाओं को लागू करवाने में प्रधानों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. आपसी राजनीति में कई बार गांव के ही दबंग इन कामों में रोड़े अटकाने का काम करते हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

झाबुआ की मात और दस वर्ष का जश्न

जावेद अनीस

मध्य प्रदेश के इतिहास में दिग्विजय सिंह के बाद शिवराज सिंह चौहान ऐसे दूसरे शख्स बन गए हैं, जिन्होंने बतौर मुख्यमंत्री एक दशक का समय पूरा किया. बीते 29 नवंबर को उन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व काल के 10 वर्ष पूरे कर लिए. इस दौरान हुए ज़्यादातर चुनावों एवं उपचुनावों में भाजपा ने अपनी पकड़ ढीली नहीं होने दी और उसका पलड़ा कांग्रेस के मुक़ाबले भारी रहा. लेकिन, रतलाम–झाबुआ लोकसभा उपचुनाव की हार भाजपा की सबसे बड़ी हार बन चुकी है. इसने न सिर्फ़ दस वर्ष पूरे होने का जश्न फीका कर दिया, बल्कि यह सवाल भी उछाल दिया कि आख़िर इस हार का ज़िम्मेदार कौन है. कोई इसे शिवराज की हार बता रहा है, तो कोई इसे मोदी की चमक फीकी पड़ने और दिल्ली–बिहार के सिलसिले की कड़ी के रूप में देख रहा है. बिहार की तर्ज पर अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के नक्शेक़दम पर चलते हुए शिवराज सिंह ने इस सीट को प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था. उनके नेतृत्व में पार्टी की राज्य इकाई, पूरा मंत्रिमंडल एवं प्रशासनिक अमला चुनाव में लगा रहा, लेकिन इन सबसे पार पाते हुए पुलिस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए आदिवासी नेता कांतिलाल भूरिया अपनी सीट एक बार फिर वापस पाने में कामयाब रहे और वह भी क़रीब 90 हज़ार वोटों के अंतर से. इस जीत ने पिछले बारह वर्षों में कांग्रेस को पहली बार यह एहसास कराया है कि पार्टी प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर मुक़ाबले में आ सकती है, बशर्ते वह ऐसा करना चाहे.

रतलाम–झाबुआ लोकसभा सीट कांग्रेस का गढ़ रही है, जिसे 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के दिलीप सिंह भूरिया ने जीता था. उनके आकस्मिक निधन के बाद हुए उपचुनाव में भाजपा ने यह सीट बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत झोंक दी और कांग्रेस ने इसे अपनी वापसी का मौक़ा माना. यह उपचुनाव भाजपा ने अमित शाह स्टाइल में लड़ा. सबसे पहले तो चुनाव की बागडोर पूरी तरह शिवराज सिंह ने अपने हाथों में केंद्रित रखी. उन्होंने अपने 16 दिनों के चुनावी अभियान के दौरान 52 जनसभाओं को संबोधित किया. क़रीब दो हज़ार करोड़ रुपये की घोषणाएं की गईं. इस दौरान संघ और पार्टी का कुनबा तो साथ था ही, लेकिन सबके केंद्र में शिवराज ही नज़र आ रहे थे. पार्टी प्रत्याशी निर्मला भूरिया तो नेपथ्य में थीं. दूसरी तरफ़ कांग्रेस के प्रचार अभियान में उसके प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया केंद्र में रहे और प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव उनका सहयोग करते नज़र आए. इस चुनाव में कोई एक मुद्दा नहीं था. पेटलावद हादसा, व्यापमं घोटाला, किसानों द्वारा आत्महत्या और महंगाई जैसे मुद्दे भाजपा के ख़िलाफ़ गए. पेटलावद हादसा एक स्थानीय मुद्दा था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए, दोषियों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई और उसके तार भी भाजपा नेताओं से जुड़ते दिखाई दिए, जिसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा. पंचायतीराज के जनप्रतिनिधि भी अधिकार देने की मांग न मानने और भोपाल में प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज को लेकर नाराज़ चल रहे थे. त्रिस्तरीय पंचायतीराज संगठन ने भाजपा को हराने का निर्णय लिया था. अध्यक्ष अभय मिश्रा का दावा है कि उनके संगठन की वजह से भाजपा को शिकस्त खानी पड़ी.

कुछ भी हो, इस हार ने मोदी लहर और शिवराज सिंह के जादू पर सवाल खड़ा कर दिया है. रतलाम–झाबुआ लोकसभा सीट पर भाजपा की हार शिवराज सरकार के लिए एक झटका है. इससे निश्चित रूप से लगातार पिट रही कांग्रेस का हौसला बढ़ा है.

एक और प्रमुख मुद्दा बेरोज़गारी है. झाबुआ से बड़ी संख्या में लोग रोज़गार की तलाश में गुजरात पलायन को मजबूर हैं. केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद से मनरेगा में रुकावट आई है, जिसके चलते बेरोज़गारी और पलायन में वृद्धि हुई है. नेताओं के दंभ भरे बयानों ने भी असर दिखाया. चुनाव के दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने मतदाताओं को खुलेआम धमकी दी थी कि भाजपा को छोड़कर अगर कोई अन्य यह चुनाव जीत गया, तो झाबुआ का विकास रुक जाएगा. ज़ाहिर है, जनता को यह धमकी रास न आई होगी. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान ने उपचुनाव में हार के लिए संगठन को ज़िम्मेदार बताते हुए समीक्षा की मांग उठाई है. उन्होंने शिवराज सिंह को क्लीन चिट देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की लोकप्रियता में कमी नहीं आई है. रतलाम–झाबुआ में भाजपा को जो वोट मिले, वे शिवराज के विकास की बदौलत मिले. भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इसे कांतिलाल भूरिया की निजी जीत बता रहे हैं, वहीं कांग्रेस इसे मुख्यमंत्री की हार और भाजपा के पतन की शुरुआत बता रही है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव का कहना है कि रतलाम–झाबुआ लोकसभा सीट पर कांग्रेस की जीत किसानों की जीत है. लोगों ने केंद्र सरकार के ख़िलाफ़ मतदान किया.

कुछ भी हो, इस हार ने मोदी लहर और शिवराज सिंह के जादू पर सवाल खड़ा कर दिया है. रतलाम–झाबुआ लोकसभा सीट पर भाजपा की हार शिवराज सरकार के लिए एक झटका है. इससे निश्चित रूप से लगातार पिट रही कांग्रेस का हौसला बढ़ा है. वह इसे बिहार और गुजरात के स्थानीय चुनावों के नतीजों से जोड़कर देख रही है. लेकिन, इस जीत से बम–बम हुई कांग्रेस भूल रही है कि रतलाम–झाबुआ लोकसभा सीट उसका पुराना गढ़ रही है. 2014 के लोकसभा चुनाव में जिन दिलीप सिंह भूरिया ने उससे यह सीट छीनी थी, वह पहले उससे ही जुड़े थे. उधर 23 हज़ार वोट नोटा के रूप में पड़े हैं, जो कांग्रेस के लिए जीत की ख़ुशी के साथ–साथ एक संदेश भी है. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव बादल सरोज का कहना है कि रतलाम–झाबुआ के उपचुनाव में जनता ने कांग्रेस को नहीं जिताया, बल्कि भाजपा को हराया है. यह मोदी सरकार द्वारा वादों की अनदेखी करने एवं जनता पर बोझ बढ़ाने वाली नीतियों के विरुद्ध हुआ मतदान है और प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता एवं दमनकारी रुख के ख़िलाफ़ जनादेश है. शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में भाजपा का पर्याय बन चुके हैं. यही उनकी ताकत है और कमज़ोरी भी. ताकत इसलिए, क्योंकि फिलहाल राज्य में उनका कोई विकल्प नहीं है. जो विकल्प बन सकते थे, उन्हें प्रदेश से बाहर भेज दिया गया है. कमज़ोरी इस लिहाज से कि भाजपा का मौजूदा शीर्ष नेतृत्व अपने अलावा किसी अन्य को मजबूत शक्ति केंद्र के रूप में देखना पसंद नहीं करता. राजनीतिक पंडित अनुमान लगा रहे थे कि अगर बिहार चुनाव में भाजपा जीतती है, तो शिवराज सिंह की विदाई हो सकती है. शायद उन्हें केंद्र में मंत्री बना दिया जाता, लेकिन बिहार में हार के बाद मोदी–शाह की जोड़ी खुद बैकफुट पर है.

शिवराज सिंह चौहान की एक पसंदीदा कहावत है, पांव में चक्कर, मुंह में शक्कर, माथे पर बर्फ और सीने में आग. इसे वह अक्सर दोहराते हैं और यही उनकी सफलता का मंत्र भी है. तभी तो हार के तुरंत बाद वह झाबुआ का रुख करते हैं और फिर से जनता की नब्ज साधने, ग़लती सुधारने की कोशिश में अपना पूरा प्रशासनिक अमला लगा देते हैं. भाजपा की हार और कांग्रेस की जीत कितनी स्थायी है, यह तो सतना ज़िले के मैहर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे बताएंगे. फिलहाल भाजपा में सब कुछ शिवराज सिंह के नियंत्रण में है और उन्हें केंद्र में भेजे जाने की अटकलें भी बंद हो चुकी हैं. कांग्रेस को भी एक बार फिर यह सीख मिली है कि अगर उसके नेता एक–दूसरे के ख़िलाफ़ गोल करने के बजाय भाजपा के ख़िलाफ़ लड़ें, तो मध्य प्रदेश में उसकी वापसी संभव है. देखना यह है कि कांग्रेस इस सबक को कब तक याद रख पाती है. फिलहाल इस जीत ने उसके सूबेदार अरुण यादव की कुर्सी पर ख़तरे की अटकलों पर विराम लगा दिया है और उनकी टीम के हौसले बुलंद हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

पेरिस जलवायु समझौता

न किसी की जीत, न किसी की हार

पेरिस जलवायु सम्मेलन में सहमति बनने के बावजूद भारत की कई चिंताओं को मसौदे में जगह नहीं दी गई. भारत का कहना था कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित कर देने के लक्ष्य के लिए विकसित देशों को अपने उत्सर्जनों में भारी कटौती करनी होगी और विकासशील देशों को दी जाने वाली आर्थिक मदद बढ़ानी होगी. पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (आईएनडीसी) एक नई एवं बड़ी खोज है और यह महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाली साबित हुई है.

नवीन चौहान

फ्रांस की राजधानी पेरिस में 30 नवंबर से 12 दिसंबर, 2015 के बीच आयोजित जलवायु सम्मेलन (सीओपी-21) सफल साबित हुआ. सम्मेलन में शामिल हुए 196 प्रतिनिधिमंडलों (195 देश एवं यूरोपीय संघ) ने दुनिया को ग्लोबल वॉर्मिंग के ख़तरे से बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए. दुनिया भर के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करने वाले कम से कम 55 देशों (जो कुल 55 प्रतिशत ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करते हैं) के अनुमोदन करते ही यह समझौता लागू हो जाएगा. इसके लिए सभी सदस्य देशों को 22 अप्रैल, 2016 से 21 अप्रैल, 2017 के बीच इस नए समझौते पर हस्ताक्षर करने होंगे. साथ ही उन्हें अपने देश की क़ानूनी या वैधानिक प्रक्रिया के तहत समझौते के प्रावधान लागू करने होंगे. इस समझौते में पर्यावरणीय न्याय (क्लाइमेट जस्टिस) की बात कही गई है और पर्यावरण सुरक्षा की ज़िम्मेदारी मुख्य रूप से बड़े, ताकतवर एवं धनी देशों पर डाली गई है. इस समझौते को ऐतिहासिक टर्निंग प्वाइंट माना जा रहा है. समझौते के अनुसार, वैश्विक तापमान की सीमा दो डिग्री सेल्सियस से काफी कम रखने और इस समस्या से निपटने में विकासशील देशों की मदद के लिए वर्ष 2020 से सौ अरब डॉलर प्रति वर्ष की प्रतिबद्धता का प्रस्ताव शामिल है.

समझौते के अंतर्गत वर्ष 2020 के बाद होने वाले ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का कोटा निर्धारित किया जाएगा और जलवायु परिवर्तन को रोकने के उपाय किए जाएंगे. समझौते में विश्व में कार्बन डाई ऑक्साइड गैस (सीओ-2) का उत्सर्जन स्तर कम करने की कोई बात नहीं कही गई है और न जीवाश्म ईंधन के परित्याग के कोई संकेत दिए गए हैं. हालांकि, सभी देशों को जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी का अपना राष्ट्रीय लक्ष्य अनिवार्य रूप से निर्धारित करने की बाध्यता है, लेकिन उसे समयबद्ध तरीके से हासिल न कर पाने की स्थिति में किसी तरह के दंड का प्रावधान नहीं किया गया है. इसी तरह विस्तृत समय सारिणी, समय सीमा या लक्ष्यों को इस समझौते में शामिल नहीं किया गया है. समय सीमा के साथ लक्ष्य निर्धारित किए जाने को लेकर क्योटो प्रोटोकॉल का विरोध हुआ था और उसी के चलते इस जलवायु सम्मेलन का लक्ष्य किसी बाध्यकारी समझौते तक पहुंचना था, जैसा कि पिछले 20 वर्षों में संभव नहीं हो सका था.

पेरिस सम्मेलन से पहले हुए विभिन्न जलवायु सम्मेलनों में बात अंतिम समय में आकर असफल हो रही थी. क्योटो प्रोटोकाल के लक्ष्य पूरे करने की अवधि समाप्त होने के बाद दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग के ख़तरों से बचाने के लिए नए लक्ष्यों का निर्धारण नहीं हो पा रहा था. सम्मेलन से पहले कहा जा रहा था कि किसी समझौते तक पहुंचने की चाबी अमेरिका और चीन जैसे देशों के हाथों में है. यदि ये दोनों देश मसौदे पर सहमत नहीं होते हैं, तो पेरिस सम्मेलन का भी कोई नतीजा नहीं निकलेगा. हालांकि, भारत की ओर से सम्मेलन में हिस्सा लेने गए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि पेरिस में कोई समझौता होगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर है कि अमीर देश कितनी दरियादिली और लचीलापन दिखाएंगे. सम्मेलन का नतीजा विकसित देशों के सही रुख़ पर निर्भर है, वरना यह सब धोखे जैसा है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार विभिन्न मंचों पर आतंकवाद और ग्लोबल वार्मिंग को वैश्विक चुनौती बता चुके हैं. साथ ही वह इन चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी दुनिया द्वारा साझा प्रयास की बात कह चुके हैं. भारत के इसी रुख की झलक पेरिस में दिखाई दी. हालांकि, भारत जी-134 (विकासशील देशों का संगठन) में चीन के साथ मिलकर विकासशील देशों के हक़ की लड़ाई भी लड़ रहा था. ऐसे में इस बार भी अमेरिका, चीन एवं भारत पर पेरिस जलवायु सम्मेलन सफल बनाने का सबसे ज़्यादा दारोमदार था. वार्ता में भारत एक अहम भागीदार बनकर उभरा. जानी-मानी पत्रिका टाइम ने अपने एक लेख में कहा कि इस वार्ता में भारत एक अहम खिलाड़ी के रूप में सामने आया है. पत्रिका ने कहा कि भारतीय नेता जलवायु परिवर्तन के मामले पर ऐसी स्थिति में हैं, जहां उन्हें बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है. भारत के अधिकारी दिखाना चाहते हैं कि विश्व का चौथा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश अंतरराष्ट्रीय जलवायु वार्ताओं में एक रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार है.

इस समझौते में साझा, लेकिन विविध ज़िम्मेदारी के सिद्धांत को जगह दी गई है, जिसकी भारत लंबे अर्से से मांग करता रहा है, जबकि अमेरिका एवं दूसरे विकसित देश इस प्रावधान को कमज़ोर करना चाहते थे. भारत इस समझौते में टिकाऊ जीवन शैली और उपभोग का जिक्र चाहता था, जिसे इसमें जगह दी गई है. हालांकि, इस समझौते में एक बड़ी चुनौती ग्लोबल वार्मिंग को औद्योगिक क्रांति से पहले के वैश्विक तापमान से अधिकतम दो फ़ीसद तक ले जाने की है. विकासशील देशों को स्वच्छ ईंधन और प्रौद्योगिकी अपनाने में मदद करने के लिए समृद्ध देशों द्वारा 2020 से सालाना 100 अरब डॉलर देने पर सहमति बनी है, लेकिन इसमें तकनीकों के हस्तांतरण की बात नहीं है. कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मसौदे में तय 1.5 डिग्री सेल्सियस का लक्ष्य हासिल करने के लिए 2030 से 2050 के बीच जीरो कार्बन उत्सर्जन की आवश्कता होगी. जलवायु परिवर्तन पर किसी समझौते पर पहुंचने से पहले विकसित और विकासशील देशों में ज़ोरदार टकराव देखने को मिला. चर्चा के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने धमकी दी कि यदि विकासशील देश विकसित देशों पर अधिक ज़िम्मेदारी उठाने और आर्थिक मदद देने का दबाव बनाएंगे, तो अमेरिका इस समझौते से खुद को दूर कर लेगा. विकासशील देशों ने अमेरिका के रवैये पर कड़ी आपत्ति जताई. कैरी ने तीखे तेवर दिखाते हुए कहा कि समझौते के हर शब्द पर नुक्ताचीनी नहीं हो सकती. चीन ने अमेरिकी विदेश मंत्री के इस बयान पर तगड़ा हमला किया और विकासशील देशों की ओर से कहा कि कुछ देश अपनी ज़िम्मेदारी से भाग रहे हैं, जो वार्ता की भावना के अनुकूल नहीं है.

पेरिस जलवायु सम्मेलन में सहमति बनने के बावजूद भारत की कई चिंताओं को मसौदे में जगह नहीं दी गई. भारत का कहना था कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित कर देने के लक्ष्य के लिए विकसित देशों को अपने उत्सर्जनों में भारी कटौती करनी होगी और विकासशील देशों को दी जाने वाली आर्थिक मदद बढ़ानी होगी. पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (आईएनडीसी) एक नई एवं बड़ी खोज है और यह महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाली साबित हुई है. इसने 186 से अधिक देशों की भागीदारी को समर्थ बनाया है. इसके बावजूद आईएनडीसी का मसौदे में जिक्र नहीं किया गया. समझौते में वैश्विक तापमान की सीमा दो डिग्री सेल्सियस से काफी कम रखने प्रस्ताव है. तापमान वृद्धि पर अंकुश की यह बात भारत और चीन जैसे विकासशील देशों की पसंद के अनुरूप नहीं है, जो औद्योगिकीकरण के कारण कार्बन गैसों के बड़े उत्सर्जकों में से एक हैं. विशेषज्ञों की राय है कि मूल संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन में विकसित देशों पर कड़े शब्दों में ज़िम्मेदारी डाली गई थी, लेकिन मौजूदा समझौते की भाषा कमज़ोर है. इसमें ऐसी कई बातें हैं, जिनसे जलवायु वित्त पोषण (फाइनेंस) के मुद्दों पर भ्रम हो सकता है, जैसे विकास के लिए दी जाने वाली सहायता राशि या ऋण को जलवायु वित्त के रूप में गिना जा सकता है. भारत के पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी कहते हैं कि यह समझौता और अधिक महत्वाकांक्षी हो सकता था, क्योंकि विकसित देशों की कार्रवाई उनकी ऐतिहासिक ज़िम्मेदारियों और निष्पक्ष हिस्सेदारी (शेयरों) की तुलना में काफी कम है. विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका एवं विकसित देशों के समूह के भारी दबाव के बाद उनकी ज़िम्मेदारियों में कटौती की गई है. समझौते में कहा गया है कि सभी पक्ष, जिनमें विकासशील देश भी शामिल हैं, कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए क़दम उठाएं. इसका अर्थ यह हुआ कि विकासशील देशों को इसके लिए क़दम उठाने होंगे, जो विकास के उनके सपने पूरे होने में रोड़ा साबित हो सकते हैं. समझौते के अनुसार, क्षति और घाटे को दायित्व या मुआवजे के संदर्भ में नहीं देखा जाएगा. इस तरह विकसित देशों पर कोई वास्तविक दायित्व नहीं होगा. लेकिन, मसौदे में व्यवसायियों, निवेशकों, शहरों एवं क्षेत्रों द्वारा किए गए कार्यों को मान्यता देना सम्मेलन के महत्वपूर्ण परिणामों में से एक है.

दुनिया के विकासशील देशों के समूह (जी-134) के प्रवक्ता गुरु दयाल सिंह ने कहा कि भारत, चीन एवं सऊदी अरब ग्लोबल वार्मिंग पर रोक लगाने के लिए नियोजित समझौते से खुश हैं. उन्होंने कहा, हमारा मानना है कि यह संतुलित है और इसमें हमारे हितों का ध्यान रखा गया है. समझौते से भारत, चीन, सऊदी अरब एवं अरब समूह सहमत हैं. यूरोपीय आयोग ने भी कहा कि उसे समझौते पर कोई आपत्ति नहीं है. समझौते में उसकी सभी मुख्य बातें शामिल हैं. समझौता महत्वाकांक्षी और संतुलित है. जलवायु सम्मेलन के अध्यक्ष लॉरेंट फेबियस ने कहा कि यह समझौता आपसी भरोसा कायम करने वाला है. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पेरिस समझौते का एक परिणाम यह हुआ कि न किसी एक देश की जीत हुई और न किसी की हार. केवल पर्यावरणीय न्याय की जीत हुई है. ■

navinonline2003@gmail.com

मुख्य बिंदु

दूरगामी लक्ष्य: समझौते में ग्लोबल वॉर्मिंग को दो डिग्री सेल्सियस के नीचे रखने का दूरगामी लक्ष्य रखा गया है. तापमान वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रखने के प्रयास किए जाएंगे. हालांकि, औद्योगिक युग की शुरुआत से अब तक इस तापमान में एक डिग्री की वृद्धि हो चुकी है. यह लक्ष्य हासिल करने के लिए विभिन्न देशों द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जितनी जल्दी संभव हो, वृद्धि रोकने की प्रतिबद्धता ज़ाहिर की गई. 2050 के बाद मानव निर्मित कार्बन उत्सर्जन में उस स्तर तक कमी आनी चाहिए, जिसे जंगल और समुद्र अवशोषित कर सकें.

उत्सर्जन लक्ष्य: सभी देश प्रत्येक पांच साल में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने के लिए अपने-अपने राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित करने पर सहमत हुए. 180 से अधिक देश 2020 से शुरू होने वाले पहले चक्र के लिए निर्धारित लक्ष्य प्रस्तुत कर चुके हैं. केवल विकसित देशों से पूर्ण रूप से लक्ष्यों के अनुरूप उत्सर्जन में कटौती की उम्मीद की जा रही है, जबकि विकासशील देशों को समय के साथ अपनी क्षमताओं के अनुरूप कटौती के लिए प्रेरित किया जा रहा है. तब तक उनसे उनकी अर्थव्यवस्था के विकास के अनुरूप उत्सर्जन वृद्धि पर लगाम लगाने की उम्मीद की जा सकती है.

लक्ष्यों की समीक्षा: प्रारंभिक लक्ष्य दीर्घकालिक तापमान लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं. इसलिए समझौते में विभिन्न देशों से कहा गया है कि वे अगले चार सालों में अपने लक्ष्यों की समीक्षा करके यह देखें कि क्या वे कुछ और बेहतर कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें अपने लक्ष्य बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आशा है कि ऐसा अक्षय ऊर्जा स्रोतों के और अधिक किफायती एवं प्रभावी होने पर ही संभव हो पाएगा.

पारदर्शिता: उत्सर्जन के लक्ष्य पूरे न कर पाने पर किसी तरह के दंड का प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन समझौते के पारदर्शिता नियम देशों की मदद करेंगे. चीन कह रहा था कि विकासशील देशों के लिए नरम रुख हो, जो सभी के बीच सहमति बनाने में आने वाली सबसे बड़ी अड़चन थी. समझौते में कहा गया है कि सभी देश अपने यहां के उत्सर्जन स्तर और अपने द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की जानकारी दें. यह समझौता विकासशील देशों के लिए कुछ लचीलेपन की अनुमति देता है, जो विकासशील देशों की तात्कालिक ज़रूरत है.

वित्त: समझौते में प्रावधान है कि अमीर देश उत्सर्जन में कमी लाएं और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ग़रीब देशों की मदद करते रहें. यह चीन जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए मार्ग प्रशस्त करता है. ग़रीब देशों की मदद के लिए स्पष्ट तौर पर किसी धनराशि का प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन अमीर देशों ने स्वयं 2020 से विकासशील देशों की मदद के लिए प्रतिवर्ष 100 अरब डॉलर मुहैया कराने की घोषणा की है.

नुक़सान और क्षति दायित्व: बढ़ते समुद्री जलस्तर की वजह से छोटे द्वीपों के लिए उत्पन्न होने वाले डूब के ख़तरे के संबंध में भी इस समझौते में बहुत कुछ है. समझौते में पर्यावरण संबंधित आपदा से हुए नुक़सान और क्षति दायित्व के प्रावधान किए गए हैं. अमेरिका अर्से से इस प्रावधान का विरोध कर रहा है. उसकी चिंता है कि ऐसे देश मौसमी घटनाओं की वजह से हुए नुक़सान पर क्षतिपूर्ति का दावा करने लगेंगे. अंत में इस मसले को भी शामिल कर लिया गया, लेकिन फुट नोट में यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि नुक़सान और क्षति दायित्व के अंतर्गत किसी तरह की ज़िम्मेदारी तय करने या मुआवजे का प्रावधान नहीं है. ■

जनवरी 2015 में मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार राज्य वेटलैंड अथॉरिटी का राज्य एवं ज़िला स्तर पर गठन किया. राज्य स्तर पर बीएसडब्ल्यूए के अध्यक्ष मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष नगर विकास मंत्री बनाए गए. जल संसाधन, वन एवं पर्यावरण और पर्यटन आदि विभागों के मंत्री, मुख्य सचिव, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के मुख्य सचिव, राज्य सरकार के वित्त, नगर विकास, वन एवं पर्यावरण, जल संसाधन, पर्यटन, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, कृषि एवं मत्स्य विभाग के प्रधान सचिव सदस्य बनाए गए. ज़िला स्तर पर भी प्राधिकरण का गठन किया गया. लेकिन, आज तक न तो प्राधिकरण की बैठक हुई, न अतिक्रमण हटा और न पैमाइश का काम पूरा हुआ.

बिहार: मोतिहारी

मस्तक का तिलक बन रहा बदनुमा दाग

मोती झील की ज़मीन का खसरा संख्या 858 एवं 859 एक है. प्रशासन की उदासीनता के चलते भू-माफियाओं ने जानपुल की ओर से मोती झील की ज़मीन का एक बड़ा रकबा कब्जा लिया. खास महाल की उक्त ज़मीन की धड़ल्ले से खरीद-बिक्री होने लगी. यही नहीं, निजी स्वार्थवश नियमों को ताक पर रखकर भूखंडों का दाखिल-खारिज भी होता रहा. 2002-03 में राष्ट्रीय सम विकास योजना शुरू हुई, जिसके तहत झील के विकास के लिए ज़िला स्तर पर तीन करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया. राष्ट्रीय सम विकास योजना के अध्यक्ष स्थानीय सांसद और सचिव ज़िलाधिकारी होते थे. 2009 तक मोती झील के संरक्षण के लिए कुछ भी नहीं हुआ, तो नगर परिषद ने प्रयास शुरू किए और विधानसभा में सवाल पूछे गए. उस समय नर्मदेश्वर लाल ज़िलाधिकारी थे और वह मोतिहारी के विकास को लेकर संजीदा थे. उन्होंने मोती झील की स्थिति की समीक्षा के बाद विधानसभा के सवाल के जवाब में कहा कि उक्त धनराशि से मोती झील के विकास एवं संरक्षण का कार्य नहीं हो सकता. उन्होंने सरकार को स्थिति से अवगत कराते हुए लिखा कि तीन करोड़ रुपये से झील का जीर्णोद्धार नहीं हो सकता. लाल ने कहा कि ज़िला स्तर पर ऐसी कोई तकनीकी टीम नहीं है, जो मोती झील के जीर्णोद्धार की योजना बना सके. इसलिए सरकार अपने स्तर पर मोती झील के लिए योजना बनवाए. बाद में उन्होंने ज़िला योजना एवं विकास विभाग से अनुमति प्राप्त कर उक्त धनराशि से समाहरणालय एवं चम्द्रहिया के गांधी स्मारक के सौंदर्यीकरण और गांधी मैदान की चहारदीवारी निर्माण का कार्य कराया.

यह नर्मदेश्वर लाल के प्रयासों का प्रतिफल है कि मोतिहारी का समाहरणालय देश का सबसे सुंदर एवं व्यवस्थित समाहरणालय माना जाता है. श्री लाल ने मोती झील की ज़मीन की पैमाइश कराकर उसे अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश अंचल पदाधिकारी को दिया. मापी हुई ज़मीन और अतिक्रमणकारियों को चिन्हित कर ज़िला प्रशासन की ओर से नोटिस भेजा गया. शहर में हड़कंप मच गया. कईयों ने अपने कागजात प्रशासन को दिखाए और कहा कि बेतिया राज द्वारा उक्त ज़मीन उन्हें बंदोबस्त की गई है. सच्चाई की तह तक जाने के लिए श्री लाल ने एक पदाधिकारी को कोलकाता भेजा और जांच कराई, जहां उक्त दावों की सत्यता पर प्रश्नचिन्ह लग गया. हालांकि, इस बीच श्री लाल का स्थानांतरण हो गया और मामला ठंडे बस्ते में चला गया. उधर राज्य सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने भारत सरकार की राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना (एनएलसीपी) को प्रस्ताव भेजा. प्रस्ताव को स्वीकृति देते हुए एनएलसीपी ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करके भेजने का निर्देश दिया. एनएलसीपी ने कहा कि परियोजना की लागत राशि का 70 फ़ीसद हिस्सा भारत सरकार देगी और बाकी 30 फ़ीसद राज्य सरकार को वहन करना होगा. 2012 में अपनी विकास यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मोतिहारी आए, तो उन्होंने मोती झील का निरीक्षण किया. मोती झील की दुर्दशा और अतिक्रमण देखकर उन्होंने इसकी पैमाइश कराकर अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश तत्कालीन डीएम को दिया. आदेश के बाद पैमाइश हुई और 169 लोगों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस देकर खानापूर्ति कर दी गई. लेकिन, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी.

फरवरी 2013 में राज्य सरकार के नगर विकास विभाग द्वारा 220 करोड़ रुपये का एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन एनएलसीपी को भेजा गया. प्रतिवेदन में मोती झील एवं करिया मन के विकास और सौंदर्यीकरण के काम भी शामिल थे. एनएलसीपी ने उस परियोजना प्रतिवेदन को यह कहकर वापस कर दिया कि उसका काम केवल झील को संरक्षित करना है. सौंदर्यीकरण एवं पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का काम पर्यटन विभाग द्वारा किया जाएगा. जुलाई 2013 में राज्य सरकार ने पुन: 110 करोड़ रुपये का संशोधित परियोजना प्रतिवेदन एनएलसीपी को भेजा, लेकिन उसमें भी ग़लतियां रह गईं. संशोधित प्रतिवेदन में करिया मन को हटा दिया गया, लेकिन मोती झील के सौंदर्यीकरण की योजना नहीं हटाई गई. फरवरी 2014 में परियोजना प्रतिवेदन पुन: संशोधित करके भेजा गया, जो 70 करोड़ रुपये का था. एनएलसीपी ने उसकी जांच वेटलैंड एशिया नामक तकनीकी संस्थान से कराई और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि चूंकि मोती झील खास महाल की ज़मीन पर है, इसलिए एक प्राधिकरण का गठन किया जाए और उस प्राधिकरण की बैठक में परियोजना अनुमोदित करके भेजी जाए. साथ ही कहा गया कि मोती झील का रख-रखाव वन एवं पर्यावरण विभाग करता है और बंदोबस्ती मत्स्य विभाग करता है. इसलिए प्राधिकरण समेकित ज़िम्मेदारी तय करे. राज्य सरकार गंदे पानी का बहाव रोकने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना सुनिश्चित करे, अतिक्रमण हटाए और चीनी मील एवं अन्य उद्यमों का कचरा मोती झील में गिरने से रोके. साथ ही झील के संरक्षण के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान करते हुए कहा गया कि अन्य कार्यों के लिए राशि की मांग संबंधित विभाग राज्य सरकार से करें.

जनवरी 2015 में मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार राज्य वेटलैंड अथॉरिटी का राज्य एवं ज़िला स्तर पर गठन किया. राज्य स्तर पर बीएसडब्ल्यूए के अध्यक्ष मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष नगर विकास मंत्री बनाए गए. जल संसाधन, वन एवं पर्यावरण और पर्यटन आदि विभागों के मंत्री, मुख्य सचिव, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के मुख्य सचिव, राज्य सरकार के वित्त, नगर विकास, वन एवं पर्यावरण, जल संसाधन, पर्यटन, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, कृषि एवं मत्स्य विभाग के प्रधान सचिव सदस्य बनाए गए. ज़िला स्तर पर भी प्राधिकरण का गठन किया गया. लेकिन, आज तक न तो प्राधिकरण की बैठक हुई, न अतिक्रमण हटा और न पैमाइश का काम पूरा हुआ. मोती झील को बचाने के लिए पिछले एक साल से आंदोलन जारी है. इस आंदोलन की शुरुआत सोशल मीडिया द्वारा गत वर्ष 14 अक्टूबर को हुई. उसके बाद 18 अक्टूबर, 2014 को मोती झील बचाओ समिति का गठन किया गया. 23 अक्टूबर, 2014 को दीवाली की पूर्व संध्या पर कैंडल मार्च का आयोजन हुआ, जिसमें शहर के प्रतिष्ठित चिकित्सकों, शिक्षाविदों, व्यवसायियों एवं पत्रकारों समेत कई संस्थाओं ने हिस्सा लिया. तबसे मोती झील बचाओ समिति के बैनर तले आंदोलन लगातार जारी है. नगर परिषद के सभापति प्रकाश अस्थाना कहते हैं कि वह भी मोती झील के पुनरुद्धार के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में नगर परिषद की कोई भूमिका नहीं है. यह केंद्र एवं राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है. मोती झील के प्रति जन-जागरण के उद्देश्य से 2014 से मोती झील महोत्सव की शुरुआत हुई है. बीते 29-30 नवंबर को द्वितीय मोती झील महोत्सव का आयोजन हुआ. हालांकि, मोती झील बचाओ समिति द्वारा महोत्सव का विरोध किया गया. समिति के सचिव अंसारुल हक़ का कहना है कि जितना पैसा महोत्सव में खर्च किया गया, उससे मोती झील साफ़ कराई जा सकती थी. स्थानीय सांसद एवं केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि एनएलसीपी ने 25 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान कर दिया है. जब राज्य सरकार प्राधिकरण से अनुमोदित संशोधित परियोजना प्रतिवेदन केंद्र सरकार को भेज देगी, तो उसके एक सप्ताह के भीतर उक्त धनराशि उसे मिल जाएगी. ■

राकेश कुमार

पूर्वी चंपारण के मोतिहारी ज़िला मुख्यालय की हृदयस्थली कहलाती है मोती झील. शहर को दो हिस्सों में बांटती मोती झील कभी उसके मस्तक पर कुमकुम की तरह चार चांद लगाती थी, पर आज वह एक बदनुमा दाग की शक्ल में नज़र आती है. कभी मोती झील की तुलना श्रीनगर की डल झील से की जाती थी. 487 एकड़ में फैली मोती झील आज मोतिहारी के लिए तनाव की वजह बन गई है. मोती झील का एक बड़ा हिस्सा अतिक्रमण का शिकार है, उसमें पानी पहुंचाने वाले स्रोत बंद कर दिए गए हैं और किनारे बसे मुहल्लों के नालों का पानी उसे दूषित कर रहा है. आज मोती झील कूड़ा-कचरा फेंकने का अड्डा बन गई है, जलकुंभी ने झील को ढंक रखा है. स्वच्छ हवा की जगह बदबू का साम्राज्य है. मोती झील की दुर्गति के लिए सभी लोग यानी नागरिक, नेता और प्रशासन समान रूप से ज़िम्मेदार हैं. सुखद यह कि मोती झील को बचाने के लिए एक बार फिर शहर के बुद्धिजीवी एवं आम लोग एक साथ आ खड़े हुए हैं.

मोती झील के लिए पानी का मुख्य स्रोत नेपाल की पहाड़ियों से निकलने वाली रामरेखा नदी थी. सेमरा बांध से लखौरा की तरफ़ से चवर और सोती के सहारे पानी खोखरा पुल होते हुए जानपुल के रास्ते मोती झील में आता था. झील से यह पानी करिया झील होता हुआ गंडक नदी में चला जाता था. वहीं पुराणों में वर्णित धनौती नदी, जिसे प्राचीन काल में विशाल्या गंडक कहते थे, की एक उप-धारा मोती झील में जाती थी. इससे उत्तर दिशा से नेपाल की ओर से आने वाले जल का अनवरत प्रवाह मोती झील के रास्ते होता रहता था. यही वजह है कि मोतिहारी में बाढ़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था. मोती झील को मोतिहारी का सुरक्षा कवच भी कहा जा सकता है, लेकिन जल प्रवाह के रास्तों का अतिक्रमण होने लगा. देवराहा बाबा मठ के पास स्थित पुल राष्ट्रीय उच्च पथ निर्माण के दौरान बंद हो गया. लखौरा की ओर से जल प्रवाह रुक गया, धनौती नदी भी शहर आते-आते नाले में तब्दील हो गई. जानपुल की ओर से मोती झील के अतिक्रमण के चलते मुहाना ही बंद हो गया. साफ़ पानी की जगह मोती झील में दूषित पानी नज़र आने लगा. हालांकि, ब्रिटिश काल में भी शहर के नालों का पानी मोती झील में ही गिरता था. मिसकार्ट मुहल्ले में आज भी इसका प्रमाण मिलता है. 1986 में रतनपुर उप-वितरणी का निर्माण भी मोती झील में पानी पहुंचाने के लिए किया गया था. रतनपुर उप-वितरणी के अनुसंधान प्रतिवेदन से इसकी पुष्टि होती है.

मोती झील की ज़मीन का खसरा संख्या 858, 859 एवं एक है. प्रशासन की उदासीनता के चलते भू-माफियाओं ने जानपुल की ओर से मोती झील की ज़मीन का एक बड़ा रकबा कब्जा लिया. खास महाल की उक्त ज़मीन की धड़ल्ले से खरीद-बिक्री होने लगी. यही नहीं,

मोती झील के लिए पानी का मुख्य स्रोत नेपाल की पहाड़ियों से निकलने वाली रामरेखा नदी थी. सेमरा बांध से लखौरा की तरफ़ से चवर और सोती के सहारे पानी खोखरा पुल होते हुए जानपुल के रास्ते मोती झील में आता था. झील से यह पानी करिया झील होता हुआ गंडक नदी में चला जाता था. वहीं पुराणों में वर्णित धनौती नदी, जिसे प्राचीन काल में विशाल्या गंडक कहते थे, की एक उप-धारा मोती झील में जाती थी.

feedback@chauthiduniya.com

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

यह सिर्फ़ हास्यास्पद नहीं है, बल्कि इससे अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम के लोग जनता की नज़र में अपनी विश्वसनीयता खो देंगे. वे अपने विरोधियों को घेर सकते हैं, अरुण जेटली को अपमानित कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उनके पास कोई पुख्ता आधार होना चाहिए. जब तक संसद सत्र चल रहा है, तब तक समाचार चैनल इस मामले को हरा रखना चाहते हैं. यह हमारे परिपक्व लोकतंत्र के संचालन के लिए अच्छा संकेत नहीं है. बहुत-सी सरकारें बदलीं, कई प्रधानमंत्री आए, लेकिन इस तरह का तमाशा पहले कभी नहीं हुआ.

सरकार स्थापित मापदंड अपनाए

दिल्ली के घटनाक्रम ज़ाहिर करते हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब अपना संयम खो चुके हैं. यह सच है कि जबसे उन्होंने 70 में से 67 सीटों के अपार बहुमत के साथ चुनाव में जीत हासिल की है, भाजपा उसे स्वीकार नहीं कर पाई है. हरसंभव तरीके से उन्हें परेशान करने की कोशिशें लगातार हो रही हैं और उनका काम मुश्किल बनाया जा रहा है. पुलिस कमिश्नर, जो मुख्यमंत्री की तुलना में छोटे ओहदे का अधिकारी है, मुख्यमंत्री को बहस के लिए चुनौती दे रहा है. यह एक बेतुकी और अतार्किक बात है. लेकिन, बाद में पुलिस कमिश्नर को सद्बुद्धि आई और वह अपने काम से काम रखने लगे. अभी तक राज्य सरकार और केंद्र सरकार आवश्यक समन्वय स्थापित नहीं कर सकी हैं. पिछले दिनों सीबीआई ने मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव राजेंद्र कुमार के कार्यालय पर छापा मारा. वह एक नियमित सेवा के अधिकारी हैं. अरविंद केजरीवाल उन्हें कहीं और से लेकर नहीं आए हैं. उनके ख़िलाफ़ वर्ष 2002 के बाद की शिकायतें हैं. छापे औचक तरीके से ही मारे जाते हैं. 2002 की शिकायतों पर अब छापेमारी करना समझ से परे है. अगर वह शख्स मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़ा हुआ है, तो सीबीआई को अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए थी, लेकिन सीबीआई तो सीबीआई है और वह अपने पारंपरिक एवं चिर-परिचित अहंकारी अंदाज़ में मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंच गई.

केजरीवाल की प्रतिक्रिया सही ठहराई जा सकती है, लेकिन उन्होंने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, उसे किसी भी तरह जायज नहीं कहा जा सकता. वह न केवल सख्त थी, बल्कि एक तरह से कहा जाए, तो असभ्य थी. आख़िरकार वह एक प्रधानमंत्री के बारे में कुछ कह रहे थे. आप प्रधानमंत्री के कितने भी ख़िलाफ़ हो जाएं, लेकिन आपको भाषा में संयम सदैव बरतना चाहिए. इसे बदकिस्मती ही कहिए कि लगातार चलने वाले घटनाक्रम की वजह से अरविंद केजरीवाल अपना आपा खो बैठे और उन्होंने मोदी पर इस मसले में सीधे तौर पर शामिल होने का आरोप लगा दिया. इस मसले पर नीतीश कुमार ने बहुत ही तार्किक और संतुलित बयान दिया. उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें अपनी मर्यादा का पालन नहीं कर रही हैं, जिसकी उनसे अपेक्षा है. मेरे ख्याल से यह बहुत ही सटीक और उपयुक्त बयान था, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार से क़ानून और मर्यादा के अनुरूप कार्य करने की अपेक्षा की गई है.

अब एक बहुत छोटा मसला, जिसका संबंध प्रशासन से नहीं है और जो डीडीसीए की कार्यप्रणाली से संबंधित है. हर खेल संगठन की तरह यहां भी कीर्ति आज़ाद और बिशन सिंह बेदी जैसे नाखुश लोग हैं, जो समय-समय पर अपनी राय रखते रहे हैं. अरुण जेटली 1999 से 2013 तक डीडीसीए के अध्यक्ष रहे. सीबीआई के छापे ने उन पर हमला करने के लिए इन नाखुश लोगों को एक हथियार दे दिया. वे रोज़ाना जेटली पर आरोप लगा रहे हैं और उनके इस्तीफ़े की मांग कर रहे हैं, जो बहुत हास्यास्पद है. जब अरुण जेटली के ख़िलाफ़ बतौर वित्त और कंपनी मामलों के मंत्री के रूप में कुछ नहीं मिला, तो अब उनका इस्तीफ़ा डीडीसीए के अध्यक्ष के कार्यकाल के दौरान हुए एक मामले के आधार पर मांगा जा रहा है. यह सिर्फ़ हास्यास्पद नहीं है, बल्कि इससे अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम के लोग जनता की नज़र में अपनी विश्वसनीयता खो देंगे. वे अपने विरोधियों को घेर सकते हैं, अरुण जेटली को अपमानित कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उनके पास कोई पुख्ता आधार होना चाहिए. जब तक संसद सत्र चल रहा है, तब तक समाचार चैनल इस मामले को हरा रखना चाहते हैं. यह हमारे परिपक्व लोकतंत्र के संचालन के लिए अच्छा संकेत नहीं है. बहुत-सी सरकारें बदलीं, कई प्रधानमंत्री आए, लेकिन इस तरह का तमाशा पहले कभी नहीं हुआ.

राजीव गांधी के बाद नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज होने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं. वह एक मजबूत स्थिति में हैं. जब आप मजबूत स्थिति में होते हैं, तब आपको विनम्र होना चाहिए, आपको सबको साथ लेकर चलने वाला होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ. दिल्ली चुनाव के नतीजों से उन्हें सीख लेनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. बिहार चुनाव के नतीजों के बाद ऐसा लगता है कि भाजपा का एक वर्ग यह समझ गया है कि अहंकार से काम नहीं चलेगा.

राजीव गांधी के बाद नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज होने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं. वह एक मजबूत स्थिति में हैं. जब आप मजबूत स्थिति में होते हैं, तब आपको विनम्र होना चाहिए, आपको सबको साथ लेकर चलने वाला होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ. दिल्ली चुनाव के नतीजों से उन्हें सीख लेनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. बिहार चुनाव के नतीजों के बाद ऐसा लगता है कि भाजपा का एक वर्ग यह समझ गया है कि अहंकार से काम नहीं चलेगा. लेकिन, हमें कोई सुधार नज़र नहीं आ रहा है. प्रधानमंत्री जितनी जल्दी इस दिशा में क़दम उठाएंगे (और वह ऐसा आसानी से कर सकते हैं), उतना ही बेहतर होगा. दिल्ली सरकार अपने मामलों को मुख्यमंत्री की एक ही बैठक में दुरुस्त कर सकती है. आख़िरकार दिल्ली सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन उसके अधिकार सीमित हैं. सीमित अधिकारों के अंतर्गत वह जो करना चाहती है, उसे करने देना चाहिए. पांच वर्षों के बाद उन्हें मतदाताओं का एक बार फिर सामना करना पड़ेगा. इसलिए कोई बाधा पहुंचाने और अपनी कमियां दूसरों पर मढ़ने का मौक़ा देने के बजाय उन्हें इस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे जनता से किए गए वादे पूरे करें. दरअसल, उन्होंने जनता से ऐसे वादे किए हैं, जिन्हें पूरा कर पाना बेहद मुश्किल है. भ्रष्टाचार ख़त्म कर पाना बेहद मुश्किल काम है, लेकिन वे इसके लिए पुरज़ोर कोशिश कर रहे हैं. अगर वे दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त कर पाते हैं, तो यह देश के लिए बहुत बड़ी सेवा होगी. और, किसी को इस पर क्या आपत्ति होनी चाहिए?

फिलहाल सबसे उचित क़दम यह होगा कि लोकतंत्र को पटरी पर लाया जाए. यह सभी दलों का काम है. राजनीति संयम का खेल है. इसमें कोई जीतता है, तो कोई हारता है और इसके लिए चिंतित नहीं होना चाहिए. लेकिन, मूलभूत ढांचे के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए. ऐसी स्थितियों में हर मामला अदालतों में जाता है और अदालतें राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगती हैं, जो सरकार के लिए ठीक नहीं है. दरअसल, जो काम सरकार को करना चाहिए, वह अदालतें कर रही हैं. सरकार जितनी जल्दी स्थापित मापदंड अपनाना शुरू कर देगी, भारतीय लोकतंत्र के लिए उतना ही बेहतर होगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

कश्मीरी किसानों पर जंगली जानवरों की मार

रेयाज मलिक

प्रकृति के नियमानुसार मानव को जीवन व्यतीत करने के लिए कुछ न कुछ मेहनत करनी पड़ती है और जब यह मेहनत सफल होती है, तो निस्संदेह बहुत खुशी होती है. यदि मेहनत किसी कारणवश विफल हो जाए, तो पछतावा कितना बड़ा होगा, इसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता. कुछ यही हालत है, जम्मू-कश्मीर सीमावर्ती ज़िले पूंछ के मंडी तहसील इलाके की, जहां की अधिकतर आबादी का जीवन खेती-बाड़ी से चल रहा है, लेकिन जंगली पशुओं ने उनका जीना दूभर कर रखा है. ग़ौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1978 जंगली पशु-पक्षियों अथवा जीव-जंतुओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए लागू किया गया था. 1982 में उक्त अधिनियम के तहत पशु-पक्षियों अथवा जीव-जंतुओं को सुरक्षा प्रदान करने और ख़तरनाक जंगली जानवरों से लोगों को बचाने के लिए अलग से एक विभाग बनाया गया, जो जम्मू-कश्मीर वन्य जीव सुरक्षा विभाग के नाम से जाना जाता है. विभाग की वेबसाइट के अनुसार, अब तक लगभग 15,806.75 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का घेराव किया जा चुका है, जिसमें पांच नेशनल पार्क, 14 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एवं 37 कंजर्वेशन रिजर्व शामिल हैं. यदि भौगोलिक तौर पर अनुमान लगाया जाए, तो राज्य का 15.85 प्रतिशत क्षेत्र विभाग के अंतर्गत आता है, जबकि वन्य के हिसाब से देखा जाए, तो 12.73 प्रतिशत. राज्य में जबरदस्त जलवायु परिवर्तन के अलावा लगभग 60 मुख्य नस्लों के जंगली जीव-जंतु पाए जाते हैं.

ग़ौरतलब है कि राज्य का राष्ट्रीय पशु हंगल (बारहसिंघा) है, जबकि राष्ट्रीय पक्षी काली लंबी गर्दन वाला क्रेन. चिनार राज्य का राष्ट्रीय वृक्ष है और कमल राष्ट्रीय फूल. जंगली जानवरों और इंसानों के झगड़े निपटाने के लिए राज्य सरकार के इस विभाग ने 50 कंट्रोल रूम बनाए हैं, जिनमें से 25 कश्मीर इलाके में हैं और 25 जम्मू में. विभाग के अनुसार, केंद्रीय कश्मीर में तीन, उत्तरी कश्मीर एवं शोपियां में सात-सात, अनंतनाग में पांच और तराई क्षेत्र में तीन कंट्रोल रूम हैं. शीतकालीन राजधानी यानी जम्मू में कठुआ में पांच, किश्तवाड़ एवं राजौरी में आठ-आठ और जम्मू में चार कंट्रोल रूम हैं. मजेदार बात यह है कि लद्दाख में एक भी कंट्रोल रूम नहीं है और न सीमावर्ती ज़िले पूंछ में. इसका खामियाजा स्थानीय नागरिकों को आएदिन भुगतना पड़ता है. कभी भालू बच्चों एवं महिलाओं पर हमला करके उन्हें अपना ग्रास बना लेते हैं, तो बंदर काट-काटकर अधमरा कर देते हैं, लेकिन विभाग विशेष लोगों की कोई मदद नहीं करता.

शीतकालीन राजधानी यानी जम्मू के कठुआ में पांच, किश्तवाड़ एवं राजौरी में आठ-आठ और जम्मू में चार कंट्रोल रूम हैं. मजेदार बात यह है कि लद्दाख में एक भी कंट्रोल रूम नहीं है और न सीमावर्ती ज़िले पूंछ में. इसका खामियाजा स्थानीय नागरिकों को आएदिन भुगतना पड़ता है. कभी भालू बच्चों एवं महिलाओं पर हमला करके उन्हें अपना ग्रास बना लेते हैं, तो बंदर काट-काटकर अधमरा कर देते हैं, लेकिन विभाग विशेष लोगों की कोई मदद नहीं करता.

मंडी तहसील अंतर्गत प्लेरा और राजपुरा दो बड़ी पंचायतें हैं, जो तहसील मुख्यालय से केवल चार किलोमीटर दूर हैं. इस ग्रामीण-पहाड़ी क्षेत्र में पिछले पांच वर्षों से काले भालुओं एवं जंगली बंदरों का आतंक कायम है. क्षेत्र के अधिकतर लोग खेती-बाड़ी करते हैं. मकई यहां की मुख्य फसल है, इससे मवेशियों के लिए चारा भी मिलता है और लोग इसकी रोटी बड़े चाव से खाते हैं. मकई बोते समय बंदर खेतों में घुसकर बैठ जाते हैं और बीज का एक-एक दाना ज़मीन से निकाल कर खा जाते हैं. दो-चार बार बुआई और सख्त रखवाली के बाद जब कुछ पौधे लगते हैं, तो बंदर मौक़ा पाते ही सारा खेत चौपट कर देते हैं. राजमा यहां की क़ीमती फसल है, जिसे उगाकर किसान अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं, उसे भी भालुओं एवं बंदरों ने बर्बाद कर रखा है. पलीरा निवासी 55 वर्षीय शाहबाज के अनुसार, जंगली जानवरों ने पूरी खेती बर्बाद कर रखी है. मेरे खेत में 50 क्विंटल मकई, सेब, आड़ू, नाशपाती, खुबानी और अखरोट होते थे, जिन्हें बेचकर मैं घर का खर्च चलाता था, मगर बंदरों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा. राजपुरा निवासी मोहम्मद लतीफ मलिक बताते हैं, मेरे खेत में 10 क्विंटल मकई के अलावा नाशपाती भी होती थी, मगर पिछले कई वर्षों से बंदरों ने कुछ भी नहीं होने दिया. नतीजतन, मैंने खेती करना छोड़ दिया. नियाज अहमद तांत्रे कहते हैं कि भालू और बंदर मंडी तहसील के हर गांव में फैल चुके हैं. राजपुरा, अड़ई, चखड़ीबन, सावजियां, गगड़ियां एवं लोरन आदि ऊपरी क्षेत्रों में लोगों की फसलें बिल्कुल बर्बाद हो चुकी हैं. इसके अलावा घरों में पारंपारिक तरीके से दीवारों में मधुमक्खी पालन का रिवाज है, लेकिन भालू-बंदर मधुमक्खी के छत्ते उखाड़ कर शहद और मक्खियां दोनों खा जाते हैं.

जंगली भालुओं और बंदरों ने आबादी के भीतर अपने अड्डे बना रखे हैं. नतीजतन, स्थानीय लोग आएदिन उनके शिकार बन जाते हैं. कई लोगों की जान भी जा चुकी है. अड़ई गांव निवासी बशीर अहमद को एक भालू ने उन्हीं के खेत में चीर-फाड़ कर खा लिया. उससे पहले अब्दुल अजीज डार एवं उनकी बेटी को भालू ने घायल कर दिया. अब्दुल अजीज ने अस्पताल पहुंचते ही दम तोड़ दिया. बंदरों द्वारा कुत्तों और इंसानों की पिटाई आम बात हो चुकी है. बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल है. अधिकतर अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते. यही नहीं, बंदर घरों में घुसकर राशन तक चट कर जाते हैं. अफ़सोस की बात यह है कि वन्य जीव विभाग की ओर से अब तक कोई क़दम नहीं उठाया गया. सरकार इस मद में करोड़ों रुपये खर्च तो कर रही है और अधिकारियों-कर्मचारियों को इस बाबत प्रशिक्षण भी दिया जाता है, लेकिन सब बेकार साबित हो रहा है. (चरखा)

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

जागिए, वरना हमें बर्बर समाज में जीना होगा

दिल्ली में निर्भया नाम से मशहूर बलात्कार की शिकार लड़की अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उस घटना ने देशवासियों को झकझोर दिया और दिल्ली में तो उसके ख़िलाफ़ अभूतपूर्व आंदोलन हुआ. लगभग सारी दिल्ली उस लड़की को न्याय दिलाने के लिए सड़कों के ऊपर थी. दिन बीते, लोगों के दिमाग़ से वह लड़की भी बिसरती चली गई. सिर्फ़ एक घटना बनकर रह गई, जबकि बलात्कार नामक विषय उन दिनों भी ज़िंदा था और आज भी ज़िंदा है. सरकार ने सख्त क़ानून भी बनाया, लेकिन उसका असर लोगों के दिमाग़ पर नहीं पड़ा. जिन दिनों निर्भया के समर्थन में आंदोलन हो रहा था, उन दिनों भी देश में कम से कम 11-12 ऐसे मामले प्रकाश में आए, जिनमें लगभग उसी तरह की दरिंदगी लोगों ने दिखाई थी. तीन वर्ष बीत गए, लेकिन बलात्कार के प्रति लोगों में गुस्सा नहीं पैदा हुआ.

हालत यह है कि देश में हर जगह बलात्कार हो रहे हैं और मानसिक विकृति इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि तीन वर्षीया बच्ची हो, पांच वर्षीया बच्ची हो या फिर 12 वर्षीया बच्ची हो, किसी को भी बख्शा नहीं जा रहा है. पड़ोस की लड़की हो या सड़क पर चलती लड़की हो, उसके साथ हैवानियत की जाती है और गैंगरेप नामक चीज लगातार हो रही है. पुलिस आरोपियों को पकड़ भी रही है, लेकिन उसकी प्राथमिकता में इस तरह के मामले नहीं हैं. प्रश्न पुलिस या क़ानून का नहीं है, बल्कि समाज की मानसिकता का है, समाज की मान्यताओं का है और समाज द्वारा लोगों में पैदा हुई विकृति का है. ऐसा क्यों होता है कि खुलेआम कोई बलात्कार का समर्थन तो नहीं करता, लेकिन बलात्कार के प्रति सार्वजनिक घृणा का प्रदर्शन भी नहीं होता. अख़बार में ऐसी ख़बर पढ़कर, मुस्करा कर लोग दूसरी ख़बर के ऊपर चले जाते हैं.

पिछले 20 वर्षों से जबसे टेलीविजन चैनल शुरू हुए हैं, तबसे हर चैनल के ऊपर आध्यात्मिकता का ज़ोर तूफान मचा रहा है. हर चैनल पर कोई न कोई बाबा, साधु, महंत या जगतगुरु जीवन की शिक्षा देते दिखाई दे रहा है. इसके बाद सिर्फ़ अध्यात्म का प्रचार करने वाले विशेष चैनलों की शुरुआत हो गई, जिनमें 24 घंटे या तो कोई साधु या तो कोई बाबा लोगों को धर्म के प्रति प्रेरित करता दिखाई देता है या सत्संग-कीर्तन होता है. जैसे-जैसे चैनल बढ़े, जैसे-जैसे साधु महाराज सत्संग करने टेलीविजन पर आने लगे, यह विडंबना है कि वैसे-वैसे समाज में अपराध का ग्राफ बढ़ा, वैसे-वैसे मानवता को लज्जित करने वाले अपराधों, जैसे बलात्कार आदि की संख्या भी बढ़ी. आख़िर यह कौन-सी मानसिकता है? क्या हम धर्म के नाम पर ढोंग कर रहे हैं या जो लोग धर्म की शिक्षा देते हैं, उनमें आत्मबल नहीं है या फिर समाज नैतिकता या धर्म की बातें स्वीकार नहीं करना चाहता? यह सोचने का विषय है.

पहले बलात्कार का मतलब लड़कियों से बलात्कार होता था, लेकिन अब बलात्कार के मायने बदल गए हैं. कई ऐसी रिसर्च सामने आई हैं, जिनके अनुसार, लड़कियों से बलात्कार के मामलों की संख्या के मुक़ाबले लड़कों से बलात्कार के मामलों की संख्या ज़्यादा होती है. खासकर, शो बिजनेस में जो लोग हैं, उनके साथ तो बलात्कार होता ही है. अभी एक प्रसिद्ध अभिनेता ने खुलासा किया कि वह भी कास्टिंग काउच का शिकार रहा है. इसका मतलब उसके साथ जबरदस्ती की गई और उसने काम पाने के लिए समझौता किया. देश में समलैंगिक लोगों के आंदोलन चल रहे हैं, जिन्हें समाज मान्यता दे रहा है. दूसरी तरफ़ इंटरनेट के ऊपर पोर्न साइट्स की बाढ़ आई हुई है. पहले तो बहुत सारे टीवी चैनल रात 11 और एक बजे के बाद सॉफ्ट पोर्नोग्राफी वाली कहानियां दिखाते थे और फिल्में भी दिखाते थे. अभी चर्चित चैनल ऐसा नहीं कर रहे हैं. लेकिन, इंटरनेट के ऊपर पोर्न की धूम है और 10-12 वर्ष के बच्चे उस धूम के अगुवा बने हुए हैं. इंटरनेट, यू ट्यूब और फेसबुक वैसे वीडियो क्लिप्स खुलेआम दिखा रहे हैं, जिन्हें देखना पहले वर्जित माना जाता था. वे फिल्में हिट हो रही हैं, जिनमें सॉफ्ट पोर्नोग्राफी का इशारा है या द्विअर्थी संवाद हैं. क्या हमारा समाज इनके ख़तरे नहीं पहचानता? 10-12 वर्षीय बच्चे स्त्री-पुरुष के रिश्तों की हर बारीकी से परिचित हैं. अब उन्हें किसी टेलीविजन सीरियल या फिल्म से सीख की ज़रूरत नहीं है. इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है, जो उन्हें इन सारी चीजों की सजीव दुनिया में ले जाता है और वहां से उनके मन में देह के प्रति वह आकर्षण दिखता है, जिसके लिए बलात्कार शब्द बाद में प्रयोग में लाया जाता है.

पहले तो बहुत सारे टीवी चैनल रात 11 और एक बजे के बाद सॉफ्ट पोर्नोग्राफी वाली कहानियां दिखाते थे और फिल्में भी दिखाते थे. अभी चर्चित चैनल ऐसा नहीं कर रहे हैं. लेकिन, इंटरनेट के ऊपर पोर्न की धूम है और 10-12 वर्ष के बच्चे उस धूम के अगुवा बने हुए हैं. इंटरनेट, यू ट्यूब और फेसबुक वैसे वीडियो क्लिप्स खुलेआम दिखा रहे हैं, जिन्हें देखना पहले वर्जित माना जाता था. वे फिल्में हिट हो रही हैं, जिनमें सॉफ्ट पोर्नोग्राफी का इशारा है या द्विअर्थी संवाद हैं. क्या हमारा समाज इनके ख़तरे नहीं पहचानता?

सहमति से बहुत सारे रिश्ते बनते हैं. अब तो 10-11 वर्ष की आयु में रिश्ते बनने लगे हैं. लेकिन, जहां पर रिश्ते नहीं बन पाते, वहां जबरदस्ती होती है और वह जबरदस्ती हैवानियत में बदल जाती है.

मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि हमारा समाज जब इतनी चीजें ग़लत नहीं मानता, तो फिर वह बलात्कार को भी ग़लत नहीं मानता होगा. शायद इसीलिए एक आंदोलन होने के बाद बलात्कार को लेकर कोई दूसरा आंदोलन नहीं हुआ, कोई जागृति नहीं हुई. अब तो टीवी सीरियलों में खुलेआम लड़कियां आपस में बात करती नज़र आती हैं कि विदाउट ब्वॉयज नो पार्टी. अगर हम देखें, तो दूसरी तरफ़ यह एक स्वस्थ परंपरा भी है. जितना ज़्यादा घुले-मिलेंगे, उतना ही स्त्री-पुरुषों के बीच आकर्षण को विराम लगेगा. लेकिन हम अपने बच्चों को यह क्यों नहीं समझा पाते कि सहमति और जबरदस्ती, दोनों शब्दों का अर्थ क्या है? आध्यात्मिक दुनिया से जुड़े लोग या साधु-संत कोई असर नहीं डाल पा रहे हैं. और, जब मैं यह संपादकीय लिख रहा हूं, मेरे सामने ख़बर आ रही है कि तीन वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, अपराधी लापता हैं.

तो हम क्या मानें कि इसके लिए सरकार ज़िम्मेदार है? मेरा मानना है कि इसके लिए सरकार ज़िम्मेदार नहीं है, बल्कि समाज ज़िम्मेदार है. हम में से हर एक को अपनी बेटी, अपनी बहन के साथ हो सकने वाले किसी भी संभावित अपराध के लिए खुद को तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि जब हम उस अपराध के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, तो विश्वास मानिए, कोई दूसरा भी उसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाएगा. इसलिए बलात्कार जैसे अमानवीय कृत्य तब तक समाज में कम नहीं होंगे, जब तक समाज स्वयं इनके ख़िलाफ़ खड़ा नहीं होगा, जन-जागरण पैदा नहीं करेगा और इतना सख्त नहीं होगा कि वह उनका पारिवारिक बहिष्कार करने का माहौल बनाए, जो ऐसे अपराधों में लिप्त हैं. इसलिए यह समाज का विषय है और समाज को चाहिए कि वह एक सभ्य सोसायटी की जगह बारबेरियन सोसायटी या जंगली समाज की तरफ़ क़दम बढ़ाने से हिचके, अन्यथा खून के आंसू कल उन्हें भी बहाने पड़ेंगे, जो आज आवाज़ नहीं उठा रहे हैं. ■

editor@chauthiduniya.com

चेन्नई त्रासदी: सरकार की नाकामी का उदाहरण

मेघनाद देसाई

तमिलनाडु सामान्य रूप से कुशलतापूर्वक प्रशासित होने वाला राज्य है, जहां की कमान एक योग्य मुख्यमंत्री की हाथों में है, लेकिन इसके बावजूद यहां कोई दूरगामी सोच नहीं है. यहां न तो पुराने बुनियादी ढांचे का नवीनीकरण किया गया है और न आपातकाल में बचाव प्रणालियों का परीक्षण. एक ऐसा देश, जो अभियांत्रिकी प्रतिभा से परिपूर्ण है और एक ऐसा शहर, जिसका इतिहास दो सौ साल पुराना है, वहां इस तरह की त्रासदी समझ से बाहर है और राजनीतिक नेतृत्व की विफलता का प्रतीक भी. इसी वजह से अरविंद केजरीवाल की ऑड-ईवन (सम-विषम) अंक वाली क्रांतिकारी (रेडिकल) प्रणाली की प्रशंसा की जानी चाहिए.

चेन्नई आपदा को मुंबई में हर साल मानसून की शुरुआत में आने वाली बाढ़ या श्रीनगर की बाढ़ की नाटकीय पुनरावृत्ति के रूप में देखा जाना चाहिए. अगर बंगलुरू, कोलकाता एवं लखनऊ को भी ऐसी ही आपदा का सामना करना पड़े, तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए. भारत की नगरीय शासन व्यवस्था बुरी तरह विफल हो गई है. देश में निर्वाचित प्रतिनिधि भूमि के उपयोग को नियंत्रित करके भोले-भाले लोगों को लूटने में लगे हुए हैं. वे भूमि उपयोग में बदलाव लाकर उसके अलग उपयोग की अनुमति दे सकते हैं या किसी योजना में बसावट का प्रतिशत बढ़ा सकते हैं. उनके लिए यह एक लाभप्रद व्यवसाय है. दिन के उजाले में डकैती जैसे इन मामलों की हिमायत करने वाले दिग्गज कभी-कभी हत्या जैसे गंभीर मामलों से भी साफ़ बचकर निकल आते हैं. नगरीय प्रशासन राज्य एवं पंचायत के प्रशासन के बीच का प्रशासन बनकर रह गया है. कई नगरीय प्रशासन तो एक सदी से भी अधिक पुराने हैं और उनका नेतृत्व जवाहर लाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस जैसे महापुरुषों ने किया है. अब वे प्रशासन कमज़ोर और लचर हो गए हैं. इसका एक कारण यह है कि लंदन या न्यूयॉर्क के महापौर की तर्ज़ पर यहां कोई निर्वाचित एवं क्षमतावान नेतृत्व नहीं होता. शहरी राजनीति सक्षम एवं महत्वाकांक्षी लोगों को आकर्षित नहीं करती, जिसका परिणाम चेन्नई त्रासदी जैसी घटनाओं के रूप में सामने आता है.

तमिलनाडु सामान्य रूप से कुशलतापूर्वक प्रशासित होने वाला राज्य है, जहां की कमान एक योग्य मुख्यमंत्री की हाथों में है, लेकिन इसके बावजूद यहां कोई दूरगामी सोच नहीं है. यहां न तो पुराने बुनियादी ढांचे का नवीनीकरण किया गया है और न आपातकाल में बचाव प्रणालियों का परीक्षण. एक ऐसा देश, जो अभियांत्रिकी प्रतिभा से परिपूर्ण है और एक ऐसा शहर, जिसका इतिहास दो सौ साल पुराना है, वहां इस तरह की त्रासदी समझ से बाहर है और राजनीतिक नेतृत्व की विफलता का प्रतीक भी. इसी वजह से अरविंद केजरीवाल की ऑड-ईवन (सम-विषम) अंक वाली क्रांतिकारी (रेडिकल) प्रणाली की प्रशंसा की जानी चाहिए. मैं पिछले 11 वर्षों से लगातार दिल्ली आता रहा हूं. मैं यहां के जीवन स्तर में गिरावट से जितना हैरान हूं, उतनी ही हैरानी मुझे इसके प्रति राजनीतिक नेतृत्व की उदासीनता से है. अब इस सिलसिले में अधिक से अधिक यह कहा जा सकता है कि 10 वर्षों की देरी से सही, लेकिन बदलाव हो रहा है. 1990 के दशक से ही मेट्रो की आवश्यकता महसूस होने लगी थी. उसी तरह कारों के स्वामित्व और उनके उपयोग पर नियंत्रण की आवश्यकता काफी दिनों से महसूस की जा रही थी. ग़ैर-क़ानूनी पार्किंग तो वर्षों पहले समाप्त हो जानी चाहिए थी. लेकिन, यहां बदलाव के बजाय निष्क्रियता की राजनीति लोगों को अधिक भाती है. केजरीवाल ने बहुत-से ऐसे काम किए, जो बचकाना और अहंकारपूर्ण थे.

अब उन्होंने पहली बार यह दिखाया है कि आवश्यकता पड़ने पर अलोकप्रिय फ़ैसले लेने की क्षमता उनमें है. कार रखने वाले लोग स्वाभाविक रूप से केजरीवाल के फ़ैसले की विफलता की भविष्यवाणी करेंगे. लंदन में भी कंजेशन (भीड़भाड़) शुल्क लगाने से पहले यह सिस्टम आजमाया गया था, वहां भी अव्यवस्था की भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन प्रशासन ने स्मार्ट तकनीक के ज़रिये कंजेशन शुल्क की सख्ती से वसूली करके अव्यवस्था की भविष्यवाणी ग़लत साबित कर दी. केजरीवाल को भी इस फ़ैसले पर होने वाली आपत्तियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और क़ानून का पालन न करने वालों को किसी तरह की छूट नहीं मिलनी चाहिए. जनता स्थिति से उसी वक्त अभ्यस्त होगी, जब उसे यह एहसास होगा कि उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है. केजरीवाल दिल्ली के निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं. देश के किसी दूसरे नगरीय प्रशासक को ऐसी वैधता नहीं है. उन्हें यह साबित करना है कि भारत का राजनीतिक नेतृत्व ऐसे फ़ैसले लेने के योग्य है, जिनके दूरगामी परिणाम होंगे. वह अपने असाधारण बहुमत को अपने अलोकप्रिय फ़ैसले के ख़िलाफ़ ढाल बना सकते हैं. एक अच्छा नेता सत्ता का उपयोग जनता की भलाई के लिए करता है. वह ऐसे फ़ैसले भी लेता है, जिन्हें जनता की मंज़ूरी नहीं होती. केजरीवाल अपने पहले कार्यकाल में नाकाम रहे थे. उनके लिए अच्छा यह होगा कि वह अपने दूसरे कार्यकाल में बेहतर काम करें, अन्यथा फिर तीसरा कार्यकाल नहीं मिलेगा. अगर वह कामयाब होते हैं, तो देश में वैकल्पिक नेतृत्व की जगह भर सकते हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

मोदी सरकार वक्फ बोर्ड को नहीं दे रही है पैसा

आखिर वक्फबोर्ड क्या है? वक्फ एक अरबी शब्द है, जिसका मतलब होता है कि वह प्रॉपर्टी जो अल्लाह के नाम पर दान दी गई है. ताकि उसका इस्तेमाल गरीबों की भलाई के लिए हो सके. भारत में वक्फ संस्थाओं का वजूद 800 वर्षों से है. सरकार मदरसों के आधुनिकीकरण की बात खूब करती है, लेकिन मदरसों को जारी की जाने वाली राशि को कम कर दिया है. मोदी सरकार पर अक्सर मुस्लिमों से भेदभाव के आरोप लगते रहते हैं. ऐसे में मदरसों को कम धनराशि आवंटित करने के कारण निराशा का माहौल है...

धर्मेन्द्र कुमार सिंह feedback@chauthiduniya.com

मोदी सरकार अल्पसंख्यकों, खासकर मुस्लिमों, के हितों की बातें खूब करती है लेकिन असलियत में केंद्र सरकार का यह दावा खोखला साबित हो रहा है. मोदी सरकार ने अपने डेढ़ साल के कार्यकाल में मुसलमानों के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है. नरेन्द्र मोदी को मुस्लिमों में बनी उनकी खराब और अविश्वसनीय छवि को सुधारने का बड़ा मौका प्रधानमंत्री के रूप में मिला था, लेकिन मुस्लिमों के प्रति उनके कार्यों को देखकर लगता है कि वे अपनी छवि नहीं सुधारना चाहते हैं.

भाजपा के नेताओं और मंत्रियों द्वारा मुसलमानों के बारे में बेहद आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं, उस पर भी प्रधानमंत्री चुप रहे. प्रधानमंत्री कहते तो जरूर हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन यह केवल एक नारा बनकर रह गया है. यह बात लोकसभा में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर से पता चलती है. नकवी द्वारा लोकसभा में दिए गए जवाब से पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए की मोदी सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड की चल रही योजनाओं के लिए कोई धनराशि जारी नहीं की गई और उन योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया है.

मुख्तार अब्बास नकवी ने उदयपुर के भाजपा सांसद अर्जुन लाल मीणा द्वारा लोकसभा में पूछे गए एक सवाल का जवाब दिया कि दो योजनाओं के लिए सरकार से राशि आवंटित की जातीहै. इनमें राज्यों के वक्फ बोर्ड्स के अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण और राज्य वक्फ बोर्ड के सुदृढ़ीकरण की योजना शामिल है. इसके अलावा शहरी वक्फ संपत्तियों के विकास के अन्तर्गत वक्फबोर्ड को धन प्रदान किया जाता है. अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा जो आंकड़ा उपलब्ध कराया गया उससे पता चला कि मोदी सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड को अभी तक कोई धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई. जबकि इससे पहले यूपीए सरकार ने कम से कम राज्य वक्फ बोर्ड्स के अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण के लिए 89.70 लाख और 40.09 लाख रुपये क्रमश: 2012–2013 और 2013–2014 के लिए जारी किए थे.

हालांकि वर्ष 2014–2015 के लिए कोई धन राशि आवंटित नहीं की गई है. मंत्रालय ने कहा है कि कम्प्यूटरीकरण के कार्य को आउटसोर्स

मोदी सरकार को अल्पसंख्यक हितों की न सिर्फ बात करनी चाहिए बल्कि उसके लिए सकारात्मक कदम भी उठाने चाहिए जिससे इस तबके में यह विश्वास कायम हो सके कि वे इस देश के उसी प्रकार नागरिक हैं जैसे बहुसंख्यक तबका है.

किया है और केंद्रीय वक्फ बोर्ड परिषद द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है. जहां तक दूसरी योजना राज्य वक्फ बोर्ड को सुदृढ़ीकरण करने का संबंध है, सरकार ने इस साल के लिए भी कोई धन नहीं जारी किया है, जो चिंता की बात है. जहां यूपीए सरकार ने 2014–2015 के लिए आवंटित 7 करोड़ रुपये के बदले 3.95 करोड़ रुपये जारी किए थे. मंत्रालय ने दावा किया है कि यह योजना 2014–2015 में शुरू की गई थी, लेकिन लोकसभा में 5 अगस्त 2015 को दिए जवाब से पता चलता है कि इस योजना के लिए यूपीए सरकार ने 5 करोड़ रुपये और 7 करोड़ रुपये क्रमश: 2012–2013 एवं 2013–2014 के लिए आवंटित किए थे, हालांकि इस निधि का पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया गया.

गैर योजना शहरी वक्फ संपत्तियों के विकास, जिनका कार्यान्वयन केंद्रीय वक्फ परिषद द्वारा किया जा रहा है. उसके लिए पिछली सरकार की तुलना में मोदी सरकार ने बहुत कम धन आवंटित किया है. केरल और कर्नाटक ऐसे दो राज्य हैं, जिनको इस योजना के तहत अधिक लाभ मिला है. इस रिपोर्ट से मोदी सरकार के दावों की सच्चाई का पता चलता है कि वक्फ बोर्ड को उसकी योजनाओं के लिए कोई धन प्रदान नहीं किया गया, बल्कि यूपीए सरकार द्वारा जो धनराशि प्रदान की गई थी, उसमें भी कटौती कर दी.

आखिर वक्फबोर्ड क्या है? वक्फ एक अरबी शब्द है, जिसका मतलब होता है कि वह प्रॉपर्टी जो अल्लाह के नाम पर दान दी गई है. ताकि उसका इस्तेमाल गरीबों की भलाई के लिए हो सके. भारत में वक्फ संस्थाओं का वजूद 800 वर्षों से है.

इसी प्रकार सरकार मदरसों के आधुनिकीकरण की बात खूब करती है, लेकिन मदरसों को जारी होने वाली धनराशि को कम कर दिया है. मोदी सरकार पर समय-समय मुस्लिमों से भेदभाव के आरोप लगते रहते हैं. जहां तक वक्फ बोर्ड की बात है, तो उसका भी इस्तेमाल गरीबों के लिए किया जाता है. मोदी सरकार को चाहिए कि वक्फ बोर्ड को दी जाने वाली धनराशि को रोकने बजाय उसे जारी करे. ■

feedback@chauthiduniya.com

तस्वीरों में यह सप्ताह

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय / सुनील मल्होत्रा*

● नई दिल्ली में आयोजित ऊर्जा महोत्सव (उमंग 2015) में स्कूली बच्चों के साथ राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी.

● दिल्ली सचिवालय में सीबीआई के छापे के बाद पत्रकारों को संबोधित करते उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया.

● दिल्ली के शकूरबस्ती में रेलवे द्वारा झुग्गियां गिराने का संसद के बाहर गांधी प्रतिमा के सामने विरोध करते टीएमसी और आप सांसद.

● जंतर मंतर पर केंद्र सरकार द्वारा श्रम कानूनों में बदलाव का विरोध करता भारतीय ट्रेड यूनियन.

● सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के खिलाफ धरना देते रेलवे लोको कर्मचारी.

● कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के जन्मदिन पर कांग्रेस मुख्यालय पर खुशी मनाते पार्टी कार्यकर्ता.

डोनाल्ड ट्रम्प मुस्लिम विरोधी टिप्पणी के कारण अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचनाओं के शिकार हुए हैं. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ट्रंप की तुलना हिटलर से की जा रही है. लोग ट्रंप और हिटलर की नीतियों की सूची बना कर तुलना कर रहे हैं. हालांकि इन सारे मामलों पर डोनाल्ड ट्रम्प का कहना है कि वह जो कुछ भी कर रहे हैं, वह मुसलमानों की भलाई के लिए कर रहे हैं. ट्रम्प ने कहा कि वह सबसे कम नस्लवादी हैं. वे कहते हैं कि मेरे कई सारे मुसलमान दोस्त भी मेरे इस बात से सहमत हैं कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, वह मुस्लिमों की भलाई के लिए कर रहा हूं. मेरे मित्र मुझसे कहते हैं कि तुमने (डोनाल्ड) जो विचार मेरे सामने रखे हैं, वह बहुत ही शानदार और कमाल के हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव

ट्रम्प का मुस्लिम कार्ड

अमेरिकी राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रम्प ने पिछले दिनों मुसलमानों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध को लेकर एक ऐसा विवादित बयान दिया, जिससे पूरे विश्व में हंगामा मच गया. पहली नजर में यह मालूम होता है कि ट्रम्प ने यह बयान बहुत सोच-समझकर दिया है, क्योंकि इस बयान के बाद वे अपने प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवारों के बीच सबसे आगे हो गए हैं. सवाल यह है कि अगर ट्रम्प राष्ट्रपति चुनाव जीत जाते हैं तो बतौर अमेरिकी राष्ट्रपति मुसलमानों को लेकर उनका रवैया क्या इसी तरह का होगा या उनका आज का विवादित बयान सिर्फ चुनाव जीतने का शिगूफा भर है?

राजीव रंजन

अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होने में अभी समय बाकी है, लेकिन उम्मीदवारों में अभी से ही आरोप-प्रत्यारोप, विवादित बयानों के द्वारा प्रसिद्धि हासिल करने का प्रयास जारी है. ताजा मामले में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रम्प ने कैलिफोर्निया में दो मुसलमानों द्वारा की गई हत्याओं के बाद यह बयान दिया है कि अमेरिका में मुस्लिमों के प्रवेश पर पाबंदी लगा देनी चाहिए. उनके इस बयान के बाद पूरी दुनिया में हंगामा मच गया है. हालांकि ट्रम्प के इस बयान का राष्ट्रपति के अन्य दावेदारों और मुस्लिमों द्वारा विरोध शुरू हो गया है. सच्चाई तो यह है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करने से पहले से ही विवादास्पद बयान देने शुरू कर दिए थे. जानकार इसे हर वक्त सुर्खियों में बने रहने का तरीका मानते हैं. ट्रम्प का विवादों से कितना गहरा नाता रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कभी वे अमेरिकी राष्ट्रपति पर विवादित बयान देते हैं तो कभी इमिग्रेशन पर तो कभी महिलाओं को लेकर वे उल्टे बयान दे देते हैं, कभी गैर अमेरिकियों को अमेरिका में नौकरी नहीं देने की बात करते हैं तो कभी मुसलमानों को लेकर चर्चा बटोरने की कोशिश करते हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा का भी कहना है कि ट्रम्प लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते हैं और उन्हें इतना भर ही आता है. गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने डोनाल्ड ट्रम्प के बयान की निंदा करते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों का समर्थन कीजिए. ट्रम्प के इस बयान का असर दुबई में भी देखने को मिला. दुबई रियल एस्टेट फर्म की 6 अरब डॉलर की गोल्फ इमारत से डोनाल्ड ट्रम्प का नाम और उसका चित्र हटा दिया गया. अमेरिका में मुसलमानों की एंट्री पर रोक लगाने की मांग करने वाले डोनाल्ड ट्रम्प पर सऊदी के प्रिंस ने भी निशाना साधा है. ट्रम्प के बयान से नाराज प्रिंस अलवालीद बिन तलाल ने ट्विटर पर उन्हें अमेरिका के लिए शर्मिंदगी करार दिया. जवाब में ट्रम्प ने प्रिंस को नशेड़ी कहा. ट्रम्प के बयान का जवाब अमेरिकी राष्ट्रपति के रिपब्लिकन उम्मीदवार टेड क्रूज ने भारत की मिसाल देकर दी और कहा कि भारत में करोड़ों मुसलमान बिना किसी समस्या के शांतिपूर्ण ढंग से रहते हैं. हालांकि भारत में ट्रम्प के बयान को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, लेकिन यह बयान अगले साल अमेरिका में होने वाले चुनाव में अहम साबित हो सकते हैं.

डोनाल्ड ट्रम्प मुस्लिम विरोधी टिप्पणी के कारण अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर भी आलोचनाओं के शिकार हुए हैं. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ट्रंप की तुलना हिटलर से की जा रही है. लोग ट्रंप और हिटलर की नीतियों की सूची बना कर तुलना कर रहे हैं. हालांकि इन सारे मामलों पर डोनाल्ड ट्रम्प का कहना है कि वह जो कुछ भी कर रहे हैं, वह मुसलमानों की भलाई के लिए कर रहे हैं. ट्रम्प ने कहा कि वह सबसे कम नस्लवादी हैं. वे कहते हैं कि मेरे कई सारे मुसलमान दोस्त भी मेरे इस बात से सहमत हैं कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, वह मुस्लिमों की भलाई के लिए कर रहा हूं. मेरे मित्र मुझसे कहते हैं कि तुमने (डोनाल्ड) जो विचार मेरे सामने रखे हैं, वह बहुत ही शानदार और कमाल के हैं. ट्रंप कहते हैं कि वह पश्चिम एशिया और वहां के लोगों से बहुत प्यार करते हैं. जब उनसे यह पूछा गया कि क्या वह कट्टर हैं या उन्हें इस्लामोफोबिया है तो ट्रंप ने इसके जवाब में कहा कि आप अब तक जितने लोगों से मिले होंगे, मैं उनमें सबसे कम नस्लवादी हूं. ट्रम्प की पॉपुलैरिटी भी कम नहीं है. मशहूर पत्रिका टाइम ने इस साल पर्सन ऑफ द ईयर के लिए जिन अंतिम आठ दावेदारों का चुनाव किया था, उनमें डोनाल्ड ट्रम्प शामिल थे. टाइम पत्रिका के संपादकों ने 2015 पर्सन ऑफ द ईयर के लिए अंतिम आठ दावेदारों को सूचीबद्ध किया था. मीडिया और सोशल साइट पर ट्रम्प के इस बयान पर मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है. सोशल साइट ट्विटर और फेसबुक पर लोग ट्रम्प को विभिन्न तरह की उपमाओं से नवाज रहे हैं तो कुछ लोग यहां तक कह रहे हैं कि हमारे देश में ही मूर्ख नेता नहीं हैं, ये ट्रम्प ने अपने बयान से साबित कर दिया है. ट्रम्प अपने इस बयान के बाद भी अपने प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवारों की तुलना में मशहूर हैं. खुद ट्रम्प ने फेसबुक पर लिखा कि उन्होंने एक सर्वे करवाया है, जिसमें उनके 68 फीसदी समर्थकों ने कहा कि अगर ट्रम्प रिपब्लिकन छोड़ भी दें तो वह उन्हें ही वोट करेंगे. न्यू हैंपशायर विश्वविद्यालय के सर्वेक्षण केंद्र की तरफ से कराए सीएनएन/डब्ल्यूएमयूआर जनमत सर्वेक्षण में सामने आया है कि राष्ट्रपति पद के अन्य रिपब्लिकन दावेदारों पर ट्रम्प की बढ़त और अधिक हो गई है. ट्रम्प रिपब्लिकन पार्टी में राष्ट्रपति पद के दावेदारों में सबसे आगे चल रहे हैं. मुस्लिमों के अमेरिका में प्रवेश पर रोक लगाने की मांग करने वाले ट्रंप ने पार्टी छोड़ने तक की धमकी दी और कहा कि अगर वह पार्टी छोड़ भी दें तो चुनाव जीत जाएंगे. आलोचनाओं से बेपरवाह ट्रंप ने अपने बयान को आतंकवाद के खिलाफ एक अस्थाई कदम बताया. उन्होंने अपनी बात के पक्ष में पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का भी सहारा लेते हुए कहा कि ये वो राष्ट्रपति हैं, जिनका सभी बहुत सम्मान करते हैं. 1940 के दशक में देश विश्व युद्ध का सामना कर रहा था और आज चरमपंथी इस्लाम से युद्ध का सामना कर रहा है. हमें एक बेहद गंभीर समस्या पर हाथ डालना होगा. अगर हम सख्ती, चुस्ती नहीं दिखाएंगे तो और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर होंगे. ट्रम्प के इस बयान पर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है. चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्रंप की टिप्पणी पर कोई सीधी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की और कहा कि यह अमेरिका का आतंरिक मामला है और वह इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते. ब्रिटेन में डोनाल्ड ट्रंप के देश में प्रवेश पर रोक की मांग की जा रही है. चूंकि इस अभियान में एक लाख से अधिक लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं, इसलिए अब इस पर ब्रिटिश संसद में चर्चा होगी. ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन के प्रवक्ता ने ट्रंप टिप्पणी को विभाजनकारी बताया था.

ट्रम्प के बयान और इस पर लोगों की प्रतिक्रिया से यह सवाल हमारे सामने आता है कि क्या ट्रम्प इस तरह के विवादित और अव्यवहारिक बयान सोच-समझ कर दे रहे हैं, ताकि वे चुनाव में जीत दर्ज कर सकें या इस तरह के बयान को लेकर वे गंभीर हैं और अगर वे आनेवाले समय में अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाते हैं तो मुसलमानों के प्रवेश पर वे सचमुच प्रतिबंध लगाएंगे?

ट्रम्प के बयान और इस पर लोगों की प्रतिक्रिया से यह सवाल हमारे सामने आता है कि क्या ट्रम्प इस तरह के विवादित और अव्यवहारिक बयान सोच-समझ कर दे रहे हैं, ताकि वे चुनाव में जीत दर्ज कर सकें या इस तरह के बयान को लेकर वे गंभीर हैं और अगर वे आनेवाले समय में अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाते हैं तो मुसलमानों के प्रवेश पर वे सचमुच प्रतिबंध लगाएंगे या उनके यह बयान चुनाव जीतने का सिर्फ शिगूफा भर है? ■

feedback@chauthiduniya.com

अंतरराष्ट्रीय अपराधी

लैलुरी बनाती थी नौकरों को अपनी दरिंदगी का शिकार

मैरी डेल्फिन लैलुरी का जन्म सन् 1775 में न्यू ऑर्लेअंस में हुआ. मैरी डेल्फिन 19 वीं शताब्दी की खूंखार सीरियल किलर थी. हमेशा से ही डेल्फिन लैलुरी का बड़े लोगों में उठना-बैठना रहता था, लेकिन उसका असली चेहरा लोगों के सामने तब आया, जब उसकी तीन मंजीली हवेली में आग लगी और उसके घर से दर्दनाक हालातों में नौकर मिले, जिसे देखकर लोगों की रूह कांप गई .

मैरी डेल्फिन बचपन से ही रसूखदार परिवार में पढ़ी-बढ़ी. उसके लंबे घने बाल और मदहोश करने वाली आखें हर किसी को उसका मूरीद बान देती थीं. पहली शादी से उसे एक बेटी हुई और पहले पति की मौत केबाद सन् 1808 में मैरी डेल्फिन ने जीन बलांक से शादी की, जो पेशे से बैंकर, व्यापारी,वकील और विधायक था. शादी के वक्त जीन ने अपने परिवार केलिए न्यू ऑर्लेअंस में 409 शाही मार्ग पर हवेली खरीदी जो आगे चलकर विला ब्लैंक से जाना गया. डेल्फिन की जीन से चार बच्चे हुए. सन् 1816 में जीन की मौत के बाद डेल्फिन ने अपने से छोटी उम्र के लियोनार्ड लुइस निकोलस लैलुरी से शादी रचाई. सन् 1831 में डेल्फिन ने 409 शाही मार्ग को छोड़कर 1140 शाही मार्ग पर घर खरिदा, जिसे डेल्फिन ने तीन मंजिला बनाया और न्यू ऑर्लेअंस के उच्च समाज में अपने पति और बच्चों केसाथ रहने लगी. न्यू ऑर्लेअंस केतीन मंजीला महल में डेल्फिन लैलुरी की शानदार पार्टियों की चर्चा किए बिना कोई नहीं रहता था. लेकिन कोई नहीं जानता था कि डेल्फिन के खूबसूरत सूरत के पीछे इतना भयानक चेहरा भी छिपा हुआ है. डेल्फिन के गुस्से का आलम यह था कि अगर बाल बनाते वक्त किसी नौकरानी से उसका हल्का सा कोई बाल खिंच जाता तो वह उस नौकरानी को बागीचे में ले जाकर निर्दयता से इतना मारती कि देखने वालों की आखों से आंसू छलक आते थे. नौकरों में डेल्फिन का इतना खौफ होता था कि कहीं मैडम डेल्फिन को गलती का पता नहीं चल जाए, इसलिए एक नौकरानी ने तो तीन मंजिला महल की खिड़की से ही छलांग लगा दी थी. सन् 1834 में डेल्फिन के घर में जब आग लगी, तब आग बुझाने आए बचावकर्मियों को घर से सड़ी हुई लाशें मिलीं, जिन्हें देखकर हर कोई अवाक रह गया. जब पुलिस ने डेल्फिन के घर की तलाशी लेनी शुरू की तो उन्हें जंजीरों में जकड़े हुए नौकर और मुंह सिली हुई नौकरानियां मिलीं. डेल्फिन की दरिंदगी का मंजर यहीं खत्म नहीं हुआ. तलाशी में तड़पते हुए अधमरे नौकर पिंजरों में मिले और कई मनुष्य के अंग उसके घर पर पाए गए. नौकरों की दर्दनाक और भयानक स्थिती को देखकर डेल्फिन लैलूरी केप्रति स्थानीय लोगों जबरदस्त आक्रोश था. डेल्फिन लैलूरी को आखिरकार पुलिस को चकमा देकर अपने पति केसाथ पेरिस भाग गई और वहां शिकार करते हुए शूअर के हमले में मारी गई. ■

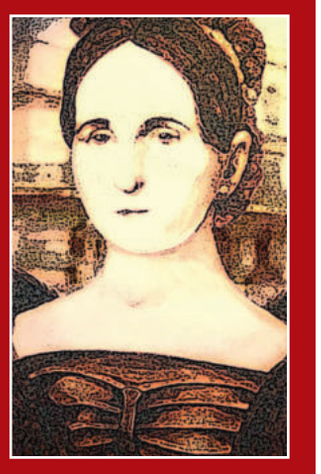

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

संक्षिप्त ख़बरें

तुर्की की बोट पर गोलियों की बौछार

रूस ने तुर्की की एक बोट पर एजियन सागर में हमला किया था.मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रूस ने वॉरशिप स्मेत लाइवी से तुर्की की बोट पर गोलियां बरसाई थीं. रूस का दावा है कि उसने ऐसा वॉर्निंग देने केलिए किया था. 500 मीटर नजदीक आ पहुंची तुर्की की बोट से टक्कर रोकने केलिए उसे गोलियां चलानी पड़ीं थीं. रूस ने अपनी सफाई में कहा कि एजियन सागर में मछली पकड़ने वाली तुर्की की एक बोट ने हमारे जंगी जहाज की वॉर्निंग का कोई जवाब नहीं दिया.तुर्की की बोट वॉरशिप से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर थी, जिसके बाद वॉरशिप को गोली चलानी पड़ी.गोली चलाते ही तुर्की की बोट ने रास्ता बदल लिया. रूस और तुर्की में काफी समय से तनाव बना हुआ है, क्योंकि तुर्की के एफ-16 फाइटर प्लेन पर 24 नवंबर को रूस के एसयू-24 एयरक्राफ्ट को गिराने का आरोप लगा था. तुर्की ने कहा कि रूस ने उसके एयरस्पेस के नियमों का उल्लंघन किया है. रूस ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि एसयू-24 सीरियन एयरस्पेस में था. इसके बाद से दोनों देशों के बीच टेंशन की लकीर खिंच गई है. रूस और तुर्की में सीरिया को लेकर भी विवाद चल रहा है. जहां तुर्की, अमेरिका और फ्रांस एक साथ हैं. वहीं, रूस खुद आईएसआईएस पर हमले कर रहा है, लेकिन वह सीरिया के राष्ट्रपति असद का साथ भी दे रहा है. तुर्की ने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को नकार दिया है और रूस ने तुर्की पर कई इकोनॉमिक सैंक्शन्स भी लगा दिए हैं. इन सैंक्शन्स में इम्पोर्ट और ट्रैवल भी शामिल हैं. पिछले हफ्ते तुर्की मीडिया ने रशियन सोल्जर की एक वॉरशिप पर रॉकेट लॉन्चर लिए हुए फोटो छापी थी और इसे लेकर भी दोनों देशों के बीच बहस हुई थी. ■

इजरायली पीएम का कुत्ता राजनेताओं को काटता है

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पालतू कुत्ते पर कानून के तहत 10 दिनों तक निगरानी रखी गई थी, क्योंकि प्रधानमंत्री नेतन्याहू के कुत्ते ने कई लोगों को काट लिया था. इसमें सांसद और मिनिस्टर भी शामिल थे. कुत्ते को नजरबंद करने की जानकारी नेतन्याहू ने खुद फेसबुक के एक पोस्ट के द्वारा दी थी. पीएम नेतन्याहू ने फेसबुक पोस्ट पर लिखा था कि हमें न चाहते हुए भी इस दस साल के कुत्ते को देना पड़ा. अब कानून के तहत कुत्ते पर अगले 10 दिनों तक निगरानी रखी जाएगी. मुझे उम्मीद है कि मुझे मेरा कुत्ता वापस मिल जाएगा और तब तक वह काफी बदल चुका होगा. हाल ही में एक प्रोग्राम के दौरान इजरायल के पीएम के कुत्ते ने डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर समेत दो गेस्ट्स को काट लिया था. यहूदी फेस्टिवल हन्नुकाह के मौके पर पीएम के रेजिडेंस पर पार्टी दी गई थी और इसी दौरान कुत्ते ने नेतन्याहू की लिकुड पार्टी से सांसद शरीन हॉस्केल को भी काट लिया था. जानकारी के मुताबिक, पीएम नेतन्याहू का बेटा इसी साल जुलाई में एक रेस्क्यू होम से इस कुत्ते को लाया था. प्रधानमंत्री नेतन्याहू का यह कुत्ता अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी समेत कई हस्तियों से मिल चुका है. ■

सऊदी चुनाव में महिलाओं का परचम

सऊदी अरब में पहली बार महिलाओं ने चुनाव लड़ा और जीता है. सबसे पहला नतीजा मुस्लिमों के सबसे पवित्र स्थान मक्का से आया था.मक्का के मेयर ओसामा अल बार ने बताया कि पास के गांव मदरकाह में सलमा बिंत हिजब अल-ओतीबी ने जीत हासिल की है. इसी के साथ, वे देश की पहली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बन गई हैं. आंकड़ों के मुताबिक, 20 महिलाएं चुनाव जीत चुकी हैं. सऊदी अरब केदूसरे सबसे बड़े शहर जेद्दा की एक सीट पर महिला उम्मीदवार लामा अल-सुलेमान ने भी जीत दर्ज कराई है. रूढ़िवादी देश सऊदी अरब में पहली बार महिलाओं को रिप्रेजेंटेटिव बनने और वोट डालने का हक मिला था.चुनाव के बाद सऊदी अरब सिनेमा कमेटी ने एलान किया है कि देश में जल्द ही सिनेमा थिएटर खुलेगा. राजधानी रियाद में इसे बनाने के लिए एमओयू पर साइन भी किया गया है. देश में लंबे वक्त से कई संगठनों ने सिनेमा थिएटर खोले जाने के लिए आंदोलन छेड़ रखा था. जेद्दा से जीती लामाअल सुलेमान कहती हैं कि मैं महिलाओं के हक के लिए चुनाव में खड़ी हुई थी. जीत से यह भरोसा मिला है कि हमें समाज में बराबरी मिलेगी. सऊदी अरब में 2100 सीटों के लिए हुए चुनाव में 7000 उम्मीदवार थे. इनमें 979 महिलाएं थीं.सऊदी अरब में राजशाही है. यहां सिर्फ निकाय चुनाव ही होते हैं. पहली बार 2005 में चुनाव हुए थे. 13.5 लाख पुरुष वोटरों के मुकाबले 1.31 लाख महिलाओं ने वोटिंग केलिए रजिस्ट्रेशन कराया था. किंग अब्दुल्ला ने 2011 में महिलाओं को चुनाव लड़ने और वोटिंग की इजाजत दी थी. ■

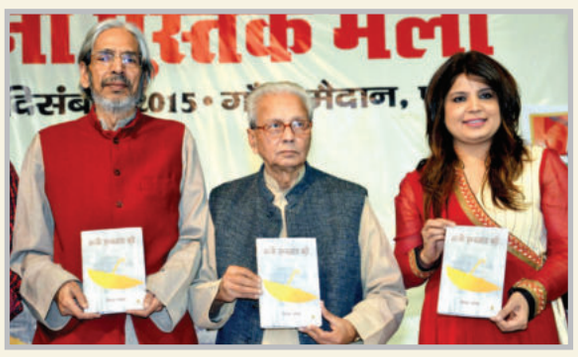

दिनकर जी जैसे बड़े कवि को प्रगतिशील आलोचकों ने वो स्थान नहीं दिया जिसके वो हकदार थे. निराला के उन लेखों को सायास छुपा दिया गया जो कि उन्होंने कल्याण पत्रिका में लिखे थे. निराला के कल्याण में छपे लेखों को दबा देने के पीछे की मंशा सिर्फ इतनी नजर आती है कि उनका वामपंथ की तरफ के झुकाव को उभार कर स्थापित किया जा सके. वरिष्ठ पत्रकार अच्युतानंद मिश्र की किताब –पत्रों में समय संस्कृति–से यह बात साफ है कि निराला जी ने कल्याण पत्रिका में हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के अनुरोध पर कई लेख लिखे थे.

कविता की मंच पर वापसी हो

अनंत विजय

इन दिनों पूरे देश में साहित्य उत्सवों की धूम है, दिल्ली से लेकर पटना तक, बंगलुरु से लेकर मुंबई तक. दरअसल हर साल दिसंबर से लेकर फरवरी तक ज्यादातर साहित्यिक मेलों का आयोजन होता है. इन साहित्यिक आयोजनों में विवादों को सायास उठाया जाने लगा है, बावजूद इसके कुछ आयोजनों में सार्थक विमर्श भी होते हैं. साहित्यिक प्रवृत्तियों के बारे में वरिष्ठ लेखकों की राय सामने आती है. साहित्य पर मौजूदा या आसन्न खतरों पर बात की जाती है. पटना में जारी पटना पुस्तक मेला के जनसंवाद कार्यक्रम में एक सत्र था– नई सदी की कविताई. इस सत्र में युवा कवियों– राकेश रंजन, नताशा, संजय कुंदन, और स्मिता पारिख ने अपनी कविताओं का पाठ किया. लेकिन असली बात हुई कविता पाठ के बाद जब इन युवा कवियों को सुनने के बाद हिंदी के वरिष्ठ कवि आलोक धन्वा से इस विषय पर बोलने का आग्रह किया गया. आलोक जी ने कविता को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने इशारों में यह सवाल उठाया कि किस वजह से कविता आज पाठकों से दूर होती जा रही है और पाठकों को कविता की ओर लाने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए. इस संदर्भ में आलोक धन्वा ने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं और उनके मंच पर उसके पाठ करने से पैदा होनेवाले प्रभाव का उल्लेख किया. आलोक धन्वा ने रामधारी सिंह दिनकर की मशहूर कविताओं का पाठ भी किया. उन्होंने दिनकर की मशहूर काव्य कृति रश्मिरथी के उस प्रसंग को बताया जहां कर्ण का निकट अंत आ गया था और वो शल्य से कहता है कि घोड़ों को तेज चलाकर उस जगह पर ले चले जहां कृष्ण और अर्जुन मौजूद हैं. कर्ण के रथ का पहिया रक्त से पंकिल जमीन में इस कदर फंसा गया कि वो कर्ण के निकाले भी नहीं निकल रहा था. अपनी काव्य कृति रश्मि रथी में दिनकर इस स्थिति को यूं कहते हैं –महि डोली/ससिल–आगार डोला/भुजा के जोर से संसार डोला/न डोला, किंतु , जो चक्का फंसा था/ चला वह जा रहा नीचे धंसा था. इस स्थिति को देखते हुए युद्ध के मैदान में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यही मौका है और कर्ण का वध कर दो. अर्जुन यहां भी तर्क करने लग जाते हैं कि ये उचित नहीं होगा क्योंकि कर्ण विरथ है. कृष्ण एक बार फिर से अर्जुन को समझाते हैं जिसको दिनकर अपनी कविता में यूं व्यक्त करते हैं – खड़ा है देखता क्या मौन भोले?/शरासन तान, बस, अवसर यही है/घड़ी फिर और मिलने को नहीं है/विशिख कोई गले के पार कर दे /अभी ही शत्रु का संहार कर दे. आलोक धन्वा ने कहा कि दिनकर जब इन कविताओं का पाठ करते थे तो ऐसा प्रतीत होता था कि युद्ध का वो पूरा प्रसंग पाठकों की आंखों के सामने जीवंत हो उठा है. आलोक जी भी जब दिनकर की कविताओं का पाठ कर रहे थे तो पूरे सभागार में सन्नाटा छाया था और कविता रसिक श्रोता मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे. आलोक धन्वा का मानना था कि जब कविताएं कवियों से सुनी जाती हैं तो उनका एक अलग प्रभाव पाठकों के मन पर पड़ता है. कविता पाठकों को अपने साथ बहाने लग जाती है. उनके मुताबिक कवि और कविता को पाठकों के साथ सीधे संवाद करना चाहिए और यह कविता पाठ से ही संभव है. अपनी बात को मजबूती देने के लिए आलोक धन्वा ने हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद आदि की कविताओं को उद्धृत किया. बच्चन की कविताओं की लोकप्रियता की वजह भी उनका पाठ था. आलोक धन्वा के पहले मुंबई की कवयित्री स्मिता पारिख के संग्रह – नज्में इंतजार की – का विमोचन करते हुए हिंदी के वरिष्ठतम कवियों में से एक केदारनाथ सिंह ने भी कुछ इसी तरह की बात की थी. केदार जी ने कहा कि कविता लिखे से ज्यादा पढ़े जाने की चीज है. पहले तो वहां मौजूद दर्शकों को लगा कि केदार जी पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं लेकिन बाद में उन्होंने साफ किया कि कवि के लिए कविता लिखना जितना महत्वपूर्ण है पाठकों के लिए उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कवि उन कविताओं का पाठ करे. उन्होंने कहा कि स्मिता की कविताएं मंचों पर पढ़ी जानी चाहिए.

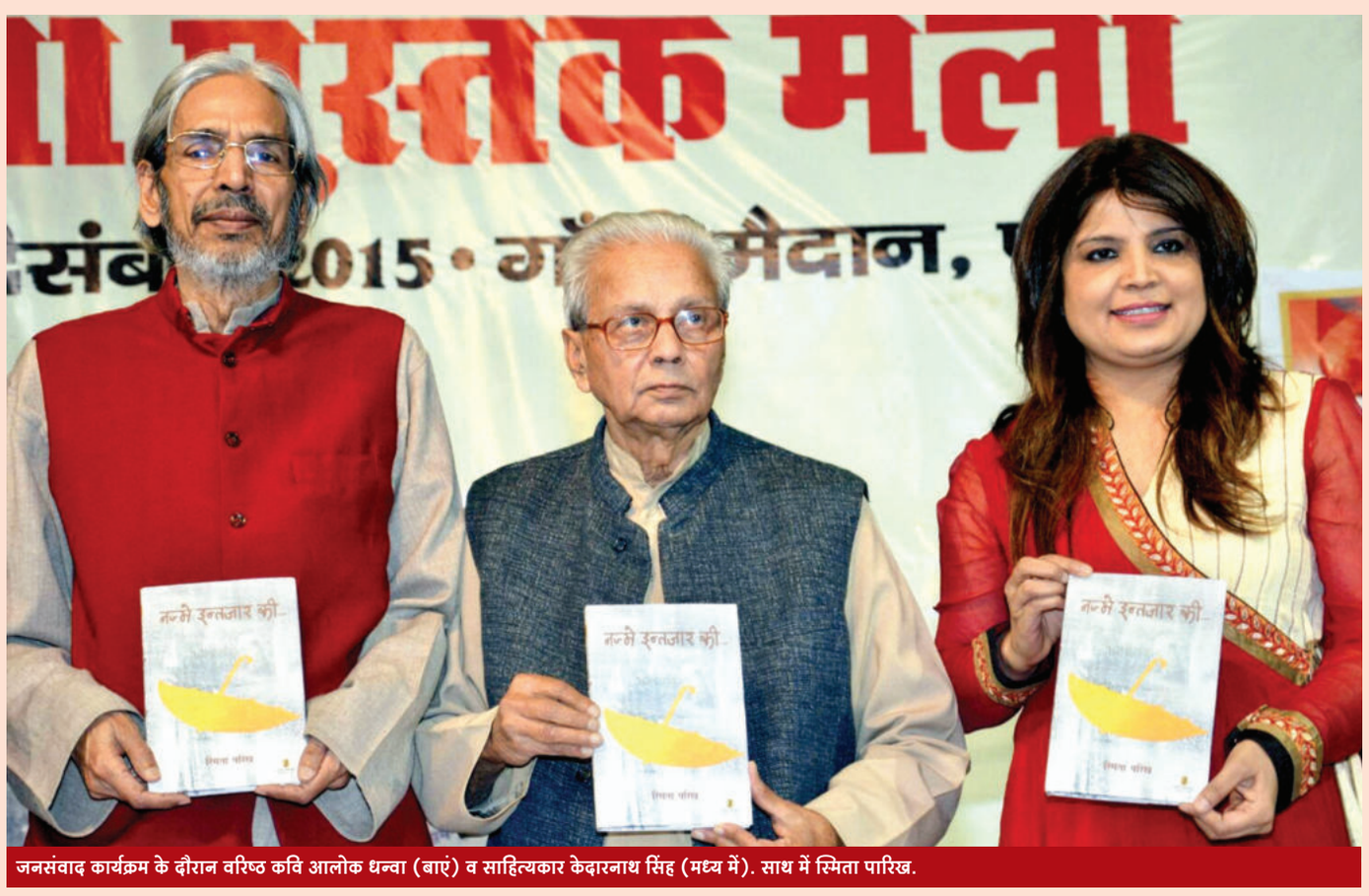

जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ कवि आलोक धन्वा (बाएं) व साहित्यकार केदारनाथ सिंह (मध्य में). साथ में स्मिता पारिख.

मंच से कविता पाठ की संस्कृति का लगभग खत्म हो जाने का हिंदी कविता को बहुत नुकसान हुआ. साठ के अंतिम वर्षों या सत्तर के दशक की शुरुआत के बाद मंच पर कविता पाठ करनेवालों कवियों को मंचीय कवि कहकर हेय दृष्टि से देखे जाने की प्रवृत्ति ने जोर पकड़ा. इसका नतीजा यह हुआ कि बड़े पैमाने पर आयोजित किए जानेवाले कवि सम्मेलनों में बड़े कवियों ने जाना पहले कम किया और फिर बंद कर दिया. क्योंकि माहौल ही ऐसा बना दिया गया कि जो मंच पर कविता पाठ करेगा उसको प्रतिष्ठा नहीं मिल सकती है. इस प्रचार से कुछ तुकबंदी करनेवाले कवियों की पौ बारह हो गई. संजीदगी से कविताई करनेवाले नेपथ्य में चले गए और कविता के नाम पर चुटकुले सुनानेवाले बढ़ते गए.

कविता को लेकर कई वरिष्ठ कवियों और लेखकों ने चिंताएं व्यक्त की हैं. कवि नरेश सक्सेना ने भी कुछ दिनों पहले अपने एक साक्षात्कार में कहा था कि एक छोटी लाइन और एक बड़ी लाइन लिखकर लोग समझते हैं कि वो कवि हो गए हैं. उनके मुताबिक इस तरह की कविताओं ने छद्मशास्त्र को भी निगेट किया. इसी तरह की बात कई वरिष्ठ कवि लेखक अलग–अलग मंचों पर अलग–अलग तरीके से कह चुके हैं. इन कवियों की चिंताओं के केंद्र में कविता का पाठकों से दूर होते जाना है. केदार नाथ सिंह जब यह कहते हैं कि कविता लिखे से ज्यादा पढ़े जाने की चीज है तो वो मंच से कविता पाठ की वकालत करते हुए नजर आते हैं. मंच से कविता पाठ की संस्कृति का लगभग खत्म हो जाने का हिंदी कविता को बहुत नुकसान हुआ. साठ के अंतिम वर्षों या सत्तर के दशक की शुरुआत के बाद मंच पर कविता पाठ करनेवालों कवियों को मंचीय कवि कहकर हेय दृष्टि से देखे जाने की प्रवृत्ति ने जोर पकड़ा. इसका नतीजा यह हुआ कि बड़े पैमाने पर आयोजित किए जानेवाले कवि सम्मेलनों में बड़े कवियों ने जाना पहले कम किया और फिर बंद कर दिया. क्योंकि माहौल ही ऐसा बना दिया गया कि जो मंच पर कविता पाठ करेगा उसको प्रतिष्ठा नहीं मिल सकती है. इस प्रचार से कुछ तुकबंदी करनेवाले कवियों की पौ बारह हो गई. संजीदगी से कविताई करनेवाले नेपथ्य में चले गए और कविता के नाम पर चुटकुले सुनानेवाले बढ़ते गए. इससे उस दुष्प्रचार को बल मिला कि मंच पर गंभीर कवि कविता पाठ नहीं करते हैं. बहुत दिन नहीं बीते हैं जब हिंदी की साहित्यिक पत्रिका पाखी में मंचीय कवि कुमार विश्वास का एक साक्षात्कार छपा था तो कविता के मठधीशों और उनके चेलों ने बवाल खड़ा कर दिया था. कुमार को और पाखी के संपादक प्रेम भारद्वाज को इस बाबत सफाई देनी पड़ी थी. कुमार ने तो बेहद तल्ख अंदाज में अपनी बात रखी और साहित्यिक लॉबियों पर सवाल खड़ा कर दिया. यह ठीक है कि कुमार कई बार तुकबंदियां करते हैं लेकिन उनकी कविताओं ने हिंदी कविता को एक नया पाठक वर्ग तो दिया ही है. हिंदी में मंचीय कवि, लुगदी साहित्य, पॉपुलर कल्चर, पॉपुलर सिनेमा आदि शब्द नकारात्मकता के साथ प्रचारित कर दिए गए. ये शब्द उस दौर में नकारात्मक हुए, जिस दौर में हिंदी साहित्य में प्रगतिशीलता, जनवादिता का जोर चल रहा था. इस बात की गंभीरता से पड़ताल होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ कि मंच पर कविता पाठ करने वाले कवियों को मुख्यधारा का कवि नहीं माना गया, बल्कि उनके मूल्यांकन में भी भेदभाव बरता गया. दिनकर जी जैसे बड़े कवि को प्रगतिशील आलोचकों ने वो स्थान नहीं दिया जिसके वो हकदार थे. निराला के उन लेखों को सायास छुपा दिया गया जो कि उन्होंने कल्याण पत्रिका में लिखे थे. निराला के कल्याण में छपे लेखों को दबा देने के पीछे की मंशा सिर्फ इतनी नजर आती है कि उनका वामपंथ की तरफ के झुकाव को उभार कर स्थापित किया जा सके. वरिष्ठ पत्रकार अच्युतानंद मिश्र की किताब –पत्रों में समय संस्कृति–से यह बात साफ है कि निराला जी ने कल्याण पत्रिका में हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के अनुरोध पर कई लेख लिखे थे. उनको सामने आना चाहिए. इस तरह की हरकतों या तिकड़मों का नतीजा यह हुआ कि पाठकों के बीच कविता को लेकर एक संस्कार या पढ़ने की संस्कृति का विकास बाधित हो गया. लंबे समय तक इस पर ध्यान नहीं दिया गया जिसकी वजह से कविता के नए पाठक बनने बंद हो गए. आज हिंदी में कविता की इतनी बुरी गत हो चुकी है कि कोई भी प्रकाशक कविता संग्रह छापने में रुचि नहीं दिखाता है. वरिष्ठ कवियों को भी इस दिक्कत का सामना करना पड़ता है, युवाओं की तो बात ही छोड़ दीजिए. कवियों को पैसे देकर अपनी किताबें छपवानी पड़ रही हैं. अब जब कविता को लेकर साहित्य में इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं तो वरिष्ठ जनों का ध्यान इस ओर गया है जो कि साहित्य में कविता की वापसी के लिए किए जा रहे प्रयत्नों के संकेत के तौर पर देखा जाना चाहिए. लेकिन वरिष्ठ कवियों का इतना कहना भर ही काफी नहीं है उनको मंचों पर जाकर अपनी कविताओं का पाठ कर पाठकों को कविता की ओर वापस लाने का भागीरथ प्रयास करना होगा. अगर वो इस तरह की पहल करते हैं तो युवा कवियों को भी बल मिलेगा और संभव है कि साहित्य में कविता की वापसी हो जाए. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)

anant.ibn@gmail.com

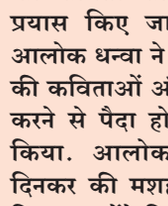

पाठकों की दुनिया

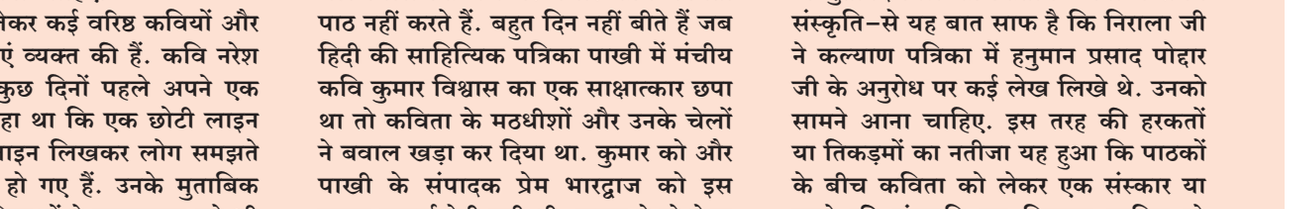

नेपाल समस्या का समाधान

क्या सोच रही है सरकार, यह सोचकर भी आश्चर्य लगता है. भारत सरकार विदेशों में जहां अति सक्रिय उपस्थिति दर्ज कर रही है, संवाद कर रही है. वहीं नेपाल में मचे घमासान पर मरहम लगाने की उसे फुर्सत नहीं है. इस पर सरकार को विचार करना चाहिए और साथ ही नेताओं को ऐसे बयानों से परहेज करना चाहिए कि मधेसी भारतीय हैं या जमीन हमारी है, क्योंकि नेताओं के ऐसे बयानों से नेपाल और भारत के बीच तकरार बढ़ेगी. अगर सरकार सोचती है कि हमें पड़ोसी के घर से क्या मतलब, तो यह खतरनाक होगा.

हमें नेपाल में रह रहे 20 लाख भारतीय परिवारों के बारे में सोचना चाहिए. क्षेत्र के व्यापार–उद्योग धंधे पर जो व्यापक असर आएगा और हजारों घरों के चूल्हे–चौके बंद होने की कगार पर होंगे, उसका क्या? सबसे महत्वपूर्ण यह है कि भारत–नेपाल की 1800 किमी की खुली सीमा पर क्या चिंतन करेंगे? क्योंकि जगजाहिर है कि चीन अपनी नीति के तहत नेपाल पर हावी हो भारत की मोर्चेबंदी की ओर अग्रसर है.

हम बड़े हैं, शक्तिशाली हैं, सामने वाले से कई गुना ज्यादा साधन–संपन्न हैं, तो हमारा दायित्व और भी बढ़ जाता है कि अपने से छोटे व कमजोर को विभिन्न तरीके से मनाने का प्रयत्न करना चाहिए, इससे समस्या का समाधान भी हो सकता है और कद भी बढ़ेगा.

–राजेश कुमार सुन्दरका,
सामाजिक कार्यकर्ता, सीतामढ़ी, बिहार.

दिल्ली में लोकपाल पर बवाल

केजरीवाल सरकार द्वारा लाए गए–लोकपाल बिल पर बवाल मचा है. भ्रष्टाचार–नियंत्रण के लिए लाए गए इस बिल में मीन–मेख निकालकर, टीका–टिप्पणी करके आजकल कुछ चेहरे अपने को भ्रष्टाचार–उन्मूलन का मसीहा साबित करने पर तुले हैं. उनका प्रमुख आरोप यह है कि इस बिल में लोकपाल के चयन का प्रावधान वर्ष 2004 के जैसा नहीं है. न्यायपालिका व अन्य विशिष्ट व्यक्तियों की बजाय इसमें राजनीतिक दल या सरकार का बहुमत है. यदि ऐसा है भी तो इसके पीछे आम–आदमी सरकार, जो देश में एक नई राजनीतिक शुरुआत है, की एक स्पष्ट सोच दिखती है. आज तक देश में भ्रष्टाचार व स्वराज किसी पार्टी का चुनावी–मुद्दा कभी नहीं रहा था. पहली बार दिल्ली की जनता ने इसी मुद्दे पर आप की सरकार बनाई है. इसलिए भ्रष्टाचार से लड़ने की ज्यादा जवाबदेही इसी सरकार की है. यह सरकार एक ईमानदार लोकपाल के माध्यम से भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसकर देश के समक्ष एक नजीर पेश करना चाहती है, जिससे भ्रष्ट–तंत्र में खलबली है. तथाकथित भ्रष्टाचार–विरोधी व स्वराज अभियान के पितामह क्या देश को यह विश्वास दिलाने में सक्षम है कि न्यायपालिका व अति विशिष्ट–जन बेदाग होंगे, और उन्हें इस भ्रष्ट–तंत्र द्वारा ख़रीदा नहीं जा सकेगा? यदि नहीं तो यह कांव–कांव क्यों?

केजरीवाल को जनता ने आपार बहुमत देकर एक नयी स्वच्छ–व्यवस्था की आशा की है. अत: सरकार को कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए.

–अमितानन्द, *मोतिहारी, बिहार.*

बिहार चुनाव में हार के निहितार्थ

किसी भी चुनाव में पराजित पक्ष गलतियों का पुतला बन जाता है और विजेता मसीहा. बिहार में हार के लिए भाजपा की कमियां निकालना आसान है, पर ठीक चुनाव के वक्त दालों के दाम बेलगाम होना तथा मीडिया के द्वारा असहिष्णुता का हौवा खड़ा करने के साथ–साथ भाजपा नेताओं के वे बेतुके बयान भी हार के प्रमुख कारण हैं, जो अब भी रुक नहीं रहे हैं. ऐसे में नरेन्द्र मोदी व अमित शाह को अपनी हार की समीक्षा कर मंत्रिमंडल में फेरबदल करनी चाहिए और अक्षम व अप्रभावी मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, ताकि सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतर सके.

–सत्य प्रकाश शिक्षक,
लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश.

सभी उत्तीर्ण युवाओं की नियुक्ति हो

लोकतंत्र सभी तंत्रों में श्रेष्ठ है, लेकिन इधर कुछ दशकों से लोकतंत्र का स्वरूप विकृत हुआ है. जनता द्वारा चुने शासकों को जनता की कोई फिक्र नहीं है. मनमानी नियुक्तियां की जा रही हैं. प्रशिक्षित युवाओं के होते हुए भी शिक्षा मित्रों के पद पर अयोग्य लोगों की नियुक्तियां की गईं. जब बीएड उत्तीर्ण युवा उपलब्ध थे तो हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट उत्तीर्ण युवाओं को क्यों नियुक्त किया गया? मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यदि युवा पीढ़ी के शुभ चिंतक हैं, तो 2011 में टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके प्रत्येक युवा को नियुक्त करें. यदि आर्थिक समस्या है, तो आचार्य पद सृजित कर मात्र दस हजार मासिक मान देय पर नियुक्त करें. नियमत: जब तक सभी टीईटी उत्तीर्ण युवाओं को नौकरी न मिल जाए, तब सरकार को अगली टीईटी परीक्षा नहीं करानी चाहिए.

–राज किशोर पाण्डेय,
लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश.

सहिष्णु देश

देश जल रहा है,
दुश्मन मचल रहा है.
असहिष्णु मारे सहिष्णु को
लोकतंत्र गल रहा है
दादरी का शैतान उभर
अमन निगल रहा है
तमगा सत्ता को वापस
सूरज निकल रहा है
कानी कुतिया कुर्सी बनी
हिंसक खल रहा है
बदला धर्म का चेहरा
अधर्मी छल रहा है
कोना हुए राम रहीम
व्यक्तिवाद मचल रहा है
कतर जा कतरा गुलाब
वक्त दल रहा है

–घनश्याम बेलानी गुलाब,
कटनी, मध्य प्रदेश.

जीवन का ज्ञान

अगर पहले पहल अविश्वास नहीं होता तो विश्वास इतना पक्का नहीं होता. यह समझो कि हमारे जो अवगुण हैं, वही आगे गुण बनाने में सहायता करेंगे और यह सोचना चाहिए कि बाबा ने ही यह सब कुछ दिया है. उसे आप मन से नहीं निकाल सकते. सद्गुरु को साथ लेकर, जैसे मैंने कहा था कि बाबा की ही लीला समझकर, उसे सहन करके देखिए, क्योंकि बाबा ने कहा था कि आगे-आगे देखो होता है क्या?

अपराजिता

अपराजिता, विष्णुक्रांता, गोकर्णी आदि नामों से जानी जाने वाली श्वेत या नील वर्ण के पुष्पों वाली कोमल वृक्ष आश्रित वल्लरी उधानों एवं गृहों के शोभा वर्धनार्थ लगाई जाती है. इस पर पुष्प विशेषकर वर्षा ऋतु में लगते हैं. यह वनस्पति अपने प्रयोग में प्राय: अपराजित या सफल भी होती है अथवा जिसके प्रयोग से वैध पराजित नहीं होता, इसलिए इसे अपराजिता कहते हैं.

बाह्य स्वरूप

इसकी 2 मी से लम्बी, बहुवर्षायु, सुन्दर, शाखा-प्रशाखायुक्त लता होती है. इसके काण्ड पतले मूसलाकार कुछ अंश तक रोमिल तथा आरोही होते हैं. इसके पत्ते छोटे और प्राय: गोल होते हैं. इसके पुष्प जल सीप के आकार वाले गोल, चमकीले, नीले अथवा श्वेत वर्ण के रहते हैं. इसकी फली 5-10 सेमी लम्बी, 1 सेमी चौड़ी, चपटी, नुकीली, थोड़ी मुड़ी हुई, मटर के आकार की एवं तलवार के जैसे झुकी हुई रहती है. एक फली में 6-10 अण्डाकार, चपटे, उड़द के दानों के समान कृष्ण वर्ण के चिकने बीज निकलते हैं. इसका पुष्पकाल एवं फलकाल जुलाई से मार्च तक होता है.

आयुर्वेदीय गुण-कर्म प्रभाव

1. इसके बीज शिर: शूल नाशक होते हैं.

2. दोनों प्रकार की अपराजिता मेधा के लिए हितकारी, शीतल, कंठ को शुद्ध करने वाली, त्रिदोषशामक, स्मृति व बुद्धिवर्धक, कुष्ठ, मूत्र-दोष, आमदोष, सूजन, व्रण तथा विष को दूर करने वाली है.

3. यह विषघ्न, कंठ्य, चक्षुष्य, मस्तिष्क रोग , कुष्ठ, अर्बुद, शोथ, जलोदर तथा यकृत व प्लीहा में उपयोगी है.

4. यह विरेचक, कासघ्न, मूत्रल तथा वेदनाशामक होती है.

5. इसके पत्र मूत्रल, विरेचक, वामक तथा नियातकालिक व्याधिरोधी होते हैं.

6. इसके मूल एवं बाज तंत्रिका बलकारक, परिवर्तक तथा विरेचक होते हैं.

7. इसका मूल प्रशामक होता है.

8. इसके पत्र एवं मूल सर्वांग शूल, संक्रामक रोग, लैंगिक मूत्रज विकार, कृमिरोग, दंशजन्य प्रभाव, जीर्ण श्वास-नलिका शोथ में हितकर होते हैं.

औषधीय प्रयोग मात्रा एवं विधि

शिरो रोग

1. शिरोवेदना-अपराजिता की फली के 2-4 बूंद रस का नस्य अथवा मूल के रस का नस्य प्रात: खाली पेट एवं सूर्योदय से पूर्व देने से शिरोवेदना नष्ट होती है. इसकी जड़ को कान में बांधने से भी लाभ होता है.

2. इसके बीजों के 2-2 बूंद रस को नाक में टपकाने से आधासीसी का दर्द मिट जाता है.

3. अपराजिता के बीज ठंडे और विषघ्न हैं. बीज और जड़ को समभाग लेकर जल के साथ पीसकर नस्य देने से अर्धावभेदक में लाभ होता है.

नेत्र रोग

1. नेत्र रोग- श्वेत अपराजिता तथा पुनर्नवा के मूल कल्क में समभाग जौ का चूर्ण मिलाकर अच्छी तरह घोटकर, वर्ती बनाकर, जल से घिसकर अंजन करने से नेत्रगत विकारों का निवारण होता है.

कर्ण रोग

1. कर्णशूल- अपराजिता पत्र-स्वरस को सुखोष्ण कर कान के चारों तरफ लेप करने से कर्णशूल का शमन होता है.

मुख रोग

1. दंतशूल- अपराजिता मूल कल्क में काली मिर्च चूर्ण मिलाकर मुख में धारण करने से दंतशूल में लाभ होता है.

कण्ठ रोग

1. श्वेत अपराजिता की जड़ के 1 से 2 ग्राम चूर्ण को घृत में मिश्रित कर खाने से अथवा कटु फल के चूर्ण को गले के अन्दर घर्षण करने से गलगण्ड रोग शान्त होता है.

2. तुण्डिकेरी शोथ- 10 ग्राम अपराजिता पत्र का 500 मिली जल में क्वाथ कर, आधा शेष रहने पर सुबह-शाम गंडूष करने से टॉन्सिल, गले के व्रण तथा स्वर भंग में लाभ होता है.

3. गलगण्ड -श्वेत अपराजिता मूल को घृतकुमारी के रेशों के सूत्र से बांधकर हाथ में बांधने से संध उत्पन्न गण्डमाला का शमन होता है.

अपची- पुष्य नक्षत्र में श्वेत अपराजिता मूल को उखाड़ कर गले में बांधने से तथा प्रतिदिन मूल के चूर्ण को गोदुग्ध या गोघृत के साथ खाने से अपची रोग में शीघ्र लाभ होता है.

वक्ष रोग

कास श्वास- अपराजिता मूल का शर्बत, थोड़ा-थोड़ा पीने से कास, श्वास और बालकों की कुक्कुर खांसी में लाभ होता है.

उदर रोग

जलोदर- आधा ग्राम अपराजिता के भुने हुए बीज चूर्ण को उष्णोदक के साथ दिन में दो बार सेवन कराने से जलोदर, कामला और बालकों के डिब्बा रोग में लाभ होता है.

बालकों के उदर शूल- अपराजिता के 1-2 बीजों को आग पर भूनकर, बकरी के दूध अथवा घी के साथ चटाने से अफारा तथा उदरशूल में शीघ्र लाभ होता है.

यकृतप्लीहा रोग

1. प्लीहा वृद्धि- अपराजिता की जड़ को दूसरी रेचक और मूत्र जनक औषधियों के साथ देने से बढ़ी हुई तिल्ली और जलोदर आदि गोर मिटते हैं. मूत्राशय की दाह मिटती है.

2. 3-6 ग्राम अपराजिता मूल चूर्ण को छाछ के साथ देने से कामला में लाभ होता है.

वृक्कवस्ति रोग

1. मूत्रकृच्छ- 1-2 ग्राम अपराजिता मूल चूर्ण को गर्म पानी या दूध के साथ दिन में 2 या 3 बार प्रयोग करने से गठिया, मूत्राशय की जलन और मूत्रकृच्छ में लाभ होता है.

2. अश्मरी- 5 ग्राम अपराजिता की जड़ को चावलों के धोवन के साथ पीस-छानकर कुछ दिन प्रात: सायं पिलाने से मूत्राशय की पथरी कट-कट निकल कर निकल जाती है.

प्रजन्न संस्थान रोग

1. अण्डकोष वृद्धि- अपराजिता के बीजों को पीसकर गर्म कर लेप करने से अण्डकोष की सूजन का शमन होता है.

2. गर्भस्थापनार्थ- 5 ग्राम श्वेत अपराजिता छाल अथवा पत्रों को बकरी के दूध में पीस-छानकर तथा मधु मिलाकर पिलाने से गिरता हुआ गर्भ ठहर जाता है तथा कोई पीड़ा नहीं होती है.

3. 1 ग्राम श्वेत अपराजिता की जड़ को दिन में दो बार बकरी के दूध में पीस-छानकर, मधु मिलाकर कुछ दिनों तक खिलाने से गिरता हुआ गर्भ ठहर जाता है.

4. सुख प्रसव के लिए- अपराजिता की बेल को स्त्री की कमर में लपेट देने से शीघ्र ही प्रसव होकर पीड़ा शान्त हो जाती है.

5. पूयमेह- 3-6 ग्राम अपराजिता मूलत्वक् को 1.5 ग्राम शीतल चीनी तथा 1 नग काली मिर्च तीनों को जल के साथ पीसकर छानकर सुबह-सुबह सात दिन तक पिलाने से तथा पंचांग के क्वाथ में रोगी को बिठाने से या मूत्रेन्द्रिय को उसमें डुबोए रखने से शीघ्र लाभ होता है.

अस्थिसंधि रोग

1. संधिशोथ- अपराजिता पत्र- कल्क को संधियों पर लगाने से संधिशोथ में लाभ होता है. ■

आचार्य बालकृष्ण

रोजगार गारंटी की पूरी जानकारी चाहिए तो आरटीआई का प्रयोग करें

रोजगार गारंटी के तहत मांगे गये काम का विवरण

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन.

महोदय,

मैं.....ग्राम का निवासी हूं. मैंने एन.आर.ई.जी.ए. के तहत रोजगार के लिये आवेदन किया था. मेरा जॉब कार्ड संख्या.....है. इस सम्बंध में निम्न विवरण प्रदान करें:

1. आपके रिकॉर्ड के मुताबिक मेरे आवेदन पर क्या कार्रवाई की गई है? क्या मुझे काम दिया गया? यदि हां तो निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराएं:
   क. कार्य का नाम
   ख. काम दिये जाने की तारीख
   ग. काम की स्थिति (चालू है या समाप्त हो गया)
   घ. आवेदन करने बाद मुझे कितने दिन का काम दिया जा चुका है
   ड. काम के बदले भुगतान की गई राशि
   च. राशि का भुगतान किस तारीख को किया गया
   छ. रिकॉर्ड रजिस्टर के उस भाग की प्रमाणित प्रति, जहां मेरे भुगतान से सम्बंधित विवरण दर्ज है

2. एन.आर.ई.जी.ए. के तहत काम के लिये आवेदन करने के कितने दिनों के अन्दर काम मिल जाना चाहिए? इससे सम्बंधित नियमों/आदेशों/दिशानिर्देशों की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराएं.

3. एन.आर.ई.जी.ए. के तहत काम के लिये आवेदन करने के कितने दिनों तक काम नहीं उपलब्ध करा पाने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है?

4. आपके रिकॉर्ड के अनुसार, क्या मुझे बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए? यदि हां तो क्या मुझे बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा? यदि हां तो इससे सम्बंधित निम्नलिखित सूचनाएं दें:
   क. कब से दिया जा रहा है, तारीख बताएं
   ख. कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है, तिथिवार विवरण दें
   ग. रिकॉर्ड रजिस्टर के उस भाग की प्रमाणित प्रति, जहां मेरे भुगतान से सम्बंधित विवरण दर्ज है

5. मेरे गांव में जिन लोगों को जॉब कार्ड दिया गया है, उनमें से कितने लोगों ने काम देने का आवेदन किया है, उसकी सूची निम्नलिखित सूचनाओं के साथ उपलब्ध कराएं:
   क. आवेदक का नाम व पता
   ख. आवेदन करने की तारीख
   ग. दिए गये कार्य का नाम
   घ. कार्य दिए जाने की तारीख
   ड. कार्य के लिए भुगतान की गई राशि व भुगतान की तारीख
   च. रिकॉर्ड रजिस्टर के उस भाग की प्रमाणित प्रति, जहां इनके भुगतान से सम्बंधित विवरण दर्ज हैं
   छ. यदि काम नहीं दिया गया है तो क्यों?
   ज. क्या उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है?

6. एन.आर.ई.जी.ए. के तहत तय समयसीमा काम या बेरोजगारी भत्ता नहीं देने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी और कब तक?

मैं आवेदन फीस के रूप में 10 रुपये अलग से जमा कर रहा/रही हूं.

भवदीय
नाम:
पता:
फोन नं:
संलग्नक:
(यदि कुछ हो)

यदि आपने सूचना अधिकार कानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें.

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11 नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन-201301
ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

साईं वंदना

भय, आशंका एवं अविश्वास से मुक्ति

डॉ. चन्द्रभानु सतपथी

मन जो भय, आशंका, आदि बुरे विचारों से हमें घेरे रखता है और बाबा के करीब जाने नहीं देता, क्या इसकी पकड़ से हम इस जन्म में निकल सकते हैं?

मन में जो भय, आशंका, अविश्वास और बुरे विचार हैं, वे बाबा के करीब आने नहीं देते हैं, यह बातें मुझे ठीक नहीं लग रही हैं. मैं तो यह कहता हूं कि उस भय, आशंका, अविश्वास के बीच बाबा को देखो. हम ये क्यों नहीं सोचते कि बाबा सब कुछ नियंत्रित करते हैं. यह भय, अविश्वास, आशंका भी एक आवश्यक अनुभव के रूप में हमें दिया जा रहा है, ताकि हम कल उन्नति के मार्ग पर चल सकें. अगर भय नहीं होता तो इतने पाप करते कि समाज ज्यादा दिन नहीं चल पाता. आशंका नहीं होती तो लोग अपने आपको संयमित नहीं कर पाते. अगर पहले पहल अविश्वास नहीं होता तो विश्वास इतना पक्का नहीं होता. यह समझो कि हमारे जो अवगुण हैं, वही आगे गुण बनाने में सहायता करेंगे और यह सोचना चाहिए कि बाबा ने ही यह सब कुछ दिया है. उसे आप मन से नहीं निकाल सकते. सद्गुरु को साथ लेकर, जैसे मैंने कहा था कि बाबा की ही लीला समझकर, उसे सहन करके देखिए, क्योंकि बाबा ने कहा था कि आगे-आगे देखो होता है क्या?

झूठे आडंबर एवं सिद्धियां

यह भी देखा गया है कि कुछ लोग मंदिरों में अन्य लोगों के समक्ष भक्ति-भाव का बाह्य रूप से खूब प्रदर्शन करते हैं, फिर भी वे अंदर से शांति-भाव को क्यों नहीं प्राप्त कर पाते हैं?

कुछ व्यक्ति आध्यात्मिक जगत को चमत्कार के रूप में देखना चाहते हैं. वे चाहते हैं कि उन्होंने जितना भक्ति-प्रदर्शन किया है और भागदौड़ की है, इसके लिए बहुत जल्दी उन्हें ऋद्धि, सिद्धि आदि शक्तियां या ऐसी ही दुर्लभ चीज मिल जाए, ताकि उसे वे समाज के सामने दिखा कर स्वयं को महान भक्त दर्शा सके. ऐसे लोग कभी-कभी बाबा की तरह वेशभूषा भी पहन लेते हैं और बाबा से उनका कितना निकट का संबंध स्थापित हो रहा है-इसका वर्णन वे सबसे करते हैं. आम लोग इतने भोल-भाले होते हैं कि बाह्यआचरण देखकर समझने लगते हैं कि वे किसी उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं. आखिर में जब उनको इस प्रकार सिद्धि आदि नहीं मिलती है, तो वे सोचते हैं कि उन्होंने व्यर्थ ही समय को बर्बाद किया है और उनकी प्राप्ति के लिए अन्यत्र जैसे तांत्रिकों आदि के पास भी चले जाते हैं.

ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं और जो होते हैं, वे या तो अत्यंत स्वार्थी होते हैं या फिर शक्ति प्राप्त करके अपने को गुरु कहलवाने की इच्छा रखते हैं. कभी-कभी गलत संगति में पड़कर भी वे ऐसा करते हैं. ■

साई भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साई से आप कब और कैसे जुड़े. साई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साई को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साई भक्त. साई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है? साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

पुणे के हुए धोनी

आईपीएल-6 में स्पॉट फिक्सिंग मामले में दोषी पाए जाने केबाद चेन्नई सुपरकिंग्स और राजस्थान रॉयल्स को दो-दो साल के लिए टूर्नामेंट से सस्पेंड कर दिया था. चेन्नई और राजस्थान के को-ऑनर्स भी करप्शन केदोषी पाए गए थे. इसी वजह से आईपीएल के अगले 2 सीजन के लिए दो नई टीमों को चुनना पड़ा था. दोनों नई टीमें राजकोट और पुणे सिर्फ दो साल के लिए ही टी-20 लीग का हिस्सा रहेंगी.

हाल ही में आईपीएल 9 की दो नई टीमों पुणे और राजकोट ने प्लेयर्स की बोली लगाई. हालांकि सबसे पहले महेन्द्र सिंह धोनी पर बोली लगाई गई थी. उन्हें पुणे की टीम ने 12.5 करोड़ रुपये में लिया है. इससे पहले धोनी को चेन्नई सुपर किंग्स से करीब 20 करोड़ रुपये मिलते थे. सीएसके की सफलता में बराबर योगदान देने वाले सुरेश रैना को राजकोट फ्रेंचाइजी ने खरीदा है. पुणे की टीम में महेंद्र सिंह धोनी, अजिंक्य रहाणे, आर. अश्विन, स्टीवन स्मिथ, फॉफ डुप्लेसी हैं और राजकोट की टीम में सुरेश रैना, रवींद्र जडेजा, ब्रैंडन मैक्कुलम, जेम्स फॉक्नर, ड्रवेन ब्रावो हैं. नई टीम में चुने जाने के बाद सुरेश रैना ने ट्वीट कर खुशी जाहिर की है. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि, मैं खूबसूरत शहर राजकोट की तरफ से आईपीएल में खेलने को लेकर एक्साइटेड हूं. नए खिलाड़ियों और गुजरात का सपोर्ट चाहता हूं. 8 साल बाद धोनी-रैना चेन्नई सुपर किंग से अलग हुए हैं. अब विराट कोहली और हरभजन सिंह ही ऐसे दो खिलाड़ी हैं, जो लगातार एक ही टीम से खेल रहे हैं. आईपीएल-6 में स्पॉट फिक्सिंग के मामले में दोषी पाए जाने के बाद चेन्नई सुपरकिंग्स और राजस्थान रॉयल्स को दो-दो साल के लिए टूर्नामेंट से सस्पेंड कर दिया था. चेन्नई और राजस्थान के को-ऑनर्स भी करप्शन के दोषी पाए गए थे. इसी वजह से आईपीएल के अगले 2 सीजन के लिए दो नई टीमों को चुनना पड़ा था. दोनों नई टीमें राजकोट और पुणे सिर्फ दो साल के लिए ही टी-20 लीग का हिस्सा रहेंगी. उसके बाद चेन्नई और राजस्थान लीग में वापसी कर लेंगी. धोनी को चेन्नई सुपर किंग्स से करीब 20 करोड़ रुपये मिलते थे. वे पिछले साल आईपीएल में सबसे ज्यादा कीमत पाने वाले खिलाड़ी रहे हैं. उनके बाद युवराज सिंह का नंबर था, युवराज सिंह को दिल्ली ने 16 करोड़ रुपये में खरीदा था. ■

सानिया मिर्जा बनी नंबर वन

इस साल स्विटजरलैंड की मार्तिना हिंगिस के साथ युगल वर्ग में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली सानिया मिर्जा सत्र के आखिर में रैंकिंग में नंबर वन रही है. सानिया और हिंगिस ने इस साल अमेरिकी ओपन और विम्बलडन ग्रैंडस्लैम खिताब के अलावा 10 डब्ल्यूटीए खिताब अपने नाम किए, जिसमें सिंगापुर में सत्र का आखिरी वर्ल्ड टूर फाइनल्स भी शामिल था.

लंदन एटीपी वर्ल्ड टूर फाइनल्स के खिताबी मुकाबले तक पहुंचे भारतीय टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना ने सत्र की आखिरी युगल रैंकिंग में शीर्ष दस में जगह बनाई है और सानिया मिर्जा डब्ल्यूटीए युगल रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार हैं. बोपन्ना और फ्लोरिन मर्जिया की जोड़ी सत्र के इस आखिरी एटीपी फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त जीन जूलियन रोजर और होरिया टेकाउ से 4-6, 3-6 से हार गई थी. बोपन्ना ने रैंकिंग में तीन पायदान की छलांग लगाकर नौवें स्थान पर कब्जा किया है जबकि लिएंडर पेस 41वें स्थान पर बने हुए हैं. वहीं इस साल स्विट्जरलैंड की मार्तिना हिंगिस के साथ युगल वर्ग में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली सानिया मिर्जा सत्र के आखिर में रैंकिंग में नंबर वन रही हैं. सानिया और हिंगिस ने इस साल अमेरिकी ओपन और विम्बलडन ग्रैंडस्लैम खिताब के अलावा 10 डब्ल्यूटीए खिताब अपने नाम किए, जिसमें सिंगापुर में सत्र का आखिरी वर्ल्ड टूर फाइनल्स भी शामिल था. ■

2015 की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनीं सेरेना विलियम्स

इस साल टेनिस कोर्ट पर बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली अमेरिका की दिग्गज खिलाड़ी सेरेना विलियम्स को स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड ने वर्ष 2015 की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है. मैगजीन ने कहा कि टेनिस के इतिहास में इतने लंबे समय तक अच्छा प्रदर्शन करने और इस साल कई खिताब जीतने के लिए सेरेना को चुना गया. सेरेना ने तीन मेजर खिताबों के अलावा इस साल 56 में से 53 मैच जीते और लगातार दूसरे साल सत्र में हर सप्ताह नंबर वन रहीं. स्पोर्ट्स इलस्टरेटेड के समूह संपादक पाल फिशटेनबाम ने कहा, सेरेना सिर्फ अपने दौर

की ही नहीं बल्कि सर्वकालिक महानतम टेनिस खिलाड़ियों में से हैं. इस साल लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करके सभी को काफी पीछे छोड़ दिया. इसके साथ ही सेरेना विलियम्स मुक्केबाज मोहम्मद अली, ऑर्थर एश, लिब्रॉन जेम्स, माइकल जॉर्डन, बिली जीन किंग और जैक निकलस जैसे दिग्गजों की एलीट समूह में शामिल हो गई हैं. 34 वर्षीय अमेरिकी टेनिस प्लेयर सेरेना 1983 के बाद पहली महिला प्लेयर हैं, जिन्हें अमेरिका की प्रतिष्ठित पत्रिका स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड ने यह सम्मान दिया है. इससे पहले एसआई ने मेरी डेकर को इस पुरस्कार से सम्मानित किया था. अमेरिका की शीर्ष टेनिस प्लेयर सेरेना ने 2015 में लगातार तीन ग्रैंड स्लैम जीते थे. वहीं वर्ल्ड रैंकिंग में लगातार दो साल तक शीर्ष पर रहना उनकी श्रेष्ठता को भी साबित करता है. नस्लभेद के खिलाफ आवाज उठाने, समानता और दुनिया में शिक्षा के समान अवसर की वकालत करने के लिए भी पत्रिका ने सेरेना विलियम्स की जमकर तारीफ की है. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

डब्ल्यूडब्ल्यूई को अलविदा कह सकते हैं जॉन सीना

वाल स्ट्रीट जनरल को दिये एक इंटरव्यू में डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार जॉन सीना ने अपने रिटायरमेंट को लेकर और काफी चीज़ों के बारे में बातें कीं. उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई के बारे में बात करते हुए कहा की उन्होंने वो सब किया है जो वो इस खेल को लोकप्रिय बनाने के लिए कर सकते थे. उन्होंने ये भी कहा कि जब वो अपने फैन्स को खुश करते हैं तो उन्हे दिल से खुशी होती है और वो अच्छा करने के लिए प्रेरित होते हैं. जॉन सीना ने बताया कि वो हर दिन कुछ न कुछ नया सीखते हैं. उन्होंने कहा, हर रात नई होती है, सब चीज़ें भी अलग होती हैं. इसी वजह से मैं अपने काम में काफी ईमानदार रहता हूं और कुछ नया करने के लिए प्रेरित होता हूं. उन्होंने अपने रिटायरमेंट के बारे में बात की और कहा, मुझे पता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस खेल में टाइम ही सब कुछ होता है. मैंने कसम खाई है कि मैं हमेशा अपने लेवल को बनाकर रखूंगा. यहां से जाने के बाद मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा. शायद मैं पर्दे के पीछे नए टैलंट को उभारने में कुछ रोल अदा कर सकूं मैं जब भी एक बच्चे को अपने फैन के रूप में देखता हूं, तो मुझे सही में काफी अच्छा लगता है. मेरे लिए यह खुशी काफी बड़ी खुशी है. इससे ही मेरा हर दिन अच्छा और अलग होता है. ■

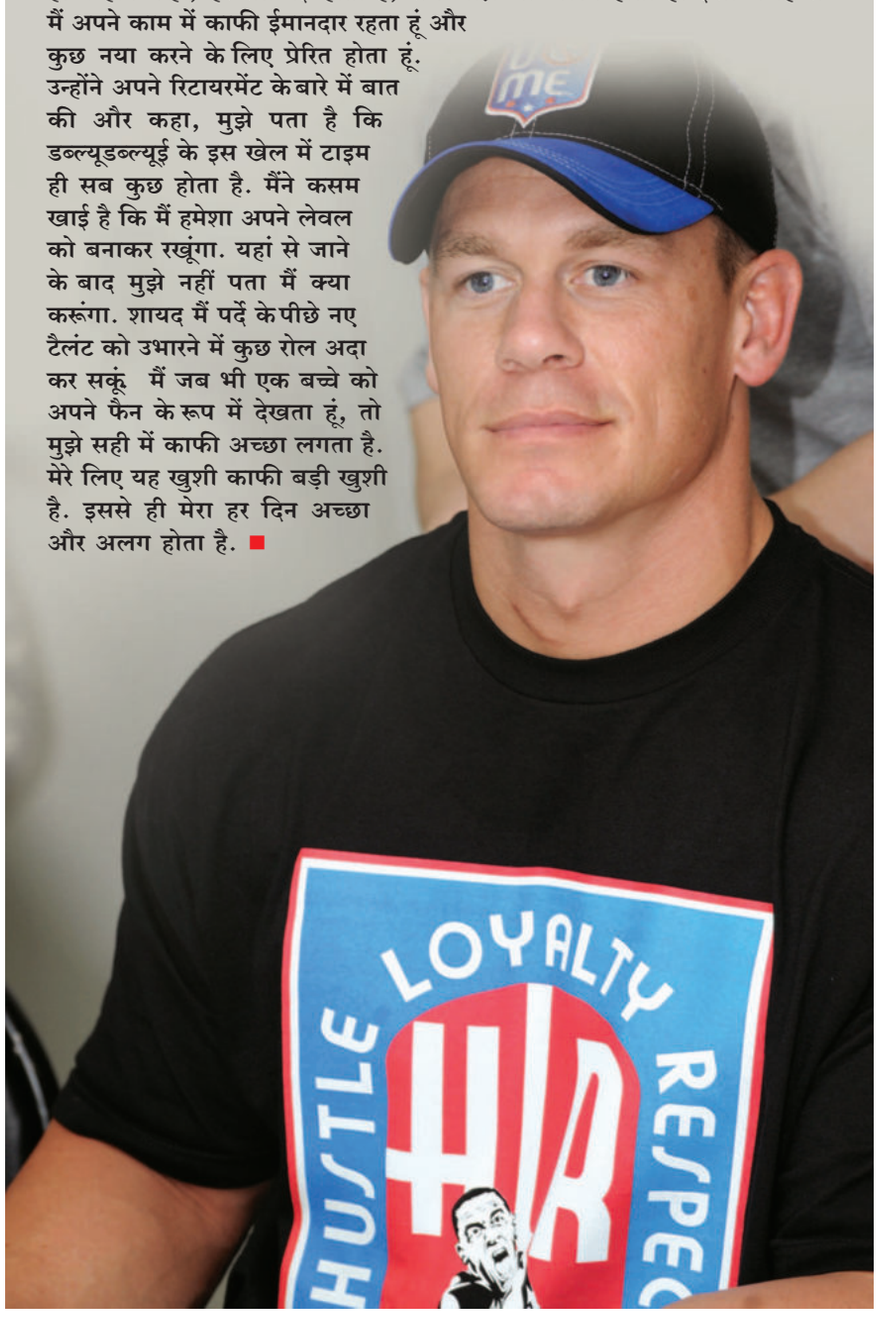

जानिए कौन था भारतीय हॉकी का पहला कैप्टन

हॉकी भारत का हमेशा से एक प्रमुख खेल रहा है, क्योंकि हॉकी देश का सिर्फ राष्ट्रीय खेल ही नहीं बल्कि इस खेल ने कई बार ओलम्पिक में देश का नाम ऊंचा करने के साथ-साथ ध्यानचंद जैसे महान खिलाड़ी भी देश को दिए हैं. आज भी हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ियों में मेजर ध्यानचंद्र के साथ-साथ जयपाल सिंह मुण्डा का नाम भी याद किया जाता है, क्योंकि जयपाल सिंह मुण्डा ही भारतीय हॉकी के सबसे पहले कैप्टन थे. जयपाल सिंह मुण्डा का जन्म 3 जनवरी, 1903 में झारखण्ड की राजधानी रांची में हुआ था. जयपाल सिंह झारखण्ड की प्रमुख आदिवासी जनजाति मुण्डा से सम्बन्ध रखते थे, जिसका मूल स्थान दक्षिणी छोटा नागपुर है. कहा जाता है कि भारत के लिए हॉकी का स्वर्णिम युग 1928 से 1956 तक था, जब भारतीय हॉकी दल ने लगातार 6 ओलम्पिक स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे. सन् 1928 तक हॉकी भारत के लिए एक जुनून बन चुकी थी और बाद में यह देश का राष्ट्रीय खेल बन गया. सन् 1928 में ही एमस्टर्डम ओलम्पिक में भारतीय टीम जयपाल सिंह के नेतृत्व में पहली बार प्रतियोगिता में उतरी और टीम ने पांच मुक़ाबलों में एक भी गोल दिए बगैर स्वर्ण पदक जीता. जयपाल सिंह की कप्तानी में टीम ने, जिसमें हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले महान खिलाड़ी ध्यानचंद भी शामिल थे, अंतिम मुक़ाबले में हॉलैंड को आसानी से हराकर स्वर्ण पदक जीता था. उस समय युवा ध्यानचंद ने अपने खेल से एम्सटर्डम के खेल प्रेमियों को मंत्र मुग्ध कर दिया था. पूरे टूर्नामेंट में जहां ध्यानचंद की जादूगरी शबाब पर थी, वहीं कोई भी विरोधी टीम एक बार भी भारतीय गोलपोस्ट को भेदने के लिए तरस गई. हॉकी से सेवा-निवृत्ति के बाद जयपाल सिंह बंगाल हॉकी संघ के सचिव और भारतीय खेल परिषद के सदस्य रहे. जयपाल सिंह का खेल से राजनीति में कदम रखना भी काफी दिलचस्प रहा.

> पूरे टूर्नामेंट में जहां ध्यानचंद की जादूगरी शबाब पर थी, वहीं कोई भी विरोधी टीम एक बार भी भारतीय गोलपोस्ट को भेदने के लिए तरस गई. हॉकी से सेवा-निवृत्ति के बाद जयपाल सिंह बंगाल हॉकी संघ के सचिव और भारतीय खेल परिषद के सदस्य रहे. जयपाल सिंह का खेल से राजनीति में कदम रखना भी काफी दिलचस्प रहा.

जयपाल सिंह शुरू से ही आदिवासियों के लिए कुछ करना चाहते थे, इसलिए सन् 1936 में वह राजनीति में आए और बाद में झारखण्ड पार्टी का गठन किया. आदिवासी नेता जयपाल सिंह सन् 1952 में प्रथम लोकसभा के सदस्य बने और आजीवन अपने क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य रहे. जयपाल सिंह का हमेशा से यह सपना रहा कि बिहार से अलग होकर ही झारखण्ड में विकास की रफ्तार हो सकती है और उनका यह सपना 12 नवंबर वर्ष 2000 में पूरा हुआ जब झारखण्ड बिहार से अलग राज्य बना. आज भी जयपाल सिंह मारंग गोमके के नाम से लोगों के बीच जाने जाते हैं, जिसका अर्थ है महान नेता. भारत की महान विभूति का निधन 20 मार्च, 1970 को दिल्ली में हुआ, लेकिन आज भी हॉकी के खल प्रेमियों दिलोंमें जयपाल सिंह याद किए जाते है. ■

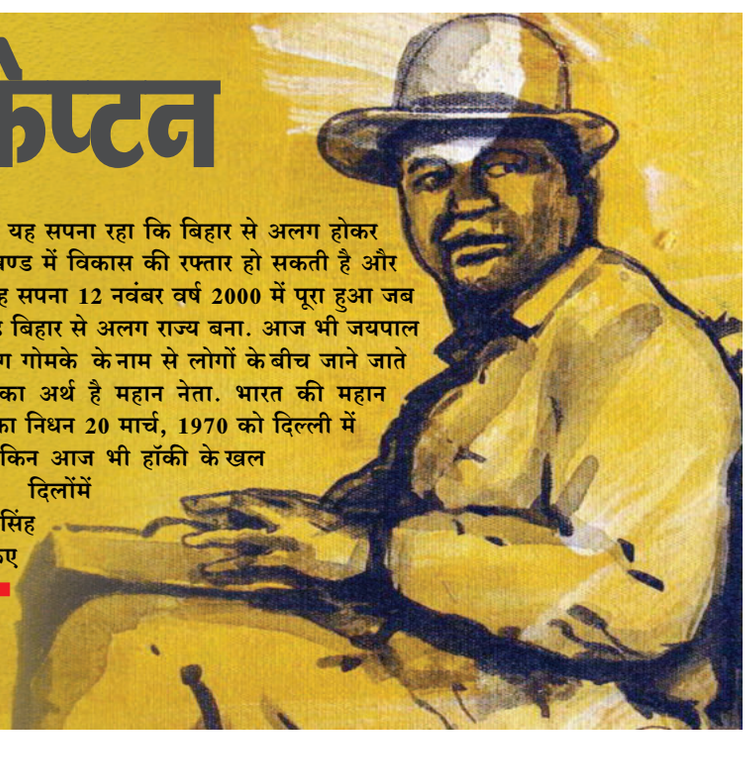

धूम मचाएगी सनी लियोनी पर बनी डॉक्यूमेंट्री

फोटो जर्नलिस्ट दिलीप मेहता ने सनी लियोनी की पिछली जिंदगी और वर्तमान करियर को इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया है.

बॉलीवुड में अपनी अदाओं से सबको अपना दीवाना बनाने वाली सनी लियोनी के अनछुए पहलू बड़े परदे पर जल्द ही देखने को मिलेंगे. सनी लियोनी की जिंदगी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनने जा रही हैं. जाने माने फोटो जर्नलिस्ट दिलीप मेहता ने सनी लियोनी की पिछली जिंदगी और वर्तमान करियर को इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाएंगे. बताया जा रहा है कि इस डॉक्यूमेंट्री में सनी ने अपने बीती हुई जिंदगी को लेकर खुलकर बात की है. सनी पर आधारित इस डॉक्यूमेंट्री का निर्माण हेमिल्टन मेहता प्रोडक्शन के बैनर तले होगा. फिल्म को दीपा मेहता डायरेक्ट करेंगी. हाल ही में सनी के फिल्म मस्तीजादे का टीजर भी रिलीज हुआ है. यह फिल्म अगले महीने रिलीज होने वाली है. फिल्म में सनी के साथ एक्टर तुषार कपूर और वीर दास भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे.■

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

आंखें के सीक्वल में शाहिद और कटरीना

फिल्म में शाहिद कपूर, कटरीना कैफ, अमिताभ बच्चन और नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी अहम किरदार में नजर आएंगे.

अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, सुष्मिता सेन, अर्जुन रामपाल और परेश रावल अभिनीत फिल्म आंखें के सीक्वल में एक्टर शाहिद कपूर और कटरीना कैफ एक साथ नजर आ सकते हैं. डायरेक्टर अनीस बज़्मी का कहना है कि अमिताभ बच्चन निश्चित रूप से 2002 की सुपरहिट सस्पेंस थ्रिलर की सीक्वल का एक अहम हिस्सा होंगे. अगर खबरें सच साबित होती हैं, तो इस थ्रिलर ड्रामा फिल्म के दूसरे पार्ट में शाहिद और कटरीना को एक साथ देखना काफी रोमांचक होगा. खबरों की माने तो फिल्म में शाहिद कपूर, कटरीना कैफ, अमिताभ बच्चन और नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी अहम किरदार में नजर आएंगे. ■

2015 दीपिका बनीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एक्ट्रेस

फोर्ब्स मैगजीन ने 100 इंडियन सेलिब्रिटीज की सूची जारी की है. इस सूची में दीपिका पादुकोण सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एक्ट्रेस हैं और इस लिस्ट में कई बॉलीवुड एक्टर-एक्ट्रेसेस ने जगह बनाई है. शाहरुख खान लगभग 257.5 करोड़ रुपये की कमाई के साथ टॉप पर हैं. दीपिका की सालाना कमाई लगभग 59 करोड़ रुपये है. वहीं लगभग 52.7 करोड़ की वार्षिक कमाई के साथ करीना कपूर खान दूसरे स्थान पर हैं. दीपिका की इस साल तीन फिल्में रिलीज हुई है. करीना की बात करें, तो वह इस साल फिल्म बजरंगी भाईजान में लीड रोल में थीं और दो अन्य फिल्मों के गानों में नज़र आईं. जबकि कटरीना कैफ 48.5 करोड़ के साथ इस साल नंबर तीन पर रहीं.■

हॉलीवुड ख़बर रोज़ाना सैर करती हैं जेसिका सिम्पसन

सिम्पसन ने एक हॉलीवुड वेबसाइट को बताया कि मैं हर रोज तीन मील की सैर करती हूं. एरिक और मुझे अपने बच्चों को भी सैर पर ले जाना पसंद है. सिम्पसन मानती हैं कि मां बनने के बाद वह स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा जागरूक हो गई हैं.

जानी-मानी गायिका जेसिका सिम्पसन प्रतिदिन सुबह सैर करती हैं. इस बात की जानकारी उन्होंने खुद दी. उन्होंने कहा कि वह अपनी खूबसूरत फिगर के लिए अपने पति एरिक जॉनसन और अपने दोनों बच्चों के साथ तीन मील सैर करती हैं. सिम्पसन ने एक हॉलीवुड वेबसाइट को बताया कि मैं हर रोज तीन मील की सैर करती हूं. एरिक और मुझे अपने बच्चों को भी सैर पर ले जाना पसंद है. सिम्पसन मानती हैं कि मां बनने के बाद वह स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा जागरूक हो गई हैं. सिम्पसन ने कहा कि स्वस्थ जीवनशैली बनाए रखना मेरे लिए जरूरी है. मां बनने के बाद से फिटनेस मेरी जिंदगी की प्राथमिकता बन गई है.■

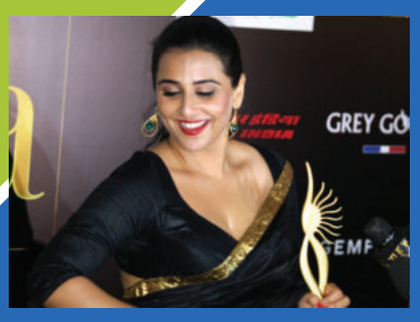

ग्लैमर और सादगी का संगम विद्या बालन

विद्या बालन आज एक ऐसा नाम है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है. अपने दमदार अभिनय से हिट फिल्में देने वाली विद्या शादी के बाद भी हर निर्माता निर्देशक की पसंद बनी हुइ हैं. अपनी मेहनत और दमदार अभिनय से विद्या ने न सिर्फ वाहवाही बटोरी बल्कि यह साबित कर दिया कि फिल्म को हिट कराने के लिए उन्हें किसी की जरुरत नहीं है और अपने अभिनय के दम पर दर्शकों का मनोंरजन कर सकती हैं. बॉलीवुड में अपने दमदार अभिनय का लोहा मनवा चुकी विद्या बालन का जन्म 1 जनवरी 1978 को केरला में हुआ था. विद्या मुंबई में ही पली-बढ़ी हैं.

पढ़ाई

उनका जन्म तमिल परिवार में हुआ था. विद्या तमिल, मलयालम, हिंदी और अंग्रेजी भाषा जानती हैं. विद्या का पूरा बचपन मुंबई में ही बीता. उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के एंथोनी गर्ल्स स्कूल से की और अपनी स्नातक की पढ़ाई संत जेवियर कॉलेज से पूरी की.

सर्वश्रेष्ठ फ़िल्में

परणिता, लगे रहो मुन्ना भाई, गुरु, बेबी, भूल भुलैया, डर्टी पिक्चर, पा, डेढ़ इश्किया, कहानी, नो वन किल्लड जेसिका, हमारी अधूरी कहानी.

करियर

विद्या बालन के करियर का सफर बेहद रोचक रहा है. विद्या बालन ने अपने करियर की शुरुआत म्यूजिक विडियो और कॉमर्शियल विज्ञापन से की. विद्या बालन ने उसके बाद बंगाली फ़िल्म भालो थेको (2003) में की. बाद में विद्या बालन ने फ़िल्म परिणीता (2005) से बॉलीवुड में धमाका किया. इस फिल्म के लिए विद्या बालन को सर्वश्रेष्ठ उभरती अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार से नवाजा गया. उन्हें एक राष्ट्रीय पुरस्कार और 5 बार फिल्मफेयर अवार्ड्स से भी सम्मानित किया जा चुका है. इस तरह विद्या बालन ने खुद को एक सफल अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया.■

रोचक बातें

- विद्या बालन को भले ही अपने गंभीर अभिनय के लिए सराहना और अवार्ड मिले हों, लेकिन उनकी पहली पसंद कॉमेडी फिल्में हैं.
- विद्या बालन अपने आप को एक लालची अभिनेत्री मानती हैं. डर्टी पिक्चर और कहानी जैसी फिल्मों में काम करके वह बेहद खुश हैं. उनका मानना है कि इन फिल्मों ने बॉलीवुड में सफल महिला केंद्रित फिल्मों को बढ़ावा दिया हैं.
- विद्या बालन ने 14 दिसबर 2012 में सिद्धार्थ रॉय कपूर के साथ साउथ इंडियन और पंजाबी परंपराओं के साथ शादी की.
- विद्या ने फिल्म परिणीता से बॉलीवुड में डेब्यू किया. साल 2011 में आई सुपरहिट फिल्म डर्टी पिक्चर के लिए विद्या को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवॉर्ड भी मिला.
- महिला प्रधान फिल्मों के लिए विद्या ही बॉलीवुड निर्माताओं की पहली पसंद हैं. एक अनुमान के मुताबिक विद्या एक फिल्म के लिए लगभग 6-7 करोड़ रूपये लेती हैं.
- चर्चित सीरियल हम पांच में विद्या ने राधिका नाम का किरदार निभाया था, जो लोगों को खासा पसंद भी आया था.
- विद्या बालन को खाली समय में किताबें पढ़ना पसंद हैं.
- विद्या बालन को सफाई बेहद पसंद है, अगर वह कहीं भी गंदगी देखती हैं, तो उसे खुद ही साफ करने लगती हैं.
- विद्या बालन भरतनाट्यम और कथक डांस में पूर्ण रूप से पारंगत हैं.
- इन दिनों विद्या बिग बी और नवाजुद्दीन के साथ अपनी आने वाली फिल्म तीन की शूटिंग में व्यस्त हैं.

करिश्मा और संजय कपूर दिखेंगे साथ

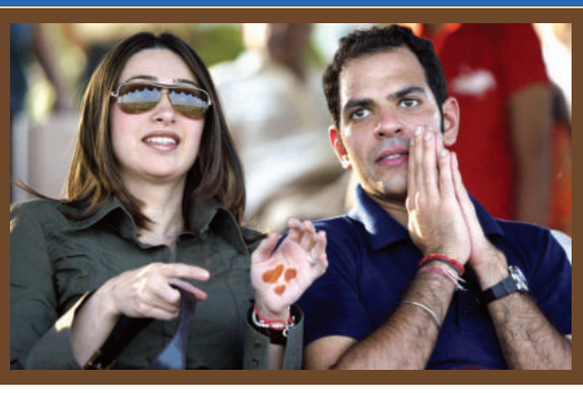

यूके के रिएलिटी शो बिग ब्रदर ने शिल्पा शेट्टी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी. अब इस शो का प्रस्ताव करिश्मा और उनके एक्स हसबैंड संजय कपूर को मिला है. पिछले दिनों ख़बर आई थी कि दोनों ने तलाक की अर्जी वापस लेकर फिर साथ रहने का फैसला किया है. दोनों की ज़िंदगी में आ रहे इस उतार-चढ़ाव की वजह से संभवत: उन्हें इस शो का ऑफर दिया गया है. अभी दोनों ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. संजय और करिश्मा की वर्ष 2003 में शादी हुई थी और 2010 से दोनों अलग हैं.■

चौथी दुनिया

पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ

28 दिसंबर, 2015–03 जनवरी, 2016
www.chauthiduniya.com

2016

आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं

जनवरी 2016

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

फरवरी 2016

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29					

मार्च 2016

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

अप्रैल 2016

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

मई 2016

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

जून 2016

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

जुलाई 2016

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

अगस्त 2016

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

सितंबर 2016

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

अक्टूबर 2016

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

नवंबर 2016

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

दिसंबर 2016

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

वर्ष के प्रमुख अवकाश

- 14 जनवरी - मकर संक्रांति
- 16 जनवरी - गुरु गोविंद सिंह जयंती
- 26 जनवरी - गणतंत्र दिवस
- 12 फ़रवरी- वसंत पंचमी
- 19 फ़रवरी- शिवाजी जयंती
- 22 फ़रवरी - गुरु रविदास जयंती
- 7 मार्च- महाशिवरात्रि
- 23 मार्च -होली
- 25 मार्च- गुड फ्राइडे
- 13 अप्रैल- वैसाखी
- 14 अप्रैल- अम्बेडकर जयंती
- 15 अप्रैल- रामनवमी
- 20 अप्रैल - महावीर जयंती
- 21 मई- बुद्ध पूर्णिमा
- 1 जुलाई- अलविदा जुमा
- 8 जुलाई - ईद-उल-फितर
- 15 अगस्त - स्वतंत्रता दिवस
- 18 अगस्त - रक्षाबंधन
- 25 अगस्त - जन्माष्टमी
- 5 सितंबर - गणेश चतुर्थी
- 12 सितंबर - ईद-उल-अजहा (बकरीद)
- 2 अक्टूबर - महात्मा गांधी जयंती
- 11 अक्टूबर - दशहरा
- 12 अक्टूबर - मोहर्रम
- 19 अक्टूबर- करवा चौथ
- 30 अक्टूबर - दीपावली
- 31 अक्टूबर - गोवर्धन पूजा
- 1 नवंबर - भाई दूज
- 6 नवंबर - छठ पूजा
- 13 दिसंबर- ईद- ए- मिलाद
- 25 दिसंबर - क्रिसमस

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

बिहार-झारखंड

28 दिसंबर, 2015–03 जनवरी, 2016

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

मीसा पर हां भी और ना भी

राजद में वही होता है, जो लालू प्रसाद की चाहत होती है. पार्टी और सरकार में हैसियत या लाभ का पद लालू-परिवार के किसी दावेदार के न होने पर ही दूसरे को मिलता है. यह राजद का दस्तूर बनता जा रहा है. यह पार्टी संविधान का अलिखित हिस्सा है. 2010 के विधानसभा चुनाव के बाद अब्दुल बारी सिद्दीकी को विधायक दल का नेता चुना गया था. उस चुनाव में राबड़ी देवी हार गईं थीं और लालू परिवार से कोई दावेदार नहीं था. ऐसी घटनाएं साल 1997 के बाद से ही राजद की परिपाटी बन गई हैं...

सुकान्त

राजनीति का पुराना चलन है–किसी मसले पर माहौल को परखना हो, तो कोई एक तुक्का छोड़ दो. राष्ट्रीय जनता दल के बिहार संगठन के अध्यक्ष पद को लेकर क्या इसी बैरोमीटर का इस्तेमाल हो रहा है? यह सवाल बिहार के राजनीतिक हलकों में पूछा जा रहा है. यहां तक कि राजद के नेता भी ऐसे ही सवाल कर रहे हैं. राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहम्मद इलियास हुसैन के बयान से राजद के आंतरिक हलके की हलचल का सारा मामला सामने आ गया है. पार्टी के बाहर माहौल भी बनने लगा है. मोहम्मद इलियास हुसैन ने बयान जारी किया कि मीसा भारती को प्रदेश राजद की कमान सौंप दी जाए– उन्हें प्रदेश राजद अध्यक्ष बनाया जाए. राजद सुप्रीमो के खास परिचित और सूबे के चर्चित अलकतरा घोटाले के आरोपित इलियास हुसैन की इस मांग का कई विधायकों ने खुल कर समर्थन किया है. इन विधायकों में लालू प्रसाद के सहायक से विधायक बने शक्ति सिंह यादव और अख्तरउल शाहीन प्रमुख हैं. पार्टी की निवर्तमान राज्य समिति के पदाधिकारियों की एक जमात ने भी इस मसले पर अपना मौन तोड़ा है, उन्होंने मीसा के नेतृत्व की मांग की है. विधायकों और पदाधिकारियों की इन जमातों ने अपने–अपने तरीके से मीसा भारती की नेतृत्व क्षमता की पुरकश तारीफ की है. मोहम्मद इलियास हुसैन ने अपने छोटे से बयान में कहा कि मीसा जी पढ़ी–लिखी और प्रतिभाशाली हैं. वह दल का किसी भी दूसरे से बेहतर ढंग से नेतृत्व करेंगी. लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और मीसा के छोटे भाई व सूबे के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इसका अपने तरीके से खंडन किया है. राबड़ी देवी ने दो–टूक शब्दों में कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है. यह सब निराधार है. तेजस्वी यादव ने मीडिया को ही नसीहत दे डाली. उनका कहना था मीडिया पिछले दिनों कई कंटेन्टलेस खबरें जारी करता रहा है. यह भी वैसी ही है. लेकिन इस मसले पर राजद सुप्रीमो अब भी मौन हैं. सुप्रीमो ही नहीं, पार्टी का हर बड़ा नाम इस मसले पर मौन है. सभी को शायद लालू प्रसाद के रुख की प्रतीक्षा है या सभी अनौपचारिक–औपचारिक चर्चा के अंत का इलहाम है. असलियत जो हो, इतना तो तय है कि बिहार प्रदेश राजद के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे का दूसरा कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है और नए साल के पहले महीने के पहले पखवाड़े में ही प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाएगा. डॉ. रामचंद्र पूर्वे दिसम्बर 09 में प्रदेश राजद के अध्यक्ष बने थे. डॉ. पूर्वे चुनाव हार गए थे और अब्दुल बारी सिद्दीकी के विधायक दल के नेता बन जाने के बाद उन्हें यह पद मिला था.

श्रीमती राबड़ी देवी और तेजस्वी प्रसाद यादव के प्रतिवाद की असलियत के बारे में कुछ भी कहना कठिन है. पर, राजद में होता है वही जो लालू प्रसाद की चाहत होती है. पार्टी और सरकार में हैसियत या लाभ का पद लालू–परिवार के किसी दावेदार के न होने पर ही दूसरे को मिलता है. यह राजद का दस्तूर बनता जा रहा है. पार्टी संविधान का अलिखित हिस्सा. 2010 के विधानसभा चुनाव के बाद अब्दुल बारी सिद्दीकी को विधायक दल का नेता बनाया गया था. उस चुनाव में राबड़ी देवी चुनाव हार गई थीं और लालू परिवार से कोई दावेदार नहीं था. राजद सुप्रीमो का 1997 से यह अनिवार्य गुण रहा है. उस साल चारा घोटाले में जब उनकी जेल यात्रा अदालत ने सुनिश्चित कर दी. अग्रिम जमानत के सारे रास्ते बंद हो गए, तो उन्होंने राबड़ी देवी को किचन से निकाल कर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया था. संकट के उन दिनों में लालू प्रसाद की राजनीतिक निर्भरता अपने दलीय राजनीतिक सहयोगियों पर रही. लेकिन सज़ायाफ्ता होने तक यह विवशता भी खत्म हो गई. संतान सक्षम मान लिये गए और इसीलिए रांची जेल में रहने के बावजूद किसी को उन्होंने अपना कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बनाया. पुत्र तेजस्वी के माध्यम से सारी राजनीति करते रहे– जेल से पार्टी चलाते रहे. खुद चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाने के कारण पाटलिपुत्र संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से रामकृपाल यादव की दावेदारी अस्वीकार कर मीसा भारती को उम्मीदार बनाया, उन्हें राजनीति में उतारा गया. लेकिन यह शुरुआत शुभ नहीं रही. विधानसभा चुनावों में पुत्रों के चुनाव लड़ने के लायक हो जाने के बाद वह दोनों को राजनीति में जमाने में लग गए, दोनों जीत भी गए और दोनों नीतीश कुमार की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री के बाद दूसरे और तीसरे नम्बर पर पदस्थापित भी हो गए हैं. राजद सुप्रीमो ने किसी और को न तो उप मुख्यमंत्री का पद दिया और न विधायक दल का नेता बनाया. बिहार के राजद विधानमंडल मंडल दल की नेता राबड़ी देवी हैं और विधानसभा में दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव हैं. यह किसी और का नहीं लालू प्रसाद का फैसला था, विधायकों ने उन्हें नेता चयनित करने के लिए अधिकृत कर दिया था, किसी का नाम नहीं दिया था. सो, सुप्रीमो ने दोनों सदनों में दल का नेता पद परिवार में ही रखा. आज के राजद में हैसियतवालों की सूची यह है: लालू प्रसाद राष्ट्रीय अध्यक्ष और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष, राबड़ी देवी विधान परिषद में दल की नेता, तेजस्वी प्रसाद यादव विधानसभा में नेता. मीसा भारती अब इस क्रम को आगे बढ़ाएंगी तो क्या खराबी है!

मीसा भारती के राजद प्रदेश अध्यक्ष बनने की उम्मीद है, बशर्ते लालू प्रसाद की चाहत यही हो. राजद के भीतर या बाहर मीसा भारती को लेकर चर्चा तेज है, पर राजद सुप्रीमो खामोश हैं. यह खामोशी रणनीतिक भी हो सकती है. महागठबंधन की सरकार में दोनों पुत्रों को नम्बर दो व तीन की हैसियत देने और तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री के साथ-साथ विधायक दल के नेता बनाए जाने पर राजद ही नहीं, उनके वोट-बैंक में भी गहरा असंतोष है.

परिवार और राजनीति के संदर्भ में लालू प्रसाद के लिए मुलायम सिंह यादव ही आदर्श हैं. परिवार से बचने के बाद ही किसी को कुछ दिया जाए, वह संगठन में हैसियत या सरकार में पद का मामला हो. बिहार राजद की कमान मीसा भारती के ही हाथ आएगा क्या? इस सवाल का जवाब देना फिलहाल कठिन हैं. पिछले कुछ वर्षों से राज्य की राजनीति में मीसा काफी रुचि ले रही हैं. संसदीय चुनाव लड़ने के पहले से ही. श्रीमती राबड़ी देवी 1997 की गर्मी में चौके से निकल कर सीधे राजभवन शपथ लेने पहुंचाई गईं और दो दिन बाद लालू प्रसाद को जेल जाना पड़ा तो मीसा भारती मां की छाया थीं. ऐसा एकाधिक बार हुआ. पिता को जमानत मिलने के बाद वह पर्दे के पीछे हो गईं. पिछले कुछ वर्षों में वह राजनीतिक तौर पर नए सिरे से सक्रिय हुई हैं. उन्हें तुरन्त राजनीतिक हैसियत दी जाए या नहीं, इस पर लालू परिवार में सदैव चर्चा रही है. लगता है, अब भी इस सवाल पर परिवार दुविधा मे है. लालू प्रसाद खुद भी कह चुके हैं कि पिता का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता है. परिवार में मतैक्य न होने की चर्चा बिहार के राजनीतिक हलकों में होती रही है. अधिकार सचेतन मीसा को जाननेवाले राजद नेताओं का मानना है कि दोनों भाइयों के इस उत्थान ने उन्हें काफी प्रेरित किया है और राजद में वह अपनी पकड़ बनाने के लिए तत्पर हैं, तो यह सहज है. लेकिन मीसा भारती की सीमा यह नहीं है, यह सीढ़ी है. राज्यसभा–विधान परिषद के भावी चुनावों में बतौर प्रत्याशी उनके नाम का सामने आना भी तय है. जिन तबकों से उन्हें अध्यक्ष बनाने की मांग की जा रही है, वही तबका उस समय उम्मीदवारी के लिए उनके नाम को सामने सामने कर सकता है. लेकिन उस समय लालू प्रसाद के घर में क्या होगा, यह कहना कठिन है. हां, पार्टी नेताओं की प्रतिक्रिया देखने लायक होगी. राजद नेताओं को याद है रामानुज प्रसाद के साथ दल का सुलूक. 2010 के विधानसभा चुनावों में राबड़ी देवी हार की आशंका से पीड़ित थीं और वह राघोपुर के अलावा एक और सहज सीट से चुनाव लड़ना चाहती थीं. इसके लिए सोनपुर की सीट खाली करवाई गई और वहां के विधायक रामानुज प्रसाद से विधान परिषद की उम्मीदवारी देने का वायदा किया गया. श्रीमती राबड़ी देवी राघोपुर से तो चुनाव हार ही गईं, सोनपुर में भी पराजित हुईं. विधानसभा में स्थिति यह रही कि किसी तरह जोड़–तोड़ से विधान परिषद की एक सीट जीती जा सकती थी. लेकिन 2012 के विधान परिषद चुनाव के समय रामानुज या किसी अन्य को दावेदारी पेश करने का अवसर ही नहीं दिया गया. चुनाव से पहले ही राबड़ी देवी को उम्मीदवारी देने की घोषणा कर दी गई. यह लालू प्रसाद की दशकों पुरानी राजनीतिक शैली है. 1990 के दशक में उनका पलड़ा सदैव सालों के पक्ष में झुका रहता था. इन नाते रिश्तेदारों को उन्होंने सब कुछ बख़्शा, भले ही अब उनके नाम सुनना न पसंद करते हों.

इस पृष्ठभूमि में मीसा भारती के राजद प्रदेश अध्यक्ष बनने की उम्मीद है, बशर्ते लालू प्रसाद की चाहत यही हो. राजद के भीतर या बाहर मीसा भारती को लेकर चर्चा तेज है, पर राजद सुप्रीमो खामोश हैं. यह खामोशी रणनीतिक भी हो सकती है. महागठबंधन की सरकार में दोनों पुत्रों को नम्बर दो व तीन की हैसियत देने और तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री के साथ–साथ विधायक दल के नेता बनाए जाने पर राजद ही नहीं, उनके वोट–बैंक में भी गहरा असंतोष है. लालू प्रसाद के इस पुत्र–प्रेम को वोट–बैंक की हिस्से की हकमारी के तौर पर लिया जा रहा है. दल के बुजुर्ग नेताओं के साथ–साथ युवा नेताओं में भी रोष है कि उनके हिस्से का अवसर खानदानी वर्चस्व को स्थापित करने में लगया जा रहा है. रघुवंश प्रसाद सिंह, जगदानंद सिंह, प्रभुनाथ सिंह, तस्लीमुद्दीन, रामचंद्र पूर्वे, अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे लोगों की घुटन बढ़ना जरूरी है. निष्ठा और अनुभव के ऐसे प्रतिदान की तो उन्होंने अपेक्षा नहीं की थी. इस घुटन का कोई महत्व है क्या? ऐसे निर्गुन घुटन का कोई अर्थ भी नहीं है. वस्तुतः क्षेत्रीय राजनीति के नायकों ने एक नई तरह की राजशाही कायम की है– जाति, धर्म भाषा के नाम पर समाज को जगाकर शासक खानदान बनाने का नया चलन चलाया है. यह दक्षिण से उत्तर तक चल रह है. पंजाब, जम्मू–कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, झारखंड, ओडिशा, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि राज्यों में यह तेजी से विकसित हो रहा है. राजद इसी राजनीति को खाद–पानी दे रही है. ऐसी राजनीतिक शैली में परिवार से बाहर के नेता, कार्यकर्ता की क्या कोई बिसात है? शायद नहीं. कम से कम तब तक नहीं, जब तक डर और आतंक मतदान का पैमाना है. इस राजनीतिक माहौल में उन्हीं के लिए अवसर है जो खानदानी हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

धनबाद

पर्यावरण नियमों का खुलेआम उल्लंघन

शैलेन्द्र चौहान

पूरे झारखंड प्रदेश को प्रदूषण ने अपने आगोश में जकड़ रखा है. कोल इंडिया (भारत सरकार) की अनुषांगिक कंपनियां, जो धनबाद बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, गुमला, रामगढ़, रांची, पलामू, फुसरो, बेरमों इत्यादि जिले में फैली हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए लागू नियमों का धता बताते हुए प्रदूषण फैला रही हैं. जबकि इनके संचालक हैं बी.सी.सी.एल, सी.सी.एल एवं ई.सी.एल.

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को अगर पर्यावरण का दुश्मन कहा जाये तो गलत नहीं होगा. क्योंकि लगभग 28 लाख की आबादी वाले धनबाद जिले का एक तिहाई भाग प्रदूषण के चपेट में है. प्रदूषण के कारण लोगों में गंभीर बीमारियां फैल रही है. इसका मुख्य कारण है बी.सी.सी.एल. के अंदर उत्खनन कर रही आउट सोर्सिंग कंपनियां जो आउट सोर्सिंग द्वारा नियम का उल्लंघन कर कोयला एवं ओ.बी. यहां के निकासी कर रहे हैं और बुरी तरह से प्रदूषण फैलाने का काम कर रही हैं. इससे निकलने वाले धूल कण से पर्यावरण के साथ ही लोगों के सेहत पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है. इन कंपनियों पर न तो खान सुरक्षा महानिदेशालय बी.सी.सी.एल नियंत्रण कर रही है और न ही राज्य सरकार का झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ध्यान दे रही है. इसके कारण आउट सोर्सिंग कंपनियों में सरकारी नियमों का कोई डर नहीं है. प्रदूषण के खिलाफ लोदना क्षेत्र सं. 10 के आस-पास रहने लोगों ने दर्जनों बार आंदोलन किया है. आन्दोलनकारियों ने कई बार काम तक बंद करा दिया मगर कोई सुनवाई नहीं हुई. सरकार या बी.सी.सी.एल. द्वारा इस बड़ी समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है. बी.सी.सी.एल में जितनी भी आउट सोर्सिंग कंपनियां चल रही हैं, कोई भी सरकार द्वारा निर्धारित कानून का पालन नहीं कर रही हैं. आउट सोर्सिंग कंपनियों में भारी-भारी मशीनों एवं वाहन दुरुस्त नहीं रहने के कारण, और यहां पर कोयला उत्खनन ओ.बी. बर्डेन की निकासी की जा रही है, जिससे प्रतिदिन इसके उड़ने वाले धूल-कणों से लोगों का जीना मुहाल हो गया है. घर के अंदर रसोई से लेकर पूरा घर-आंगन धूल-कणों से भर जाता है. इससे क्षेत्र में रहने वालों की परेशानियों का अंदाजा लगाया जा सकता है. इस धूल-कण से पूरा जन-जीवन प्रभावित है. बी.सी.सी.एल के अंतर्गत जितनी भी आउट सोर्सिंग कंपनियां चल रही हैं. कोई भी सरकार द्वारा निर्धारित कानून का पालन नहीं कर रही हैं. दिनांक 6.9.2015 को डी.वाई.एफ.आई के प्रजा पासवान ने खान सुरक्षा महानिदेशालय को अविनाश ट्रांसपोर्ट

आउटसोर्सिंग के खिलाफ प्रदूषण फैलाने की शिकायत भी की थी. शिकायत के आलोक में डी.जी.एम.एस ने उक्त आउटसोर्सिंग कंपनी के खिलाफ खान अधिनियम 1952 के अंतर्गत कार्रवाई की बात कही. दिनांक 9.9.2015 को साउथ तिसरा गोल्डेन पहाड़ी के ग्रामीणों ने अविनाश ट्रांसपोर्टिंग आउटसोर्सिंग परियोजना का काम रोक दिया. कारण ओ.बी. डम्प के कारण भारी मात्रा में जले हुये कोयले की राख बड़ी मात्रा में आस-पास के क्षेत्रों में गिरकर बहुत प्रदूषण फैला रहा है, जिससे आम जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है. घरों में केवल धूल कण ही नजर ही आता है. पानी का छिड़काव नहीं होने के कारण हालत बद से बदतर हो गया है. घर के बाहर भी स्थिति गंभीर बनी हुई है. सड़क पर लोगों के लिए दोपहिया वाहन चलाना मुश्किल हो रहा है. धूल कण सीधे आंख और मुंह में घुस जाता है. परियोजना का काम बंद हो जाने के बाद कंपनी के मातहत अधिकारियों की तंद्रा भंग हुई. मौके पर डी.जी.एम.एस से लेकर थाने के लोग पहुंचे और लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया, मगर बात नहीं बनी. क्षेत्र के आक्रोशित लोगों ने खान सुरक्षा महानिदेशक का पुतला दहन किया. मार्क्सवादी पार्टी के लोगों ने जमकर बवाल काटा और आरोप लगाया कि ये सब डी.जी.एम.एस. एवं बी.सी.सी.एल के अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है. प्रदूषण रोकने की मांग पर अधिकारी आश्वासन तो देते हैं मगर कार्रवाई नहीं होती है. आन्दोलन के बाद डी.जी.एम.एस. का दौरा होता है. डी.जी.एम.एस के उप निदेशक संजीव राय ने मौके पर साफ कहा है कि आउट सोर्सिंग कंपनियां पहले प्रदूषण रोकने का काम करें फिर काम चालू करें. मामले की गंभीरता को देख संजीव राय ने काम बंद करने का आदेश दिया और कहा कि जब तक परियोजना में प्रदूषण की रोकथाम की उचित व्यवस्था नहीं होती, पानी का छिड़काव पर्याप्त मात्रा में नहीं होता तब तक अगले आदेश तक प्रबंधक काम बंद रखें. लोदना जी.एम. प्रकाश चन्द्रा को भी काम बंद रखने को कहा. कोल डम्प पर मिट्टी डालने का आवश्यक दिशा-निर्देश दिया. चार दिन काम बंद रहा. पुनः दिनांक 12.9.2015 डी.जी.एम.एस का डस्ट सिंफार एवं आई.एस.एम द्वारा पर्यावरण में फैले धूल-कणों की स्टडी रिपोर्ट सौंपने के बाद काम शुरू करने आदेश दिया. स्टडी रिपोर्ट में न्यूनतम धूलकण से 30-31 गुणा कम पाई गई. रिपोर्ट में मात्र 0.5 मिलीग्राम प्रति क्यूबिक मीटर धूलकण पाया गया, जो की काफी कम है. मगर आस-पास के रहने वाले लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है. धूलकण की मात्रा कम से कम 8 प्रतिशत प्रति क्यूबिक मीटर यहां के वातावरण में फैला हुआ है जो यहां स्पष्ट देखा जा सकता है. काम चालू होने के बावजूद भी नियमों को अनदेखा किया जा रहा है. आज भी कंपनी द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण को देखा जा सकता है. लोदना क्षेत्र सं. 10 में आउट सोर्सिंग कंपनियों में अविनाश ट्रांसपोर्ट, एटवाल आउटसोर्सिंग, श्री साई, ए.टी. देव प्रभा, आर.के. माइनिंग द्वारा कोयला उत्खनन एवं ट्रांसपोर्टिंग का कार्य किया जाता है. प्रदूषण के खिलाफ बी.सी.सी.एल प्रबंधन द्वारा हर वर्ष इसके रोकथाम के लिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है. आयोजन के दौरान डस्ट जेनरेटिंग स्रोत, लोडिंग, अनलोडिंग एवं हॉल रोड, कोल ट्रांसपोर्टेशन रोड, सी.एच.पी, रेलवे साइडिंग, ब्लास्टिंग, ड्रिलिंग, ओ.बी. डम्प इत्यादि पर डस्ट समप्रेशन, जल छिड़काव की व्यवस्था करना एवं तिरपाल से ढक कर कोयले की ढुलाई करना, सघन वृक्षारोपण का कार्य करने, का पाठ पढ़ाया जाता है. मगर ऐसा होता नहीं है. पूरे बी.सी.सी.एल. के अन्तर्गत 12 क्षेत्र पड़ते हैं. हर क्षेत्र में 7-8 आउट सोर्सिंग कंपनियां द्वारा कोयला उत्खनन किया जाता है. इससे सहज ही समझा जा सकता है कि वायु प्रदूषण का क्या हाल होगा? प्रदूषण से होने वाले खतरों पर अगर एक नजर दौड़ाई जाय तो यहां के लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है. लोगों को अस्थमा, कैंसर, टी.बी. जैसी गंभीर बिमारियां अपने चपेट में ले रही हैं. झारखंड मुक्ति मोर्चा के राज्यसभा सांसद संजीव कुमार ने लोगों की परेशानियों को देखते हुए केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर को पत्र लिखकर झारखंड की प्रदूषण की समस्या की जानकारी दी. सांसद ने आग्रह किया कि कोयला की परिवहन एवं ओ.बी. बर्डेन पर उचित ध्यान दिया जाये. कोयले की ढुलाई के लिए ट्रकों के बदले रेलवे से व्यवस्था की जाये. दिनांक 18.9.2015 को धनबाद के डी.सी. कृपानंद झा ने कोयला खनन में लगी कंपनियों से माइनिंग एरिया में पौधा रोपण अभियान तेज करने की अपील की है. समाहरणालय में औद्योगिक क्लस्टर पर आयोजित बैठक में शहर में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता व्यक्त की गई. समय-समय पर प्रदूषण के रोक-थाम पर सेमिनार होते हैं, इसके बावजूद भी पौधा-रोपण कार्य नहीं होते हैं.

गौरतलब है कि पर्यावरण को बचाने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पर्यावरण मंत्रालय गंभीर है. किसी भी प्रोजेक्ट के 5 किलोमीटर के दायरे के बाहर एवं 10 किलोमीटर के दायरे में नियम का उल्लंघन करने पर 10 करोड़ से 15 करोड़ जुर्माना का प्रावधान है. जिसे 20 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है. लगातार पर्यावरण के नुकसान होने पर रोजाना एक करोड़ की राशि वसूली जा सकती है. नुकसान नहीं रुकता है तो 70 लाख की राशि प्रतिदिन अतिरिक्त वसूली जा सकती है. बावजूद कोल इण्डिया के बीसीसीएल, सीसीएल, ईसीसीएल के अधीन चल रही कम्पनियों के लेसमात्र भी डर नहीं है.

इस संदर्भ में राष्ट्रीय दलों के नेताओं सहित आम जन आन्दोलन शुरू करने के मूड में नजर आ रहे हैं. भाजपा के एससी एसटी विभाग के मंत्री महावीर पासवान, उपेन्द्र सिंह, सांसद अजय निषाद, बिहारी लाल चौहान, मुन्द्रिका पासवान, विद्याधर सिंह, राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के महामंत्री ललन चौबे, सतेन्द्र चौहान, रामशेर आलम, मुनीलाल राम, धर्मेन्द्र सिंह, अजय पासवान, आरिफ आलम, बिहार कोलियरी कामगार यूनियन के सुरेश पासवान, सुरेश गुप्ता, पार्षद नन्दलाल पासवान, संजय यादव, सपा के रविन्द्र पासवान, महेश निषाद, माले नेता अनिल पासवान, भजोहरि महतो, आजसू के अशोक चौहान, बीरू निषाद, बिरसा मुण्डा सेना के विनोद पासवान आदि प्रदूषण के विरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलन के मूड में हैं.■

शिकायत के आलोक में डी.जी.एम.एस ने उक्त आउटसोर्सिंग कम्पनी के खिलाफ खान अधिनियम 1952 के अन्तर्गत कार्रवाई की बात कही. दिनांक 9.9.2015 को साउथ तिसरा गोल्डेन पहाड़ी के ग्रामीणों ने अविनाश ट्रांसपोर्टिंग आउटसोर्सिंग परियोजना का काम रोक दिया. कारण ओ.बी. डम्प के कारण भारी मात्रा में जले हुये कोयले की राख बड़ी मात्रा में आस-पास के क्षेत्रों में गिरकर बहुत प्रदूषण फैला रहा है, जिससे आम जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है. घरों में केवल धूल कण ही नजर ही आता है. पानी का छिड़काव नहीं होने के कारण हालत बद से बदतर हो गये हैं. घर के बाहर भी स्थिति गंभीर बनी हुई है.

feedback@chauthiduniya.com

मानसिक रूप से सशक्त रहें
ariskon Pharma Pvt.Ltd.
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.
डॉ. तरूण शरण (नवादा)
Carbo-XT Drops
A Colic Drops
Siliplex Syp.
Oflogyl-OZ Susp.
Acoba Syp.
NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma

बेगूसराय

व्यक्तित्व ने दिलाई जीत

मटिहानी विधान सभा सीट पर जदयू का कब्जा था और इस बार भी उसी का कब्जा रहा. जदयू नेता एवं निवर्तमान विधायक नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह को महागठबंधन ने अपना प्रत्याशी बनाया. बोगो सिंह इस क्षेत्र से प्रथम बार निर्दलीय विधायक निर्वाचित हुए थे. दो बार जदयू के टिकट पर जीत हासिल की. इस बार भी जदयू के टिकट पर विजय प्राप्त की है.

सुरेश चौहान/रघुवीर झा

बेगूसराय के मटिहानी विधान सभा क्षेत्र में पूर्वानुमान के मुताबिक कांटे का संघर्ष नहीं हुआ. सही चुनाव प्रबंधन के अभाव एवं पार्टीजनों के भीतरघात के कारण विधान सभा चुनाव में भाजपा को मुंह की खानी पड़ी. मटिहानी विधान सभा क्षेत्र को भूमिहार बहुल कहा जाता है. इस कथन में सच्चाई भी है, आजतक इस विधान सभा क्षेत्र से दलित-महादलित, पिछड़ा-अतिपिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग से कोई भी विधायक नहीं बन पाया है. भूमिहार-ब्राह्मण का ही इस सीट पर कब्जा रहा है. क्षेत्र में कहीं भी मोदी-भाजपा की लहर दिखायी नहीं पड़ी. जबकि इसी विधान सभा क्षेत्र में नरेन्द्र मोदी की विशाल रैली भी आयोजित की गयी थी.

मटिहानी विधान सभा सीट पर जदयू का कब्जा था और इस बार भी इसी का कब्जा रहा. जदयू नेता एवं निवर्तमान विधायक नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह को महागठबंधन ने अपना प्रत्याशी बनाया. बोगो सिंह इस क्षेत्र से प्रथम बार निर्दलीय विधायक निर्वाचित हुए थे. दो बार जदयू के टिकट पर जीत हासिल की. इस बार भी जदयू के टिकट पर विजय प्राप्त की है. इस जीत के साथ ही बोगो सिंह ने लगातार चार बार विजयी होकर जीत का चौका लगाया है. दूसरी ओर भाजपा ने सर्वेश कुमार को चुनाव मैदान में उतारा. सर्वेश कुमार भारत सरकार के लोक सेवक पद से त्यागपत्र देकर 2010 में निर्दलीय चुनाव लड़े थे और सम्मानजनक मत प्राप्त किए थे. बाद में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली. सर्वेश कुमार के अलावा इस क्षेत्र से भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय कुमार. भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष ललन प्रसाद सिंह, भाजपा विनिवेश मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक कुन्दन कुमार भी प्रबल दावेदार थे. प्रदेश नेतृत्व के आश्वासन पर संजय कुमार जिलाध्यक्ष पद से त्यागपत्र देकर अपनी दावेदारी पेश की थी. क्षेत्र में प्रचार अभियान भी चला रखा था. ललन प्रसाद सिंह एवं कुन्दन कुमार भी क्षेत्र में काफी सक्रिय होकर चुनाव प्रचार में जुट गए थे. लेकिन सर्वेश कुमार को पार्टी टिकट मिलते ही क्षेत्र में फिजा बदल गयी. ललन प्रसाद सिंह ने तो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन पर्चा भी दाखिल कर दिया. लेकिन प्रदेश नेतृत्व के दबाव में नामांकन वापस ले लिया. दूसरी ओर सर्वेश कुमार का चुनाव प्रबंधन ठीक नहीं रहा और भाजपा कैडर एवं भाजपा समर्थक मतों को संगठित नहीं रख पाए. दूसरी ओर बोगो सिंह का चुनाव प्रबंधन काफी प्रभावी रहा जिसके कारण उन्हें महागठबंधन के घटक दलों कांग्रेस एवं राजद का सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ. इसके साथ ही विधायक रहते हुए जनता के बीच बोगो सिंह की सर्वसुलभता एवं मिलनशीलता काम आयी.

महागठबंधन के जदयू प्रत्याशी निवर्तमान विधायक नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह ने राजग के भाजपा प्रत्याशी सर्वेश कुमार को 22687 मतों से पराजित कर लगातार चौथी बार विधान सभा पहुंचने में सफलता प्राप्त की. बोगो सिंह को 89292 एवं सर्वेश कुमार को 66605 मत प्राप्त हुए.■

बोगो सिंह

सर्वेश कुमार

feedback@chauthiduniya.com

सीतामढ़ी

नयी उम्मीदों के साथ मना जिला स्थापना दिवस समारोह

आजादी के बाद से ही राज्य से लेकर केंद्र तक की सरकारों में इस जिले की कई राजनीतिक हस्तियों का वर्चस्व रहा. मगर सच्चाई है कि किसी ने भी जिले को राष्ट्रीय फलक पर लाने की दिशा में समुचित पहल नहीं की. नतीजा है कि अब तक यह जिला उपेक्षा का दंश झेल रहा है. 1972 में जिले का दर्जा मिलने के बाद भी सीतामढ़ी का सर्वांगीण विकास दशकों बाद तक नहीं हुआ. ऐतिहासिक विरासतों की रक्षा एवं उद्योग व रोजगार का विकास भी एक गंभीर चुनौती बना रहा. पिछले तकरीबन साढ़े चार दशक के इतिहास में पहला मौका है जब सामाजिक जागृति का माहौल देखने को मिल रहा है. इस तथ्य का जीवंत उदाहरण 2014 का संपन्न लोकसभा एवं 2015 का विधानसभा का चुनाव है. मतदान प्रतिशत में इजाफे का श्रेय जिला प्रशासन की सजगता व सामाजिक जागरूकता को जाता है.

वाल्मीकि कुमार

feedback@chauthiduniya.com

जगत जननी मां जानकी की पावन जन्म स्थली होने के कारण सीतामढ़ी धार्मिक दृष्टिकोण से अतिमहत्वपूर्ण जिला माना गया है. यहां के प्रमुख धर्म स्थलों में जानकी जन्म स्थली पुनौरा धाम, शहर अवस्थित रजत द्वार जानकी मंदिर, दक्षिणमुखी सिद्ध महावीर मंदिर, हलेश्वर स्थान, पंथपाकर, अन्हारी, दमामी मठ, बाबा मानकेश्वर नाथ महादेव मंदिर, अर्द्धनारीश्वर महादेव मंदिर रीगा, 123 साल पुरानी सीतामढ़ी गौशाला, प्रचीन सिद्ध बाबा का आश्रम समेत कई स्थान श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बना है. वहीं दूसरी ओर सिंगरहिया स्थित श्रृंगी ऋषि का आश्रम, परसौनी के परशुरामपुर में भगवान परशुराम की पावन तपोस्थली भी जिले के इतिहास के अहम हिस्सा के रूप में है.

आजादी के बाद से ही राज्य से लेकर केंद्र तक की सरकार में इस जिले की कई राजनीतिक हस्तियों का वर्चस्व रहा. मगर सच्चाई है कि किसी ने भी जिला को राष्ट्रीय फलक पर लाने की दिशा में समुचित पहल नहीं की. नतीजा है कि अब तक यह जिला उपेक्षा का दंश झेल रहा है. 1972 में जिले का दर्जा मिलने के बाद भी सीतामढ़ी का सर्वांगीण विकास दशको बाद तक नहीं हुआ. ऐतिहासिक विरासतों की रक्षा एवं उद्योग व रोजगार का विकास भी एक गंभीर चुनौती बना रहा. पिछले तकरीबन साढ़े चार दशक के इतिहास में पहला मौका है जब सामाजिक जागृति का माहौल देखने को मिल रहा है. इस तथ्य का जीवंत उदाहरण 2014 का संपन्न लोकसभा एवं 2015 का विधानसभा का चुनाव है. मतदान प्रतिशत में इजाफे का श्रेय जिला प्रशासन की सजगता व सामाजिक जागरूकता को जाता है. पंचायतीराज व्यवस्था के तहत महिला व दलित-पिछड़ों को समाज में सम्मानजनक स्थान दिया गया है. पंचायतीराज के अलावा नगर परिषद, नगर पंचायत, जिला परिषद, विधानसभा व लोकसभा तक महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में कामयाबी पायी है. कला के क्षेत्र में जिले के चर्चित शिल्पी फणी भूषण विश्वास ने लंबे प्रयास के बाद स्थानीय रेलवे स्टेशन परिसर में 'सीता प्राकट्य' झांकी को स्थापित कराने के साथ ही जिला को कला के क्षेत्र में भी पहचान दिलाने का काम किया है.

जिला मुख्यालय डुमरा के कैलाशपुरी निवासी दूरसंचार विभाग के कर्मी गगन प्रसाद ने भी जिले के लोगों में सफाई के प्रति जागरूकता का प्रवाह कर अपनी पहचान बनाने में कामयाबी पायी है. शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत हद तक जागृति आयी है. जिले के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं ने मैट्रिक व इंटर तक के परीक्षा फल में बेहतर परिणाम लाकर गौरवान्वित करने का काम किया है. वहीं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता का परचम लहराने में सफलता पायी है. स्वास्थ्य विभाग की स्थिति में बदलाव का नतीजा है कि जिले के लगभग सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो रही है. प्रशासनिक सजगता का आलम है कि जिले में विकलांग पुनर्वास केंद्र की स्थापना की दिशा में पहल की गयी है. इससे जिले के विकलांगों को आशातीत सहयोग मिलने की पूरी इम्मीद है.

पिछले 11 दिसंबर को जिला प्रशासन द्वारा जिला के 44 वें स्थापना दिवस के अवसर पर दो दिवसीय समारोह का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में प्रशासनिक पदाधिकारियों की पूर्ण मौजूदगी रही. कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में जिला पदाधिकारी राजीव रौशन, पुलिस अधीक्षक हरि प्रसाथ एस, डीडीसी ए रहमान व एसडीओ सदर संजय कृष्ण के अलावा विधान पार्षद राज किशोर सिंह कुशवाहा, दिलीप राय, पूर्व मंत्री सह बाजपट्टी विधायक डॉ. रंजूगीता, रीगा विधायक अमित कुमार टुन्ना, परिहार विधायक गायत्री देवी, रुन्नीसैदपुर विधायक मंगीता देवी व जिला परिषद अध्यक्ष इंद्रानी देवी ही बतौर जनप्रतिनिधि मौजूद रही.

विशेष रूप से स्थानीय सांसद राम कुमार शर्मा व तिरहुत स्नातक क्षेत्र के विधान पार्षद देवेशचंद्र ठाकुर की अनुपस्थिति लोगों को काफी खलती रही. समारोह के दौरान स्वच्छ जिला, स्वस्थ्य जिला कार्यक्रम के तहत मैराथन दौर, रक्तदान शिविर का आयोजन, खेल, वाद-विवाद, नृत्य व संगीत के अलावा कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया. सांस्कृतिक कार्यक्रमों में स्कूली बच्चों ने जहां लोकगीत व संगीत के साथ ही भाव-नृत्य से जिला के सांस्कृतिक विरासत में जीवंतता लाने का हर संभव प्रयास किया. वहीं जिले के साहित्यकार ई. सचिंद्र कुमार हीरा, उमा शंकर लोहिया, सुरेश वर्मा, तौहीद अश्क ने गीतकार गीतेश की अगुवाई में साहित्यिक चेतना का प्रवाह कर लोगों में सामाजिक एकता व भाईचारा का पैगाम दिया.

सीतामढ़ी जिले में पिछले एक दशक में कई यादगार विकास कार्यो का कार्यान्वयन सरकारी स्तर पर किया गया है. राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-77 पर बाढ़ से चार माह तक परेशान रहने वाले लोगों को कटौझा में बागमती नदी पर रामवृक्ष बेनीपुरी सेतु और एनएच - 104 के डुब्बा घाट पर पुल निर्माण से राहत राहत मिली है. वहीं बैरगनिया में बागमती नदी पर सूबे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ढेंग में वंशी चाचा सेतु का निर्माण करा कर लोगों की भावना का सम्मान किया है. सीता व रामायण सर्किट के तहत प्रमुख धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार व विकास कार्य जारी है. रामायण सर्किट से जोड़कर देश के पर्यटन स्थलों की सूचि में जिले का नाम जुड़ने का मार्ग भी स्थानीय पूर्व भाजपा विधायक सह पूर्व पर्यटन मंत्री सुनील कुमार पिंटू के अथक प्रयास से प्रशस्त होता दिख रहा था. परंतु संपन्न चुनाव में हुए सत्ता परिवर्तन ने उम्मीद को अब अधर में लटका दिया है.

जहां तक जिले के ऐतिहासिक धरोहरों की रक्षा का सवाल है तो षहर स्थित प्राचीन सनातन धर्म पुस्तकालय को हाल के वर्शो में व्यवस्थित करने की दिशा में पहल की गयी है. परंतु जिला मुख्यालय डुमरा स्थित ऐतिहासिक गीता भवन की बदहाली को दूर करने की दिशा में अब तक किसी भी प्रकार का पहल नही किया जा सका है. आलम है कि सैकड़ों साल पुरानी पुस्तकों के अलावा अन्य दुर्लभ कागजातों की सुरक्षा गंभीर चुनौती बनी है. जिला के बीच से प्रवाहित होने वाली लक्ष्मणा नदी की धारा में पिछले कुछ सालों से अवरुद्ध जल प्रवाह को चालू कराने को लेकर स्थानीय राजनीतिक व सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा आंदोलन किया जाता रहा है. मगर अब तक नतीजा नदी की धारा का प्रशासनिक मुआयना से आगे नहीं निकल सका है. वर्तमान जिला पदाधिकारी इस मामले को गंभीरता पूर्वक ले रहे हैं. अबकी बार नतीजा मिलने की उम्मीद लोगों में जगी है. विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेले के लिए चर्चित रहा सीतामढ़ी का प्रसिद्ध राम नवमी व विवाह पंचमी मेला के अस्तित्व पर भी पिछले कुछ दशक से संकट के बादल मंडराने लगे हैं. सरकारी प्रावधानों की अनदेखी कर मेला परिक्षेत्र की जमीन को वृहद स्तर पर बेच दिया गया है. नतीजतन अब मेला महज एक औपचारिकता तक सिमट कर रह गया है.

सीतामढ़ी जिले में पिछले एक दशक में कई यादगार विकास कार्यो का कार्यान्वयन सरकारी स्तर पर किया गया है. राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-77 पर बाढ़ से चार माह तक परेशान रहने वाले लोगों को कटौझा में बागमती नदी पर रामवृक्ष बेनीपुरी सेतु और एनएच - 104 के डुब्बा घाट पर पुल निर्माण से राहत राहत मिली है. वहीं बैरगनिया में बागमती नदी पर सूबे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ढेंग में वंशी चाचा सेतु का निर्माण करा कर लोगों की भावना का सम्मान किया है. सीता व रामायण सर्किट के तहत प्रमुख धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार व विकास कार्य जारी है.

पडोसी देश नेपाल की सीमा से लगे सीतामढ़ी जिले में अब तक रोजगार के लिए औद्योगिक इकाई की स्थापना राजनीतिक घोषणाओं के बाद भी नहीं की जा सकी है. बतौर केंद्रीय रेलमंत्री रहते पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने भी सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन परिसर में दशकों पूर्व स्लीपर फैक्ट्री निर्माण को लेकर शिलान्यास किया था. मगर अब तक इस दिशा में कोई पहल नहीं की जा सकी है. 70 के दशक में शहर के गौशाला चौक के समीप एक पेपर मिल की स्थापना की कवायद की गयी. परंतु कतिपय कारणों से उक्त योजना महज चंद सालों में ही लोगों के जेहन से गुम हो गयी. दूसरी ओर औद्योगिक क्षेत्र में सूत फैक्ट्री के निर्माण की चर्चा भी जोरों पर रही. परंतु भवन निर्माण के बाद भी नतीजा षून्य ही रहा. जिले में स्थापित एक मात्र औद्योगिक इकाई रीगा सुगर कंपनी लिमिटेड गन्ना इत्पादक किसानों के लिए मौजूद है. बेरोजगारी का आलम है कि प्रति वर्श रोजगार की तलाष में जिले से युवाओं का पलायन महानगरों में जारी है. जिले के किसानों के मार्गदर्षन के लिए पूर्व सांसद नवल किषोर राय के प्रयास से पुपरी के बलहा मकसूदन में साल 2006 से कृशि विज्ञान केंद्र संचालित है. जहां किसानों को समय-समय पर कृशि संबंधी जानकारी वैज्ञानिकों द्वारा दी जाती है. आपदा से लेकर सामान्य दिनों तक आमजनों की हर संभव सेवा को तत्पर भारतीय रेडक्रास सोसायटी, लायंस क्लब सीतामढी बेस्ट, लायंस क्लब सीतामढी प्रियदर्षिनी, लायनेस क्लब सीतामढी बेस्ट, लायंस क्लब यूथ, लायंस क्लब सीतामढी सेंट्रल, मां जानकी जनसेवा ट्रस्ट, अखिल भारतीय मारवाडी महिला सम्मेलन, बिहार प्रदेषिक मारवाडी सम्मेलन, रौनियार युवा मंच, बिहायुत युवा मंच, चैंबर ऑफ कॉमर्स, अग्रसेन मंच, ब्राह्मण पंचायत समेत अन्य संगठनों की भूमिका सराहनीय रही है.■

feedback@chauthiduniya.com

एक नज़र

सम्मानित हुए उमाशंकर

दिल में जज्बा हो तो सभी व्यस्तताओं के बीच भी हम समाज के लिए सकारात्मक प्रयास करके दुखी लोगों के आंसू पोछ खुशी के पल दे सकते हैं. इसे सत्य कर दिखाया है उमाशंकर राम ने. समाज के दबे कुचले लोगों के जीवन में खुशियों के रंग भरने और शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए उमाशंकर को भारतीय दलित साहित्य अकादमी द्वारा डॉ अम्बेडकर उत्कृष्ट सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. 12 दिसम्बर को दिल्ली रिंग रोड स्थित झारोडा गांव के पंचशील आश्रम में आयोजित भारतीय दलित साहित्य अकादमी के 31वें राष्ट्रीय सम्मेलन में उमाशंकर राम को दलित समुदाय के विकास हेतु किये गये. सामाजिक कार्यों के लिए डॉ. अम्बेडकर उत्कृष्ट सेवा सम्मान से पुरस्कृत किया गया. मौके पर अकादमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. एसपी सुमनाक्षर सहित बड़ी संख्या में गणमान्य उपस्थित थे. उमाशंकर फिलवक्त बिहार सरकार के गृह विभाग में डिप्टी सेक्रेट्री के पद पर कार्यरत हैं.■

- राकेश कुमार

बचपन को बचाने में जुटे प्रद्युम्न

समाज की दिशा और दशा बदलने के लिए प्रघुम्न कुमार सिंह भावी पीढ़ी के भविष्य को संवारने में लगे हैं. बचपन ए प्ले स्कूल के निदेशक प्रद्युम्न ने बताया कि खगड़िया में बड़े स्कूल तो बहुत है लेकिन नौनिहालों के लिए ऐसा एक भी स्कूल नहीं है जिससे बच्चों का बहुमुखी विकास हो और अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजकर निश्चिंत होकर कार्य करने के लिए जा सकें. आमलोगों की समस्याओं को देखते हुये स्कूल खोलने की निर्णय लिया है. उन्होनें कहा कि यहां गरीब और अमीर के बच्चे समान रूप से रहेंगे. बच्चों को खेल-खेल में हीं पढ़ाने की व्यवस्था है. खगड़िया जिले में पानी में आयरन अधिकता को देखते हुए प्रद्युम्न ने मिनरल वाटर का प्लांट भी लगाया. इसमें आशातीत सफलता नहीं मिलने के बाद भी वे इसे बढ़ा रहे हैं. उन्होंने कहा कि जिले को शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाने के लिए सीबीएसई मानको की एक बड़ा स्कूल खोलने की योजना है. इसके योजना के लिए जमीन मिल गई है.■

- गीता कुमार

समस्या आपकी समाधान Dr. Advice से

प्रश्न : डॉ. साहब मेरी उम्र 62 साल की है। उठने बैठने में काफी परेशानी होती है, जोड़ों में अकड़न रहता है। कोई आर्युवेदिक दवा बतायें। दीनानाथ सिंह, रांची
उत्तर : आप REPL निर्मित ऑर्थोविट कैप्सूल एक कौप्सूल सुबह और एक कैप्सूल रात को सोते सम लें और ऑर्थोविट ऑयल से प्रभावित जोड़ों की मालीश करें काफी लाभ होगा।
प्रश्न : मेरी उम्र 21 वर्ष है, काम क्रीड़ा में जबरदस्त उल्लास उठता है। मगर स्पर्श मात्र से ही स्खलित हो जाता हूँ। अंग भी छोटी है-मै क्या करूं? प्रभात, औरंगाबाद
उत्तर : गलत संगत या बुरी आदत के कारण अक्सर ये सब होता है। आप अपने काम पर ध्यान दें और विगोरा 2000 की 7 शीशी का कोर्स करें और विगोरा ऑयल से मालिश करें, निश्चित फायदा होगा।
प्रश्न : मेरी उम्र 32 वर्ष है कुछ दिनों से शिघ्रपतन से परेशान हूँ और एक बार सम्बन्ध स्थापित करने के बाद दोबारा मन नहीं करता और आलस्य बना रहता है। अरूण सिन्हा, नोयडा
उत्तर : आप REPL निर्मिता विगोरा 5000 दिन में 3 बार) कप पानी में लें और विगोरा ऑयल से अंग पर मालिस करें। आपकी परेशानी दूर हो जायेगी।
प्रश्न : मैं 42 वर्षीय दो बच्चों का पिता हूँ मेरी समस्या यह है कि मुझे पत्नी से सहवास की इच्छा नहीं होती। यदि होती है तो मुश्किल से 15 सेकेन्ड के लिए । मैं क्या करूं? शंकर तिवारी, गुरगांव
उत्तर : बढ़ती उम्र में अक्सर ऐसा होता है। तनाव, भागदौड़ एवं किशोरावस्था की गलती बहुत से कारण हो सकते हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है आप विगोरा हाई पावर का 90 दिन का कोर्स करें एवं हाई पावर मुसली ऑयल से दिन में दो बार मालिश करें। निश्चित फायदा होगा।
प्रश्न : उम्र 64 वर्ष है। संभोग की तिव्र इच्छा होती है मगर शिशन में कोई हरकत नहीं होती है। इसलिए मन मारकर रह जाता हूँ। सुनील मेहरा वर्धमान
उत्तर : इस उम्र में ऐसा होता है। आप विगोरा 5 X का 5 शीशी का कोर्स करें और साण्डह ऑयल से दिन में दो बार मालिश करें।
प्रश्न : डॉ. साहब मैने टी.वी. पर विज्ञापन देखकर वासनोउत्पति के लिए एक हलवा तरह की दवा मंगवाया उस दवा से फायदा तो कुछ नहीं हुआ उलटा पूरी रात सिर दर्द से छटपटाता रहा। कोई आर्युवेदिक और हानिरहित दवा बताएं। ईश्वरी राय, गाजियाबाद
उत्तर : ईश्वरी जी, कुछ दवा निर्माता बड़े-बड़े विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ताओं को अपने भ्रम जाल में फंसाते हैं और अपने दवा में सिर्फ सिल्डेनाफी मिलाकर बेचते हैं जो शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। मेरे सुझाव से आप REPL निर्मित सुपर सोनिक कैप्सूल समय से दो घंटा पहले लें। यह दवा पूर्णतः आर्युवेदिक है एवं इसका कोई भी साइड इफैक्ट नहीं है।
प्रश्न : मैं 24 वर्षीया एक अविवाहित युवती हूँ मेरे स्तनों का विकास अभी तक पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। जिससे मैं काफी परेशान रहती हूं, आशा है कि आप मुझे सही मार्गदर्शन करायेंगे। स्नेहलता वर्मा, नोयडा
उत्तर : स्तनों का का संपूर्ण विकास नहीं होने के अनेक कारण हैं, जैसे हार्मोन्स की कमी अनुवांशिक। आप चिन्ता मन से निकाल दें एवं REPL का Breastrim Oil स्तनों पर सुबह-शाम दिये गये निर्देश के अनुसार 3 माह तक मसाज करें। इसके नियमित इस्तेमाल से स्तन में उभार आयेगा एवं आप आकर्षक नजर आयेंगी।
प्रश्न : मैं 36 वर्षीय विवाहित स्त्री हूँ पिछले एक वर्ष से पानी गिरने की समस्या है और मेरी जननांग भी काफी ढीली हो गई है। कोई हानिरहित उपचार बतायें। आभा दिल्ली
उत्तर : आभा जी आप विगोरा 1000 दिन में 2 बार 15-15 बूँद आधा कम पानी मिलाकर पियें और Virgin Oil का अंदरूनी हिस्से पर लगाएं। यह बिल्कूल ही हानिरहित दवा है।
प्रश्न : मैं 38 वर्षीय पुरूष हूँ। समस्या यह है कि शरीर में हर वक्त आलस बना रहता है काम में भी मन नहीं लगता है एवं सहवास की भी इच्छा नहीं होती है। कोई आयुर्वेदिक दवा बताये। शम्भु सिंह, देहरादून
उत्तर : शम्भु जी! आप हाईपावर मुसली कैप्सूल का 1 कैप्सूल प्रत्येक दिन रात में सोते वक्त दूध के साथ लें और हाई पावर मुसली ऑयल दो बार 45 दिनों तक इस्तेमाल करें आपके शरीर में शक्ति आयेगी एवं आलस भी दूर रहेगा।
चिकित्सीय परामर्श के लिए स्वपता लिखित डाक लिफाफा, निम्न पते पर भेजें : REPL प्लाजा, तीसरा तल्ला फेडरल, पटना - 801505
Contact : 9304792851,9386880107 & 0612-2251189, (10 AM to 5 PM)
E-mail : customercare@replpharma.com, Visit us at : replpharma.com
डिस्ट्रीब्यूटर: दिल्ली/हरियाणा/पंजाब : निशा मेडिकोज 8860206755, 9988532909, जयपुर: आर.के. डिस्ट्रीब्यूटर 0141-2315071, उत्तर प्रदेश-कानपुर : खरया मेडिकल एजेंसी 0512-2372347, 9415127822, मुगलसराय: प्रकाश होमियो स्टोर 253078, मध्य प्रदेश-जबलपुर : मनीष फार्मा 0761-4004863, 9425157379, छत्तीसगढ़-भिलाई : सिंह होमियो हॉल 0788-403828, 9302839666, रायपुर : जर्मन होमियो 0771 4095630, बिहार: मॉर्डन डिस्ट्रीब्यूटर 9304018193, नॉर्थईस्ट आसाम- बोरिक होमियो रेमेडिज 03672 225340, 09435061793, पश्चिम बंगाल : एम एस ट्रेडर्स 9903175579, देव मार्कटिंग 033-30221018, सिलिगुड़ी : कलकत्ता होमियो 9593313011, झारखंड: सिंघानियां डिस्ट्रीब्यूटर 9431164318, उड़ीसा-भुवनेश्वर डायनेमिक होमियो हॉल 9437110810 कर्नाटक -विजापुर 9341610592 गुलबर्गा:9343834519

गांव में प्रवेश करते ही एक बड़ा सा बोर्ड लगा है, जिस पर लिखा है– 'इस गांव में विद्युतिकरण का कार्य राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना' के तहत किया जा रहा है, लेकिन गांव में बिजली की स्थिति में किसी प्रकार का सुधार नही हुआ है. महादलित के नाम पर केन्द्र से लेकर राज्य सरकार तक विकास को लेकर ढिंढोरा पीटने में लगी है, जबकि अभी तक किसी भी महादलित के घर में बिजली नही लगी है. यहां तीन से चार दर्जन महादलित परिवार हैं. इनकी बस्ती में जानेवाली सड़क की स्थिति अत्यंत जर्जर है.

इंटरव्यू

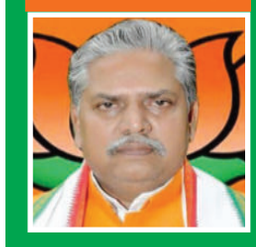

हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में रहेंगे

बिहार में हार पर विधानसभा चुनाव के बाद सबसे अधिक चर्चा आंतरिक रूप से कोई पार्टी कर रही है, तो वह है भारतीय जनता पार्टी. आने वाले वर्षों में भाजपा बिहार में संगठन स्तर पर भी बड़े बदलाव करे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा. विधानसभा चुनाव में एनडीए की करारी हार के बाद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अंतर्मन से यह स्वीकार किया कि बिहार तथा बिहारी मतदताओं को पहचानने में किसी न किसी रूप में गंभीर चूक हुई है. नहीं तो विकास व सुशासन के लिए छटपटा रहे बिहार के मतदाता भाजपा या एनडीए को इस तरह नहीं नकारते. बिहार में विधानसभा चुनाव में हार के बाद भाजपा आने वाले समय में राज्य में अपने संगठन में आमूलचूल परिवर्तन करेगी, ऐसा संकेत मिल रहे हैं. इसी परिवर्तन की कड़ी में पहला कदम है अतिपिछड़ा वर्ग से आने वाले गया शहर के विधायक डॉ. प्रेम कुमार को नेता प्रतिपक्ष बनाना. प्रेम कुमार लगातार सातवीं बार गया शहर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीत कर विधान सभा पहुंचे हैं. अतिपिछड़ा चन्द्रवंशी डॉ. प्रेम कुमार ने लोक नायक जयप्रकाश नारायण के 1974 के आन्दोलन में भाग लिया और जेल गए. यहीं से उनकी राजनीति की शुरुआत हुई. 1977 में जब बिहार में जनता पार्टी की सरकार बनी और गया शहर की तत्कालीन विधायक सुशीला सहाय गृह राज्यमंत्री बनीं तो प्रेम कुमार उनके प्राईवेट सेकेट्री बने. बाद में भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद प्रेम कुमार गया जिले में पार्टी में सक्रिय भूमिका में आ गए और 1990 में गया शहर विधानसभा क्षेत्र से पहली बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने. बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी एनडीए की सरकार में करीब साढ़े सात वर्षों तक विभिन्न विभागों के मंत्री रहे. नेता प्रतिपक्ष के रूप में डॉ. प्रेम कुमार का पहला इंटरव्यू चौथी दुनिया ने लिया. प्रस्तुत है बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डा. प्रेम कुमार से भाजपा व बिहार की भावी राजनीति पर की गई बात-चीत...

सवाल– बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की करारी हार के बाद भाजपा ने आपको नेता प्रतिपक्ष बनाया है, इसे आप किस रूप में लेते हैं?

प्रेम कुमार– पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है. मैं इसे चुनौती के रूप में लेकर पार्टी व राज्यहित में काम करने का प्रयास करूंगा. पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तथा कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद मुझे मिला है. नई सरकार आई है. राज्यहित में नेता प्रतिपक्ष के नाते मैं सकारात्मक भूमिका अदा करने की कोशिश करूंगा. लेकिन राज्य सरकार की खामियों की तरफ भी ध्यान आकृष्ट कराता रहूंगा. पार्टी संगठन, विधानमंडल में समन्वय बनाकर कार्यकर्ताओं तथा आम जनता को साथ लेकर जनसमस्याओं के समाधान के लिए काम करते हुए पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा.

सवाल– भाजपा ने बिहार के जातीय समीकरण और आने वाले समय में राजनीतिक लाभ की संभावना को देखते हुए आपको नेता प्रतिपक्ष बनाया हैं. आप पार्टी को कैसे सफलता की ओर ले जाएंगे?

प्रेम कुमार – मेरा लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है. प्रतिपक्ष में साढ़े सत्रह वर्षों तक तथा साढ़े सात वर्ष सरकार में मंत्री रहने के अनुभव के साथ-साथ पार्टी के विभिन्न पदों पर रह कर भी कार्य किया है. देश में एक मजबूत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सभी काम कर रहे हैं. बिहार को विकसित करने, बिहार को भ्रष्टाचार तथा अपराध मुक्त करने के लिए मोदी जी का जो सपना है और जो योजना है, इसे साकार करने का हर संभव प्रयास करेंगे. जिससे विकसित बिहार का सपना साकार हो.

सवाल– बिहार में आपकी सरकार नहीं बनी. ऐसे में आप कैसे विकसित बिहार के सपने को साकार करेंगे?

प्रेम कुमार– प्रधानमंत्री ने बिहार विधानसभा चुनाव के

समय बिहार को एक बड़ी राशि देने की घोषणा की थी. यह राशि बिहार को मिल रही है. इस राशि से योजनाओं को जमीन पर उतार कर बिहार को विकसित करने का काम हम सभी भाजपा के लोग करेंगे. केन्द्र सरकार की ओर से आयी बहुत सी राशि बिहार में पड़ी है. शौचालय, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन आदि योजनाओं की मद में केन्द्र के द्वारा दी गई करोड़ो की राशि पड़ी है. राज्य सरकार तथा यहां के पदाधिकारी केन्द्र से आयी राशि की योजनाओं पर काम नहीं कर रहे हैं. उदाहरणस्वरूप गया शहर के लिए हेरिटेज योजना के तहत 35 करोड़ की राशि पिछले पांच महीने से आकर पड़ी है. मैंने गया के डीएम पर दबाव बनाया तो इसकी योजना तैयार की गई है. इसी प्रकार बहुत सी योजनाओं के लिए केन्द्र से आयी राशि बिहार में पड़ी है. इन पैसे का उपयोग नहीं हो पा रहा है. ऐसी स्थिति में बिहार में आई नई सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि न सिर्फ इस पूरी राशि का उपयोग बल्कि राज्य में अन्य योजनाओं पर भी ध्यान दे.

सवाल– बिहार में नई सरकार बनने पर आप क्या महसूस कर रहे है?

प्रेम कुमार– बिहार में महागठबंधन की सरकार बनते ही अचानक अपराध में वृद्धि हो गई है. बैंक कर्मी, डॉक्टर, व्यवसायियों के साथ-साथ आम आदमी भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगा है. अपहरण की घटनायें भी बढ़ गई हैं. अब तो बिहार में भगवान भी सुरक्षित नहीं है. मंदिरों से मूर्तिचोरी की घटनायें बढ़ती जा रही हैं. आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकार को कठोर कदम उठाने होंगे. राज्य सरकार की अनदेखी के कारण बिहार से बाहर पठन-पाठन के लिए जाने वाले छात्र-छत्राओं के साथ घटनायें घट रही हैं. बिहार सरकार को चाहिए कि इन सभी राज्य सरकारों को बिहारी छात्र-छत्राओं की सुरक्षा के लिए लिखे और बात करे, जिससे कि दूसरे राज्यों में पढ़ने के लिए जाने वाले बिहारी छात्रों के साथ कोई भेदभाव न हो.

सवाल– अन्त में, यदि चुनाव पूर्व भाजपा एनडीए के मुख्यमंत्री पद के लिए आपके नाम को प्रस्तावित करता तो क्या इसका लाभ भाजपा को मिलता?

प्रेम कुमार– भाजपा नेतृत्व ने महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखण्ड में बिना मुख्यमंत्री पद की घोषणा के माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा. सफलता मिली, इसके बाद मुख्यमंत्री बनाये गए. इसी पार्टी लाइन पर बिहार में भी भाजपा ने चुनाव लड़ा. यह अलग बात है कि अब आम लोग, पार्टी कार्यक्रताओं का कहना है कि चुनाव में मुख्यमंत्री पद के किसी प्रत्याशी की घोषणा कर देते तो इसका लाभ भाजपा को मिलता.■

सुनील सौरभ

feedback@chauthiduniya.com

दामोदरपुर गांव की कहानी

हुकुमदेव नारायण यादव का आदर्श ग्राम बदहाल

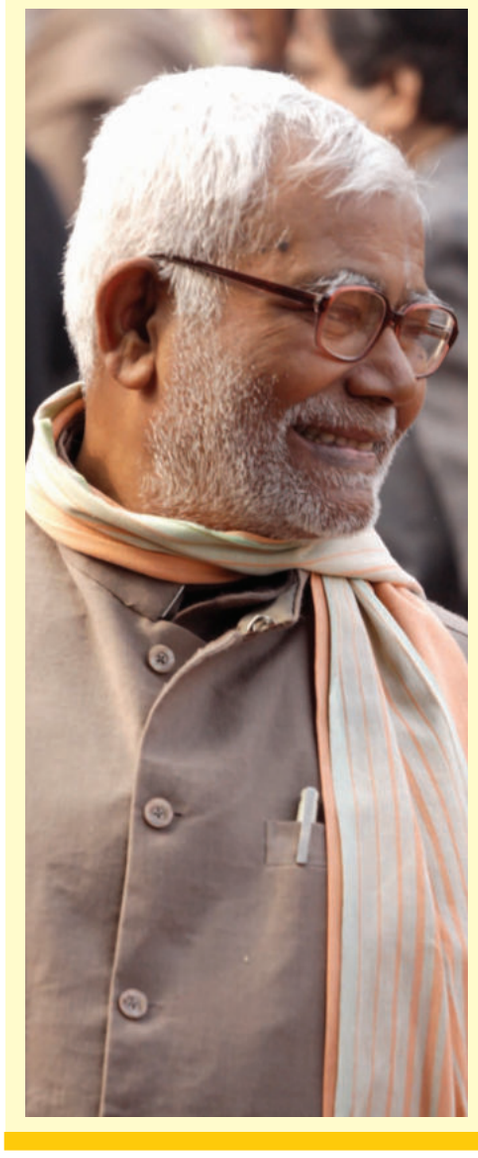

समीर मिश्रा/कुमार गौरव

देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के विकास के लिए आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की थी. इसके तहत सांसद को एक गांव गोद लेने की योजना थी, जिससे गांव को एक मॉडल गांव का रूप दिया जा सके. प्रधानमंत्री ने सोचा था कि देश का विकास गांव के विकास के बाद ही संभव है. सांसदों ने भी प्रधानमंत्री के आह्वान पर गांव को गोद लेना शुरू किया. कई माह गुजर जाने के बाद भी मांडल गांव के रूप में परिवर्तन का प्रयास नहीं किया जा रहा है. सांसद और विधायक एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं.

ऐसा ही एक गांव है मधुबनी जिले का दामोदरपुर. इस गांव को जिले के सांसद हुकुमदेव नारायण यादव ने आदर्श ग्राम के रूप में गोद लिया हुआ है. हुकुमदेव एक दिग्गज और कर्मठ नेता माने जाते हैं लेकिन दामोदरपुर गांव की कहानी भी दूसरे गांवों की तरह ही है. सांसद द्वारा गोद लिए जाने के बावजूद भी इसकी बदहाली में कोई परिवर्तन नहीं आया है. गांव के अंदर जाने वाली एक मुख्य सड़क है. गांव में प्रवेश करने से पहले एक पुल है, जो बीच से क्षतिग्रस्त हो गया है. सरकार ने अपनी कारवाई करते हुए सड़क के क्षतिग्रस्त होने का बोर्ड लगाकर अपनी खानापूर्ति कर ली है. गांव के अंदर सड़क टूटी हुई है. नाला नहीं होने के कारण सड़क पर कीचड़ जमा हो रहा है. जिससे लोगों का चलना मुश्किल हो गया है. इस गांव की मुखिया किरण देवी का कहना है कि गांव में कई परिवार भूमि और घर विहीन हैं. ऐसे लोगों के पास इंदिरा आवास होना आवश्यक है लेकिन सांसद के द्वारा ऐसी कोई पहल नहीं की जा रही है. गांव में कई ऐसे मजदूर

हैं जिसे आज तक राशन कार्ड नहीं मिला है. जिसके कारण वे अनाज तक नहीं उठा पाते हैं. प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बैंक में बार-बार कहने के बाद भी जरूरतमंद लोगों का बैंक में खाता नहीं खोला गया.

गांव में प्रवेश करते ही एक बड़ा सा बोर्ड लगा है, जिस पर लिखा है– 'इस गांव में विद्युतिकरण का कार्य राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना' के तहत किया जा रहा है, लेकिन गांव में बिजली की स्थिति में किसी प्रकार का सुधार नही हुआ है. महादलित के नाम पर केन्द्र से लेकर राज्य सरकार तक विकास को लेकर ढिंढोरा पीटने में लगी है, जबकि अभी तक किसी भी महादलित के घर में बिजली नही लगी है. यहां तीन से चार दर्जन महादलित परिवार हैं. इनकी बस्ती में जानेवाली सड़क की स्थिति अत्यंत जर्जर है. महादलित महिला विशेसरी देवी कहती हैं कि उनके नाम पर किसी और को इंदिरा आवास दे दिया गया और वह प्रखण्ड कार्यालय का चक्कर काट रही हैं फिर भी अधिकारियों द्वारा किसी प्रकार की सुनवायी नहीं की जा रही है. इस गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है, जो अपनी ही समस्या से ग्रस्त है. इस विद्यालय के कई कमरों में कबाड़ रखा हुआ है. इसी के बीच बच्चों को पढ़ाया जाता है. शौचालय जहां गंदा और खराब है तो दूसरी तरफ नये शौचालय निर्माण के लिए राशि ली जा चुकी है. फिर भी शौचालय का निर्माण नहीं किया गया है. इस विद्यालय में मध्याह्न भोजन का संचालन भी ठीक से नहीं किया जा रहा है.

गांव की वर्तमान स्थिति से स्पष्ट है कि इस गांव को गोद लेना कितना आवश्यक था. ग्रामीण भी खुश थे कि इतने बड़े संसदीय क्षेत्र में इस गांव को ही सांसद महोदय ने गोद लिया. लेकिन इतने महीने गुजर जाने के बाद भी इस गांव में सांसद के नहीं आने से स्पष्ट है कि इस गांव को मॉडल गांव बनाने में और भी समय लगेगा. इस संबंध में सांसद हुकुमदेव नारायण यादव से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन की लापरवाही के कारण इस गांव का विकास नहीं हो पा रहा है क्योंकि विकास कार्यों की देख-रेख स्थानीय प्रशासन के द्वारा की जाती है.

इस संदर्भ में जिला जदयू के उपाध्यक्ष नीरज झा का कहना है कि सांसद महोदय गांव के विकास के प्रति उदासीन हैं और इसका दोष वो स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार पर लगा रहे हैं. बेनीपट्टी के पूर्व विधायक सह भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विनोद नारायण झा से जब पूछा गया तो उन्होंने इस पर कुछ भी कहने से इंकार कर दिया. उन्होंने कहा कि इस संबंध में सांसद महोदय से ही पूछिए. माले के पूर्व जिला प्रभारी धुव्र नारायण कर्ण का कहना है कि केन्द्र की सरकार गरीब और किसान विरोधी है. गांव का विकास न होने के लिए मधुबनी के सांसद पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं.

कांग्रेस नेत्री व विधायक भावना झा का कहना है कि गांव को गोद लेने की केन्द की ये योजना सिर्फ हवा-हवाई हैं. सांसद महोदय को धरातल पर जाकर गॉव की स्थिति को देखना होगा.■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

28 दिसंबर, 2015–03 जनवरी, 2016

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड

सोने की तस्करी में चीनी तंत्र, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और नेपाल के नेता की मिलीभगत

अवैध सोने का गढ़ बन रहा भारत

मधेशियों के आंदोलन के चलते भारतीय सीमा पर ब्लॉकेड की खबरें तो लगातार सुर्खियां बनवाई जा रही हैं, लेकिन नेपाल से भारत में हो रही अंधाधुंध सोना तस्करी की खबरें दबाई जा रही हैं. नेपाल के महोत्तरी जिले से लगे सुरसंड गांव में भारत सरकार की कड़ी सीमा सुरक्षा की व्यवस्था दिखती तो है, पर तस्करों के लिए यह रास्ता सुगम है. चीन अधिकृत तिब्बत के सामरिक केन्द्र खासा से सुरसंड की औसतन दूरी छह घंटे से भी कम है. सुरसंड गांव की उत्तरी सीमा महादेव स्थान के उस पार मरुआही गांव है और दोनों गांवों के बीच केनो मैन्स लैंड (दस गजा)का उपयोग श्मशान घाट के रूप में दोनों ही देशों के ग्रामवासियों द्वारा किया जाता है. लेकिन इसी आड़ में भीषण तस्करी के धंधे को अंजाम दिया जा रहा है. दोनों तरफ सीमा पर तैनात सुरक्षा बल तस्करी तो नहीं रोकते, लेकिन सामान्य लोगों की खूब फजीहत करते हैं.

सूफी यायावर

भारत में भारी मात्रा में अवैध सोना धकेल कर भारतीय अर्थ व्यवस्था को चौपट करने का कुचक्र तेज गति से चल रहा है. इसके लिए चीनी तंत्र ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का साथ लेकर नेपाल को जरिया बनाया है. भारत के प्रति घृणा और चीन के प्रति वफादारी के ताने–बाने में नेपाल सोने की तस्करी का एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय केंद्र बनता जा रहा है. सोने की तस्करी को नेपाल के एक बड़े नेता द्वारा संरक्षण देने की बातें भी सामने आ रही हैं. सोना तस्करों से नेपाली नेता की मिलीभगत और उनकी अकूत सम्पत्ति चर्चा में है. प्रकाश टिबड़ेवाला और मोहन गोपाल खेतान जैसे कुख्यात सोना तस्कर और उनके पाकिस्तानी दोस्तों के साथ नेपाली नेताओं के सम्बन्ध उजागर हो चुके हैं. यहां तक कि नेपाल की सार्वजनिक लेखा समिति की बैठक में भी यह सवाल उठ चुके हैं कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी सोना तस्करी को बढ़ावा दे रही है और उसके नेपाली नेताओं से सीधे सम्बन्ध हैं. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व महासचिव माधव कुमार नेपाल खुले मंच से उक्त नेता और मंत्री को कुख्यात तस्कर और अपराधकर्मी बता चुके हैं.

मधेशियों के आंदोलन के चलते भारतीय सीमा पर ब्लॉकेड की खबरें तो लगातार सुर्खियां बनवाई जा रही हैं, लेकिन नेपाल से भारत में हो रही अंधाधुंध सोना तस्करी की खबरें दबाई जा रही हैं. नेपाल के महोत्तरी जिले से लगे सुरसंड गांव में भारत सरकार की कड़ी सीमा सुरक्षा की व्यवस्था दिखती तो है, पर तस्करों के लिए यह रास्ता सुगम है. चीन अधिकृत तिब्बत के सामरिक केन्द्र खासा से सुरसंड की दूरी औसतन छह घंटे से भी कम है. सुरसंड गांव की उत्तरी सीमा महादेव स्थान के उस पार मरुआही गांव है और दोनों गांवों के बीच केनो मैन्स लैंड (दस गजा)का उपयोग श्मशान घाट के रूप में दोनों ही देशों के ग्रामवासियों द्वारा किया जाता है. लेकिन इसी आड़ में भीषण तस्करी के धंधे को अंजाम दिया जा रहा है. दोनों तरफ सीमा पर तैनात सुरक्षा बल तस्करी तो नहीं रोकते, लेकिन सामान्य लोगों की खूब फजीहत करते हैं. अधिकांश शिकायतें सीमा पार के नेपाली गांवों के लोगों की मिलती हैं जिनका कहना होता है कि हम लोगों का परम्परागत बाजार सुरसंड है और यदि हम अपनी जरूरत की वस्तु भी खरीदकर लाते हैं तो एसएसबी जवानों द्वारा परेशान किया जाता है. इस इलाके से चीनी–चावल की भी भीषण तस्करी हो रही है. तस्करी करने वाले नेपाली साहू–महाजन अपने बेटे–बेटियों की शादी के फर्जी निमंत्रण कार्ड छपवा लेते हैं और उसके माध्यम से उपभोक्ता वस्तुओं की तस्करी करते हैं. इसमें दोनों ओर के सुरक्षा बलों की मिलीभगत रहती है. सुरक्षा बल के सूत्र भी मानते हैं कि दसगजा सीमा के किनारे चौकियों के बीच की दूरी में तस्कर गिरोह अपने गुर्गों से खेतों और बाग–बगीचों के रास्ते सोना पार करा रहे हैं. सोने की तस्करी में पाकिस्तान, चीन और यहां तक कि रूस का तंत्र भी संलग्न है.

इस इलाके से चीनी-चावल की भी भीषण तस्करी हो रही है. तस्करी करने वाले नेपाली साहू-महाजन अपने बेटे-बेटियों की शादी के फर्जी निमंत्रण कार्ड छपवा लेते हैं और उसके माध्यम से उपभोक्ता वस्तुओं की तस्करी करते हैं. इसमें दोनों ओर के सुरक्षा बलों की मिलीभगत रहती है. सुरक्षा बल के सूत्र भी मानते हैं कि दसगजा सीमा के किनारे चौकियों के बीच की दूरी में तस्कर गिरोह अपने गुर्गों से खेतों और बाग-बगीचों के रास्ते सोना पार करा रहे हैं. सोने की तस्करी में पाकिस्तान, चीन और यहां तक कि रूस का तंत्र भी संलग्न है. अन्तरराष्ट्रीय सोना तस्करों ने नेपाल को अपना ट्रांजिट प्वाइंट (पारगमन केन्द्र) बना लिया है. चीन के रास्ते नेपाल लाकर भारत में बड़े पैमाने पर सोने की तस्करी की जा रही है. ये तस्कर नेपाल की उत्तरी सीमा से चीन अधिकृत तिब्बत के रास्ते नेपाल के विभिन्न जिलों के रास्ते सोना लाया करते हैं.

अन्तरराष्ट्रीय सोना तस्करों ने नेपाल को अपना ट्रांजिट प्वाइंट (पारगमन केन्द्र) बना लिया है. चीन के रास्ते नेपाल लाकर भारत में बड़े पैमाने पर सोने की तस्करी की जा रही है. ये तस्कर नेपाल की उत्तरी सीमा से चीन अधिकृत तिब्बत के रास्ते नेपाल के विभिन्न जिलों के रास्ते सोना लाया करते हैं और उसे नेपाल–भारत की खुली सीमा का लाभ उठाते हुए भारतीय बाजारों में घुसा देते हैं. स्विट्जरलैंड और अफ्रीका से सीधा चीन आने वाला सोना रूस और नेपाल होते हुए भारत और अन्तरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच रहा है. भारत और चीन पहले स्विस बैंकों के मार्फत सोना आयात किया करता थे, लेकिन इधर दक्षिण अफ्रीका से भी सोना मंगाया जाने लगा है.

पाकिस्तानी एजेंसियों, चीनी एजेंसियों के अलावा भी तस्कर गिरोह अन्य चैनेलों से सोने की तस्करी कर रहे हैं. पहले लिपुलेक, टिंकर, उराल भन्जांग, हियला, खप्रांग चैर, मुसीगांव, लोमानथांग, नारू (नार), लोर्के भन्जांग, रसुवागढ़ी और तातोपानी सहित 16 नाकों से नेपाल में सोना आया करता था. अब तस्कर गिरोहों ने चीन के केरूंग, रसुवागढ़ी, खासा (झांगमल), सिन्धुपाल चौक जिले के तातोपानी, रोंगसार, ताप्लेजुंग जिले के ओलांगचुंग गोला, लोनाक, टिंगरी, सोलुखुम्बू जिले के नाप्चे चुले और दोलखा जिले के लाप्चेगांव के रास्ते को मुख्य तस्करी का मार्ग बना लिया है. सूत्र बताते हैं कि कुछ

(शेष पृष्ठ 18 पर)

अशांत नेपाल में भारत विरोधी लहर

मृत्युंजय दीक्षित

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम पद की शपथ लेने के बाद पड़ोसी देशों के साथ अपने सम्बन्धों को मजबूती प्रदान करने के प्रयास शुरू किए और इस सिलसिले में वे दो बार नेपाल भी गए. भूकम्प में नेपाल को भरपूर आर्थिक व सैन्य मदद भी दी. लेकिन सारी कवायदें एकबारगी विफल होती नजर आ रही हैं. नेपाल में नया संविधान लागू हाने के बाद और नए प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति के आने के बाद अपना वही पड़ोसी देश भारत के प्रति बेहद आक्रामक तरीके से असहनशील होता जा रहा है.

नेपाल के साथ भारत के कई अतिमहत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौते हैं जिनमें ऊर्जा, परिवहन समेत कई समझौते शामिल हैं. आज इन सभी समझौतों पर आपसी तनाव के बादल घिर आए हैं. आज नेपाल फिर से अशांत है. भारत के दो प्रमुख पड़ोसी चीन और पाकिस्तान यह कतई नहीं चाहते कि नेपाल और भारत के सम्बन्ध मधुर हों. नेपाल चीन के शिकंजे में फंसता जा रहा है. जब नेपाल में नए संविधान का निर्माण हो रहा था और वहां पर संविधान सभा ने नेपाल के नागरिकों के साथ समान व्यवहार के सिद्धांत को ताक पर रख दिया तभी यह दिखने लगा था कि नेपाल और भारत के संबंधों में नए सिरे से खटास उत्पन्न होने जा रही है.

पिछले कुछ ही दिनों में नेपाल में भारत विरोधी जो उबाल आया है वह बेहद गंभीर है. नेपाल सशस्त्र प्रहरी ने एसएसबी के 13 जवानों को उस समय बंधक बना लिया जब वे तस्करों का पीछा करते हुए नेपाल की सीमा में प्रवेश कर गए थे. मामला दो देशों का होने के कारण खलबली मचना स्वाभाविक था. बाद में दोनों देशों के अधिकारियों की बातचीत के बाद जवानों को मुक्त कराया गया. एसएसबी जवान रेहान कुमार और रामप्रसाद ने तस्करों का पीछा किया तो वे नेपाल के खुटामनी गांव में प्रवेश कर गए. जहां नेपाली नागरिक द्वारा हंगामा करने पर नेपाल सशस्त्र प्रहरी के जवानों ने दोनों भारतीय जवानों को बंधक बना लिया. जब वे जवान नहीं लौटे तब उन्हें तलाशते हुए भारत के 11 और जवान नेपाल सीमा में प्रवेश कर गए. उन्हें भी नेपाली प्रहरियों ने बंधक बना लिया. भारत सरकार के गृह मंत्रालय के कड़े हस्तक्षेप के बाद जवानों की रिहाई हुई. यह ऐसी घटना है जिसे टटोल कर देखें तो स्थितियों का अंदाजा लग सकता है. दूसरी तरफ नेपाल के एकीकृत माओवादी पार्टी से अलग हुए माओ कार्यकर्ताओं ने भी भारत पर आर्थिक नाकेबंदी का आरोप लगाकर मोर्चा खोल दिया है. कई कस्बों व शहरों में भारतीय चैनलों का प्रसारण बंद करवा दिया गया है. नेपाली सिनेमाघरों में भारतीय फिल्मों का प्रदर्शन भी प्रतिबंधित कर दिया गया है. कई स्थानों पर भारतीय वाहनों पर पथराव व आगजनी की घटनाएं घटीं. नेपाल के नए संविधान में संशोधन की मांग को लेकर मधेशी आंदोलन अब धीरे-धीरे उग्र हो रहा है. पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई के समर्थक भारत पर आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति न करने व आर्थिक नाकेबंदी करने का गंभीर आरोप लगा रहे हैं. नेपाल सरकार को लग रहा है मधेशी भारत की शह पर आंदोलन चला रहे हैं. नेपाल के मधेशी अब स्वतंत्र देश तक की मांग करने लगे हैं साथ ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भारतीय सेना के हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं. खुफिया रिपोर्टें बता रही हैं कि नेपाल भारत विरोधी आतंकी गतिविधियां चलाने वाले गिरोहों का भी स्वर्ग बनता जा रहा है. यह आने वाले समय के लिए चिंता का विषय है, लिहाजा इस समस्या का निपटारा समय रहते होना अनिवार्य है.

काठमांडू स्थित बालाजी ट्रेडर्स के संचालक बालकृष्ण अग्रवाल, संगम ज्वेलर्स बांगेमुढ़ा के संचालक रमेश खड्का, द यूनाईटेड गोल्ड मार्ट के संचालक प्रबंधक आकाश कुमार बज्राचार्य, महाराष्ट्र के मूल निवासी तथा काठमांडू के न्यू रोड में सोना चांदी का व्यापार करते आ रहे वालु जगन्नाथ घाड्गे के यहां कुछ अर्सा पहले हुए छापेमारी में दो किलो सोना के अलावा दो करोड़ नेपाली रुपये और भारी तादाद में भारतीय मुद्रा बरामद हुई थी. दधिकोट-4 भक्तपुर के रमेश खड्का के पास से 81 लाख 51 हजार रुपये नगद और 35 किलो चांदी बरामद की गई थी.

सुप्रीमकोर्ट ने पहली बार किसी राज्य का लोकायुक्त नियुक्त किया

पूर्व जस्टिस वीरेंद्र सिंह बने यूपी के लोकायुक्त

चौथी दुनिया ब्यूरो

उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त नियुक्ति के मामले पर विराम लगाते हुए सुप्रीमकोर्ट ने प्रदेश में नए लोकायुक्त की नियुक्ति की है. रिटायर्ड जस्टिस वीरेंद्र सिंह को यूपी का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है. सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार किसी राज्य का लोकायुक्त नियुक्त किया है. सर्वोच्च न्यायालय ऐतिहासिक फैसला लेते हुए लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किया. लोकायुक्त की नियुक्ति न होने से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को जमकर फटकार लगाई. आदेश जारी करने के बावजूद भी अंतिम दिन तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं होने से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए लोकायुक्त की नियुक्ति कर दी. अदालत ने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों द्वारा सर्वोच्च अदालत के फैसले का पालन न किए जाने पर अफसोस जताया.

उच्चतम न्यायालय ने बीते 23 जुलाई को राज्य सरकार से कहा था कि वह 22 अगस्त तक लोकायुक्त पद के लिए कोई नाम सुझाए, जिसके बाद अखिलेश सरकार ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश रवीन्द्र सिंह यादव का नाम तय किया और उससे संबंधित फाइल पांच अगस्त को पहली बार राजभवन को भेजी थी. उसके बाद से सरकार और राजभवन के बीच इस मुद्दे को लेकर तकरार शुरू हो गई थी. सरकार और राजभवन के बीच फाइल झूलती रही. उसके बाद राम नाइक ने आखिरकार लोकायुक्त के पद पर नियुक्ति के लिए रवीन्द्र यादव सिंह के नाम को नकारते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता की चयन समिति की बैठक में कोई और नाम होने के बाद ही वह फाइल पर अपनी मंजूरी देंगे.

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रंजन गोगोई और एनवी रमन्ना की बेंच ने उत्तर प्रदेश की पैरवी करने वाले वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल को जमकर फटकार लगाई. बेंच ने उनसे नियुक्ति के बारे में भी सवाल किया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें अपने आदेश का पालन करवाना आता है. इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि यूपी सरकार पांच नामों पर चर्चा कर रही है, वो नाम पूछे जाने पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया.

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रंजन गोगोई और एनवी रमन्ना की बेंच ने उत्तर प्रदेश की पैरवी करने वाले वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल को जमकर फटकार लगाई. बेंच ने उनसे नियुक्ति के बारे में भी सवाल किया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें अपने आदेश का पालन करवाना आता है. इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि यूपी सरकार पांच नामों पर चर्चा कर रही है, वो नाम पूछे जाने पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. जिसके चलते 16 दिसंबर को 12.30 बजे लोकायुक्त की नियुक्ति का आदेश जारी करने का समय तय किया गया था. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा लोकायुक्त नियुक्त करने को लेकर को

इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने यूपी के राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखकर कहा है कि उनकी सहमति के बिना रिटायर्ड जस्टिस वीरेंद्र सिंह को यूपी का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है. उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति के बाद एक नए विवाद को हवा मिल गई है. पूरा मामला यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिसम्बर तक नए लोकायुक्त की नियुक्ति करने का निर्देश दिया था. लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार इसमें नाकाम रही, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने एतिहासिक फैसला लेते हुए पहली बार किसी राज्य का लोकायुक्त नियुक्त किया. लोकायुक्त के चयन की तीन सदस्यीय समिति है, जिसमें मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य शामिल हैं. गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने बीते 23 जुलाई को राज्य सरकार से कहा था कि वह 22 अगस्त तक लोकायुक्त पद के लिए कोई नाम सुझाए, जिसके बाद अखिलेश सरकार ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश रवीन्द्र सिंह यादव का नाम तय किया और उससे संबंधित फाइल पांच अगस्त को पहली बार राजभवन को भेजी थी. उसके बाद से सरकार और राजभवन के बीच इस मुद्दे को लेकर तकरार शुरू हो गई थी. सरकार और राजभवन के बीच फाइल झूलती रही. उसके बाद राम नाइक ने आखिरकार लोकायुक्त के पद पर नियुक्ति के लिए रवीन्द्र यादव सिंह के नाम को नकारते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता की चयन समिति की बैठक में कोई और नाम होने के बाद ही वह फाइल पर अपनी मंजूरी देंगे.

राज्यपाल राम नाइक ने न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के एक और पत्र की बात कही थी, जिसमें सार्वजनकि कार्यक्रम में सरकार के वरिष्ठ मंत्री शिवपाल सिंह यादव के साथ न्यायमूर्ति रवीन्द्र सिंह यादव के उपस्थित रहने का उल्लेख करते हुए कहा था कि जनता की निगाह में किसी दल विशेष के प्रति झुकाव रखने वाला कोई व्यक्ति लोकायुक्त के पद पर अपने दायित्व का निष्पक्ष तरीके से निष्पादन कर पाएगा, इसमें संदेह है.

इसी तकरार के बीच राज्य सरकार ने अगस्त में विधानसभा और विधानपरिषद में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उपलोकायुक्त (संशोधन) विधेयक पारित करवाकर राज्यपाल के पास भेजा. इसमें लोकायुक्त की चयन समिति से मुख्य न्यायाधीश को हटाने का प्रावधान किया गया था. हालांकि राज्यपाल ने अभी इस विधेयक को मंजूरी नहीं दी है.

प्रदेश में मार्च 2012 में अखिलेश सरकार के गठन के बाद प्रदेश में लोकायुक्त के कार्यकाल को छह से बढ़ाकर आठ साल करने की बात कही गयी थी. ■

feedback@chauthiduniya.com

अवैध सोने का गढ़ बन रहा भारत

पृष्ठ 17 का शेष

के नेपाली ग्यलजो लामा और भारतीय मूल के मोहन अग्रवाल सक्रिय तौर पर सोने की तस्करी कर रहे हैं. नेपाली पुलिस के दस्तावेजों में सोना-डॉन के नाम से मशहूर घनश्याम अग्रवाल का भाई मोहन अग्रवाल, पुनरावेदन अदालत से सामान्य जमानत पर रिहा होने के बाद फिर से सोना का कारोबार कर रहा है, जबकि उसका ड्राइवर अभी भी जेल में बन्द है.

काठमांडू स्थित बालाजी ट्रेडर्स के संचालक बालकृष्ण अग्रवाल, संगम ज्वेलर्स बांगेमुढ़ा के संचालक रमेश खड्का, द यूनाईटेड गोल्ड मार्ट के संचालक प्रबंधक आकाश कुमार बज्राचार्य, महाराष्ट्र के मूल निवासी तथा काठमांडू के न्यू रोड में सोना चांदी का व्यापार करते आ रहे वालु जगन्नाथ घाड्गे के यहां कुछ अर्सा पहले हुए छापेमारी में दो किलो सोना के अलावा दो करोड़ नेपाली रुपये और भारी तादाद में भारतीय मुद्रा बरामद हुई थी. दधिकोट-4 भक्तपुर के रमेश खड्का के पास से 81 लाख 51 हजार रुपये नगद और 35 किलो चांदी बरामद की गई थी. आकाश कुमार बज्राचार्य की दुकान से तीन किलो निर्मित गहना, छह किलो चांदी के साथ ही नगद 31 लाख रुपये बरामद किए गए थे. नेपाली पुलिस का यह ऑपरेशन आक्टोपस सुबह से देर शाम तक चलता रहा. पुलिस ने 17 व्यक्तियों को सोने की तस्करी(ओसार-पसार) करने के आरोप में पकड़ा था. नेपाली पुलिस की सूचना के मुताबिक बालकृष्ण अग्रवाल के पार्टनर सावरमल जोधानी और कुलियों का सरगना (भरिया नाइके) श्रीराम चौधरी फरार है. उनमें से संगम ज्वेलर्स के संचालक रमेश खड्का ने राजस्व अनुसन्धान विभाग में जमानत राशि जमा करा दिया है, लेकिन सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग द्वारा अनुसंधान जारी है. सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग में जमानत राशि जमा करा देने के बाद भी आकाश बज्राचार्य जेल में है.

नेपाल में सोना तस्करी का मुख्य कारण है सोना के आयात में लगने वाला कर. वैधानिक ढंग से सोना लाने के लिए प्रति तोला 4,800 रुपये का आयात कर चुकाना पड़ता है. जबकि तस्करी के सोने से लाखों रुपये का फायदा कमाया जाता है. नेपाल के बैंकों की इजाजत से आयात किया जाने वाला सोना शुद्धता में 99.05 प्रतिशत रहता है, जबकि तस्करी के रास्ते आने वाला सोना 99.99 प्रतिशत शुद्ध रहता है.

नेपाल में सोना तस्करी का मुख्य कारण है सोना के आयात में लगने वाला कर. वैधानिक ढंग से सोना लाने के लिए प्रति तोला 4,800 रुपये का आयात कर चुकाना पड़ता है. जबकि तस्करी के सोने से लाखों रुपये का फायदा कमाया जाता है. नेपाल के बैंकों की इजाजत से आयात किया जाने वाला सोना शुद्धता में 99.05 प्रतिशत रहता है, जबकि तस्करी के रास्ते आने वाला सोना 99.99 प्रतिशत शुद्ध रहता है. नेपाल से भारत में बहुत बड़े पैमाने पर सोने की तस्करी हो रही है, उसकी वजह यह भी है कि भारत में सोने की कीमत नेपाल की अपेक्षा प्रति तोला लगभग हजार रुपये अधिक है. इस कारण नेपाल का व्यापारी सोना का गहना बनाकर उसे भारत भेज रहा है. नेपाल से कच्चा सोना भारत भेजे जाने पर भी बड़ी आमदनी होती है. नेपाल से भारत आने वाला व्यक्ति यदि छह तोला तैयार गहना भी ले जाता है तो मजदूरी के अलावा उसे एक बार में पांच-छह हजार रुपये की आमदनी हो जाती है. गोपनीय रिपोर्ट बताती है कि नेपाल में प्रतिदिन एक क्विंटल सोना आता है. इसमें नेपाल के पूरे तंत्र की साठगांठ रहती है. नेपाल की सार्वजनिक लेखा समिति नेपाल के गृहमंत्री से लेकर सचिव और पुलिस महानिरीक्षक स्तर तक के अधिकारियों पर सोने के तस्कर गिरोहों से मिलीभगत रखने का आरोप लगा चुकी है. सार्वजनिक लेखा समिति ने पूर्व गृहमंत्री वामदेव गौतम और आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याल से इस सिलसिले में सख्त पूछताछ की थी. इसके बाद ही नेपाली पुलिस ने ऑपरेशन ऑक्टोपस नाम से अभियान चलाया था और तकरीबन पांच सौ किलो सोना बरामद किया था. द यूनाइटेड गोल्ड के संचालक आकाश कुमार बज्राचार्य और इलाम के बालकृष्ण अग्रवाल परसोना तस्करी के सार्वजनिक अपराध का मुकदमा है. पांग्रेटा, सिन्धुपाल चौक का देउता तिमिल्सिना, रौतहट सिमरा भगवतीपुर-3 का मोहन चौधरी, काभ्रे नया बाजार का मिलन तमांग और कैलाली मालती का जयराज भट्ट फरार है. ■

feedback@chauthiduniya.com

भारत समेत पूरे दक्षिण एशिया में तस्करों का जाल

नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका से सोना तस्करी के ज़रिए भारत भेजा जा रहा है. लखनऊ या दिल्ली मुंबई के बाजारों में चमकने वाला सोना नेपाल और चीन की पहाड़ियों के बीच के निर्जन इलाके तातोपानी से आता है. सीमा पार तिब्बत से नेपाल में आ रहा सोना सीधे भारतवर्ष पहुंचता है. यह सीमा इतनी फैली हुई है कि तस्करी रोक पाना असंभव है. इसे रोकने में नेपाल सरकार की दिलचस्पी का आलम यह है कि वहां एक भी मेटल डिटेक्टर नहीं लगाया गया है. एक बार नेपाल में दाखिल होने के बाद भारत से लगी 1690 किलोमीटर की सीमा पर सोना हासिल करना तस्कर गिरोहों के लिए काफ़ी आसान काम है. यही माजरा बांग्लादेश का भी है, जिसकी भारत से और ज़्यादा लंबी सीमा लगती है. भारतीय कस्टम विभाग के एक आला अधिकारी गोल्डस्मिथ एसोसिएशन ऑफ़ बांग्लादेश का हवाला देकर कहते हैं कि सोना तस्कर गिरोह बांग्लादेश को एक रूट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार के कारण बांग्लादेश में सुरक्षा कड़ी नहीं है. तस्कर गिरोहों का मानना है कि उनका बांग्लादेश-नेटवर्क काफ़ी व्यवस्थित है. श्रीलंका भी सोना तस्करी का अच्छा खासा केंद्र बनता जा रहा है. भारत और नेपाल सीमा पर रक्सौल तस्करी का गढ़ बन गया है.

एक साल में 3500 किलो सोना जब्त

सोने की तस्करी भारत में हजार करोड़ रुपये के पार पहुंच गई. कस्टम, पुलिस और रेवेन्यू विभाग ने वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान 3500 किलो सोना जब्त किया, जिसकी कीमत 1100 करोड़ रुपये है. 2012-13 के दौरान 100 करोड़ रुपये कीमत का 350 किलो सोना जब्त किया गया था. सरकार ने चालू खाता घाटा कम करने के लिए सोने के आयात पर लगने वाले शुल्क को बढ़ाकर 10 फीसदी कर दिया था, जिसके कारण तस्करी 900 फीसद बढ़ गई. डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (डीआरआई) का आधिकारिक तौर पर कहना है कि सोने की तस्करी में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है. डीआरआई के आकड़ों के अनुसार 2012-13 में 100 करोड़ रुपये का सोना जब्त हुआ था. वहीं, 2013-14 के दौरान 690 करोड़ रुपये का सोना एजेंसियों ने पकड़ा. 2014-15 के दौरान सारे रिकॉर्ड टूट गए और 1100 करोड़ रुपये का सोना पकड़ा गया. भारत में सोने की तस्करी के लिए रूट्स में काफी बदलाव आया है. नेपाल में भीषण भूकंप में सोना तस्करों के एक बड़े सरगना की मौत हो गई. इस वजह से धंधे पर कुछ दिनों का असर तो हुआ, लेकिन फिर निर्बाध गति से सब चलने लगा. अब तो भारत में सोने की तस्करी के लिए गुजरात, मणिपुर और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर क्षेत्र का भी इस्तेमाल किया जा रहा है. आमतौर पर नेपाल में 80-100 किलो सोना जब्त होता है, लेकिन 2013-14 के दौरान यह आंकड़ा दो गुना बढ़ गया है. सरकारी एजेंसियों के मुताबिक तस्कर दुबई, थाईलैंड और चीन के रास्ते सोना भारत लाते हैं. वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान देश में सोने का आयात 36 फीसद बढ़कर 900 टन हुआ है. पिछले साल 665 टन सोना देश में आयात था. मार्च में सोने का आयात 60 टन से बढ़कर 125 टन पहुंच गया था. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक इस साल देश में 900-1000 टन सोना खपत होने की संभावना है. ■

एनजीटी के फैसले का उत्तरकाशी की पालिकाध्यक्ष जयेंद्री राणा ने स्वागत किया है. उनका कहना है कि वह पहले से ही पालिका क्षेत्र को पॉलीथीन से मुक्त करने के लिए अभियान छेड़े हुए हैं. वह गंगा की स्वच्छता के लिए निरंतर कार्य कर रही हैं. उन्होंने कहा कि पहले भी कई लोगों को प्लास्टिक का प्रयोग करने पर जुर्माना लगाया गया, लेकिन ऐसे सभी लोग पालिका में झगड़ा करने पंहुच जाते थे. अब एनजीटी और केंद्र सरकार ने सख्ती से निपटने का निर्णय लिया है.

बहुगुणा का लोकायुक्त नियुक्ति को लेकर हरीश पर हमला

राजकुमार शर्मा

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने राज्य की कांग्रेस सरकार को समय रहते संभल जाने की हिदायत दी है. इस बार फिर बहुगुणा ने लोकायुक्त के नाम पर हरीश को घेरने का काम शुरू कर दिया है. उन्होंने कहा कि यदि समय से लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हुई, तो आने वाला समय मुश्किलों भरा होगा. उत्तराखंड में अब तक लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर कोई खास पहल न करना हरीश सरकार की गले की फांस बनती जा रही है. विपक्ष के साथ ही कांग्रेस के अपने दिग्गज नेता भी रावत को आइना दिखा रहे हैं. उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बहुगुणा जिनके कार्यकाल के दौरान रावत रोजाना एक लेटर बम फोड़ते थे, इसी के जवाब में बहुगुणा गाहे बगाहे एक जुमला छोड़ कर रावत के माथे पर चिंता की लकीर उकेर देते हैं. बहुगुणा का कहना कि अभी तक तो हम गुजरात में लोकायुक्त नहीं नियुक्त होने के कारण नरेन्द्र मोदी को घेरते थे, उत्तराखंड में लोकायुक्त न नियुक्त होने पर हम क्या जवाब देंगे? कैबिनेट में फेरबदल पर बहुगुणा ने कहा कि केंद्र में होता है, हर राज्य में होता है, तो उत्तराखंड में कैबिनेट में फेरबदल क्यों नहीं? कैबिनेट में नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, जिन्होंने पार्टी को सींचा है.

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बहुगुणा जिनके कार्यकाल के दौरान रावत रोजाना एक लेटर बम फोड़ते थे, इसी के जवाब में बहुगुणा गाहे बगाहे एक जुमला छोड़ कर रावत के माथे पर चिंता की लकीर उकेर देते हैं. बहुगुणा का कहना कि अभी तक तो हम गुजरात में लोकायुक्त नहीं नियुक्त होने के कारण नरेन्द्र मोदी को घेरते थे, उत्तराखंड में लोकायुक्त न नियुक्त होने पर हम क्या जवाब देंगे? कैबिनेट में फेरबदल पर बहुगुणा ने कहा कि केंद्र में होता है, हर राज्य में होता है, तो उत्तराखंड में कैबिनेट में फेरबदल क्यों नहीं?

पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर मीडिया से बातचीत में कई बिंदुओं पर खुलकर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि ऐसी क्या मजबूरी है कि लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हो सकी. यूपीए सरकार के जनलोकपाल बिल को ही उनकी सरकार ने राज्य की विधानसभा से पास कराकर लागू कराया था.

दो साल बीत जाने के बाद भी लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं होना सरकार और कांग्रेस दोनों की सत्य निष्ठा पर सवाल खड़ा करता है. उन्होंने इसके पीछे की वजह पूछने पर बताया कि कोई सरकार अपने या अपने सिस्टम के ऊपर किसी तरह का अंकुश नहीं चाहती. यदि लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हुई, तो आने वाले समय में इसका खामियाजा पूरी कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा.

उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव दूर नहीं है, कांग्रेस के लिए अभी नहीं तो कभी नहीं जैसी स्थिति है. हरीश रावत सक्षम भी हैं और सरकार में किसी का दखल भी नहीं है, इसलिए इनके पास अब कोई ऐसा बहाना नहीं होना चाहिए कि अपनों ने ही नैय्या डुबो दी. सरकार के प्रदर्शन के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि कामकाज का मूल्यांकन विधानसभा चुनाव की मतपेटियों से निकलेगा. उन्होंने कहा कि जब सभी राज्यों और केंद्र में मंत्रिमंडल में बदलाव होता है, तो उत्तराखंड में हरीश क्यों डर रहे हैं? राज्य की पूरी कैबिनेट में परिवर्तन होना चाहिए. उनका मानना है कि हरीश सरकार अपना दो वर्ष का कार्यकाल पूरा करने जा रही है, सरकार की उपलब्धियों पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए. बहुगुणा की नजर में रावत सरकार में कई मंत्री ऐसे हैं, जो जनता की आकांक्षाओं पर खरा न उतरकर अपना घर भरने में लगे हैं. उनका मानना है कि ऐसे मंत्रियों को हटाकर नए चेहरों को मौका देना चाहिए, जिससे कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ की मंशा पूरी हो सके.

बहुगुणा ने कहा कि हरीश रावत को कड़े फैसले लेने होंगे. हर निर्णय के पीछे वोट बैंक की राजनीति ठीक नहीं है. 7वां वेतन आयोग सिर पर है, उत्तराखंड की आर्थिक दशा किसी से छिपी नहीं है. कर्ज लगातार बढ़ रहा है. उत्तराखंड देश का अकेला ऐसा राज्य हैं जहां पर नॉन प्लान का खर्च सबसे ज्यादा है. ऐसे में विकास कैसे होगा?

आगामी विधानसभा चुनाव में खुद के चुनाव लड़ने पर बहुगुणा ने सधी हुई प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ना मेरी प्राथमिकता नहीं है, मैं रणछोड़ भी नहीं हूं. पार्टी जैसा कहेगी, आदेश का पालन होगा. कांग्रेस का निष्ठावान कार्यकर्ता हूं और आगे भी कांग्रेस के मजबूती के लिए तत्पर रहूंगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

अर्द्धकुंभ के बहाने हरीश की केंद्र को घेरने की कोशिश

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मोदी सरकार द्वारा हरिद्वार में सम्पन्न होने वाले अर्द्धकुंभ में पूरी मदद न करने का आरोप लगाया और उनकी नियति पर सवाल खड़ा किया. हरीश सरकार ने एक बार फिर मोदी सरकार के सामने अर्द्धकुंभ के लिए मदद मांगी है. अर्द्धकुंभ को लेकर प्रदेश सरकार ने केंद्र पर निशाना साधा है. मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक बार फिर वित्त मंत्री अरुण जेटली को पत्र लिखकर कहा कि नीति आयोग की संस्तुति के बावजूद केंद्र से अर्द्धकुंभ के लिए धनराशि उपलब्ध नहीं हो पा रही है. अर्द्धकुंभ की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, अब तक केंद्र सरकार की ओर से अर्द्धकुंभ के लिए प्रदेश सरकार को एक रुपया नहीं मिला है. मुख्यमंत्री हरीश रावत प्रधानमंत्री से लेकर वित्त मंत्री के समक्ष कई बार गुहार लगा चुके हैं. इसी उम्मीद में मुख्यमंत्री ने एक बार फिर वित्त मंत्री अरुण जेटली को पत्र लिखकर अर्द्धकुंभ के लिए 500 करोड़ रुपये की मांग की है. नीति आयोग की ओर से पूर्व में अर्द्धकुंभ के लिए लगभग 167 करोड़ रुपये की संस्तुति का भी केंद्र पर असर होता दिखाई नहीं दे रहा है. मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को पत्र लिखकर हरिद्वार में आयोजित होने वाले अर्द्धकुंभ के लिए उत्तराखण्ड सरकार को एकमुश्त 500 करोड़ रुपये की सहायता दिए जाने का अनुरोध किया है. 2016 में जनवरी से अप्रैल तक हरिद्वार में अर्द्धकुंभ की महत्ता का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा है कि इसमें सात से आठ करोड़ श्रद्धालुओं के आने की सम्भावना है. हरिद्वार और इलाहाबाद के कुंभ व अर्द्धकुंभ का गंगा व त्रिवेणी के कारण दूसरे स्थानों की तुलना में अधिक महत्व है. राज्य सरकार सुरक्षित व सुविधापूर्ण अर्द्धकुंभ के लिए प्रतिबद्ध है. इस बार राज्य सरकार का फोकस स्थाई प्रकृति के आधारिक संरचना के विकास पर है.

अर्द्धकुंभ के आयोजन के लिए 500 करोड़ रूपये की योजना तैयार की गई है. इसमें से 400 करोड़ रुपये स्थाई प्रकृति के कार्य के लिए व 100 करोड़ रुपये अर्द्ध स्थायी व अस्थाई जनसुविधाओं व सेवाओं के लिए रखा गया है. राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में उपलब्ध अपने सीमित संसाधनों से अर्द्धकुंभ के लिए इतनी बड़ी राशि हस्तांतरित करने से राज्य के बजट पर काफी दबाव पड़ेगा फिर भी राज्य सरकार ने अर्द्धकुंभ के महत्व व संवेदनशीलता को देखते हुए लगभग 350 करोड़ रुपये की योजनाओं को स्वीकृति दी है. इनमें बहुत सी पूर्ण भी होने वाली हैं. मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा है कि इस संबंध में पूर्व में भी अनेक बार केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है. यहां तक नीति आयोग ने भी राज्य को अर्द्धकुंभ के लिए लगभग 167 करोड़ रुपये दिए जाने की संस्तुति की थी. इसके बाद भी यह राशि राज्य को जारी नहीं की गई. अर्द्धकुंभ की महत्ता को देखते हुए केंद्र सरकार प्राथमिकता से उत्तराखण्ड को 500 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता प्रदान करे ताकि सभी आवश्यक निर्माण कार्य व तैयारियां समय पर की जा सकें. उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार लंबे समय से अर्द्धकुंभ के निर्माण कार्य के लिए केंद्र से आर्थिक सहायता की मांग कर रही है. केंद्र सरकार से राज्य को यथोचित मदद नहीं मिल सकी है. रावत हर हाल में धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले भाजपा के प्रधानमंत्री मोदी को घेरना चाहते हैं. ■

> *मुख्यमंत्री का बार-बार पत्र लिखकर यह जताना कि केंद्र अर्द्धकुंभ के लिए पैसा नहीं दे रहा है यह राजनीतिक चाल है. केंद्र ने फंडिंग पैटर्न बदलने पर राज्य को पहले के मुकाबले कहीं अधिक पैसा दिया है. यह बात अलग है कि प्रदेश सरकार इस धन का उपयोग नहीं कर पा रही है. जहां तक अर्द्धकुंभ का सवाल है, तो पिछले कुंभ का करीब 80 करोड़ रुपये बचा हुआ है. स्थायी निर्माण के सभी कार्य जैसे सड़क व पुल आदि के कार्य पहले ही किए जा चुके हैं. अब केवल अस्थाई कार्य जैसे कुंभ के दौरान पानी की लाइन, बिजली व टैंट आदि की व्यवस्था की जानी है. इसके लिए 500 करोड़ की आवश्यकता नहीं है. वैसे भी नीति आयोग ने लगभग 167 करोड़ रुपये की स्वीकृति दे दी है. केंद्र की ओर से पैसा उपलब्ध कराया जा रहा है.*
>
> *-अजय भट्ट, नेता प्रतिपक्ष*

हरिद्वार क्षेत्र में प्लास्टिक और पॉलीथीन कंपनियों पर प्रतिबंध

रेनू शर्मा

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हरिद्वार क्षेत्र में प्लास्टिक और पॉलीथीन बनाने वाली कंपनियों को प्रतिबंधित कर दिया है. अब इससे गंगा के दिन फिरने की आस बंध गई है. एनजीटी के लोकल कमिश्नर एसए जैदी ने बताया कि 2014 में एक याचिका दायर की गई थी. इस पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने यह फैसला दिया है. अब हरिद्वार क्षेत्र में प्लास्टिक व पॉलीथीन पर रोक लगा दी गई है. गंगा में जिन होटलों व धर्मशालाओं के नालों का पानी जा रहा है. इस पर भी रोक लग जाएगी. होटल, आश्रम व धर्मशालाओं को एसटीपी प्लांट लगाने को कहा गया है. एनजीटी के फैसले का उत्तरकाशी की पालिकाध्यक्ष जयेंद्री राणा ने स्वागत किया है. उनका कहना है कि वह पहले से ही पालिका क्षेत्र को पॉलीथीन से मुक्त करने के लिए अभियान छेड़े हुए हैं. वह गंगा की स्वच्छता के लिए निरंतर कार्य कर रही हैं. उन्होंने कहा कि पहले भी कई लोगों को प्लास्टिक का प्रयोग करने पर जुर्माना लगाया गया, लेकिन ऐसे सभी लोग पालिका में झगड़ा करने पहुंच जाते थे. अब एनजीटी और केंद्र सरकार ने सख्ती से निपटने का निर्णय लिया है. वह एनजीटी के निर्णय का कड़ाई से पालन कर गंगा और नगर पालिका क्षेत्र में प्लास्टिक को प्रतिबंधित कर दोषी पाए जाने वाले लोगों से सख्ती से निपटेगी. नगरपालिका ऋषिकेश के अध्यक्ष दीप शर्मा ने बताया कि नगर में प्लास्टिक पर प्रतिबंध लागू है. गंगा में प्रदूषण डालने वालों से जुर्माने की वसूली प्रशासन या निकाय करेगा यह स्पष्ट नहीं है. पालिका को जो भी निर्देश मिलेंगे उनका पालन किया जाएगा. नगरपालिका मुनि की रेती-ढालवाला अध्यक्ष शिवमूर्ति कंडवाल ने कहा कि निकाय के पास इतनी मैनपावर नहीं है कि वह गंगा तटों की निगरानी कर सके. इस तरह के आदेश का पालन इतनी जल्दी सम्भव नहीं है. हरिद्वार को पॉलीथीन मुक्त करने का प्रयास सराहनीय है. धर्मशालाओं पर सख्ती उचित नहीं होगी, क्योंकि धर्मशालाएं जनता के हित के लिए हैं. जिन मुद्दों पर सख्ती की गई है उनके लिए विकल्प की भी आवश्यकता है. ■

राज्य सरकार देगी सभी शहीद के परिवारों को नौकरी

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भारत द्वारा पाकिस्तान पर 16 दिसंबर 1971 को मिली एतिहासिक की याद में राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में विजय दिवस के मौके पर लड़ाई में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी. इस मौके पर हरीश रावत ने शहीद जवानों के परिवार से कम से कम एक बच्चे को जरूर नौकरी देने की घोषणा की. मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि वष 1971 की लड़ाई में पाकिस्तानी सेना को 90 हजार सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा, जिससे एक अलग राष्ट्र का निर्माण हुआ. प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में आजादी के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा गौरव का क्षण था. पहले विक्टोरिया क्रास दरबान सिंह से लेकर अंलकृत सैनिकों की गाथा में एक हजार से ज्यादा शूरवीरों के नाम जुड़ चुके हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि वीर नारियों के कम से कम एक बच्चे को सरकार नौकरी देना सुनिश्चित करेगी. रावत ने एलान किया कि इसकी कार्ययोजना उपनल तैयार करेगा. सीएम ने पूर्वसैनिकों के पुनर्वास के लिए उपनल को स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम चलाकर उन्हें स्किल वर्कर की श्रेणी में शामिल करने को कहा है.

सीएम ने उपनल के एमडी ब्रिगेडियर अजय नंद बहुगुणा को इसके लिए विशेष भर्ती कार्ययोजना तैयार कर 6 माह में पात्र को नौकरी देना सुनिश्चित करने का आदेश दिया. उन्होंने उपनल को पूर्व सैनिकों को कुशल श्रेणी में अधिक वेतन के साथ रोजगार देने के लिए स्किल डेवलपमेंट कोर्स चलाने के लिए कहा है. इससे पूर्व सैनिकों को उपनल से मिलने वाले वेतन में वृद्धि होगी. सैनिक कल्याण मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार शहीदों के आश्रितों और पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए गंभीर है. सरकार शहीदों के परिवार ने जो खोया है उसकी भरपाई तो नहीं कर सकती, लेकिन उनके परिवारों के सम्मान और कल्याण के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है. इतना ही नहीं ब्लाक प्रतिनिधियों का वेतन ढाई हजार से 6 हजार रुपये मासिक किया गया है. सिपाही को उपनल से मिलने वाली भर्ती में अकुशल से कुशल श्रेणी में लाया जा रहा है. हर जनपद में पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए भर्ती पूर्व प्रशिक्षण केंद्र शुरू किए जाएंगे. समारोह में अलंकृत सैनिकों और वीर नारियों को सीएम, सैनिक कल्याण मंत्री, राज्य सैनिक कल्याण परिषद अध्यक्ष सहित पूर्व लेफ्टिनेंट जनरलों ने सम्मानित किया.

आपरेशन राइनो में शहीद हुए पौड़ी के सूबेदार धर्मवीर सिंह की पत्नी अनिता और मां सरस्वति देवी को सीएम ने दस लाख का चेक दिया. समारोह में 76 शहीद सैनिकों के आश्रित और अलंकृत सैनिकों को सम्मानित किया गया. शौर्य और विजय दिवस पर पूर्व सैनिकों से किए वादों पर अमल के लिए मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दो करोड़ रुपये विभाग को देने की घोषणा की. सीएम ने दोनों दिवसों पर हुई घोषणाओं के लिए धन की कमी को आड़े नहीं आने देने की बात कही. साथ ही एक कमेटी भी बना दी है. जनपदों में प्रेरणा स्थल, शिक्षण संस्थान और सड़कों को शहीदों के नाम पर करने के लिए हर जिले में डीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी है. ■

feedback@chauthiduniya.com

प्रधानी चुनाव में बढ़ी महिलाओं की हिस्सेदारी

धर्मेंद्र सिंह

उत्तर प्रदेश में प्रधानी चुनाव के नतीजों की घोषणा के साथ ही गांवों में नई सरकार अस्तित्व में आ गई. इस बार गांवों में नौजवानों की सरकार बनी है. एक अनुमान के मुताबिक तकरीबन 50 फीसदी से अधिक गावों में युवा प्रधान निर्वाचित हुए हैं. लेकिन इन चुनाव नतीजों की सबसे बड़ी खासियत महिला उम्मीदवारों की जीत है. उत्तर प्रदेश में पंचायतों की 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, लेकिन महिलाओं ने इससे कहीं आगे बढ़ते हुए प्रदेश की 44 प्रतिशत सीटों पर अपना परचम लहराया है. लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई की यह तस्वीर समाज में महिलाओं की सुदृढ़ होती स्थिति की ओर इशारा करती है. इस बार पिछली बार की तुलना में महिला प्रधानों की संख्या में इज़ाफा हुआ है. प्रदेश की 58,909 ग्राम पंचायतों के मुखिया पद की लिए हुई जंग में 6 लाख 77 हजार 670 उम्मीदवार थे. युवा प्रधानों की जीत से यह मुमकिन हुआ है कि युवा अपने गांव के साथ-साथ देश के भविष्य को लेकर चिंतित हैं और वे अपने गांव के विकास के साथ देश के विकास में भागीदार बनना चाहते हैं. प्रधान निर्वाचित हुए युवाओं में से कुछ उच्च शिक्षित हैं, तो कुछ प्रोफेशनल्स व टेक्नोक्रेट्स भी हैं. ऐसे लोगों के राजनीति में आने से निश्चित तौर पर देश और प्रदेश की राजनीति का भविष्य बेहतर दिखाई पड़ रहा है.

पंचायत चुनावों के परिणामों की घोषणा के बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त सतीश अग्रवाल ने महिलाओं की बढ़ी भागीदारी और बढ़े जीत के प्रतिशत को महिला सशक्तिकरण माना, उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि महिलाएं भविष्य में राज्य की राजनीति में बड़ी भूमिका अदा करेंगी. महिलाओं की जीत की कहानी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में भी लिखी गई. संभल, रामपुर और मुरादाबाद जिलों में महिलाओं ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और 50 प्रतिशत से ज्यादा पदों पर महिलाएं चुनी गईं. महिलाओं के निर्वाचन के मामले में संभल जिला सबसे आगे रहा यहां 54.5 प्रतिशत महिलाएं प्रधान के रूप में निर्वाचित हुईं हैं, लेकिन इस मामले में सबसे पीछे मथुरा रहा, मथुरा में केवल 36.7 प्रतिशत गावों में महिलाएं प्रधान निर्वाचित हो सकीं. महिलाओं की चुनाव में भागीदारी और जीत में संतुलन रहा. कुल प्रत्याशियों(4,77,814) में से 55.21 प्रतिशत पुरुष और 44.79 प्रतिशत महिलाएं थीं. 43.86 प्रतिशत महिलाएं जीत हासिल करने में कामयाब रहीं. जबकि 56.14 प्रतिशत पुरुष कामयाब रहे. अधिकारियों के मुताबिक इस बार जिन महिलाओं और युवाओं ने जीत हासिल की है उनमें से अधिकांश की किसी तरह की राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रही है. प्रदेश में 19 पीएचडी डिग्री धारक प्रधान बने हैं जिनमें से 4 महिलाएं हैं.

प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की मिसाल बनी बलात्कार पीड़िता शीलू निषाद बांदा के ग्राम पंचायत करकोला से प्रधानी का चुनाव हार गईं. वह पिछले कुछ सालों से महिलाओं के अधिकारों की बुंदेलखंड क्षेत्र में लड़ाई लड़ रही हैं. जब शीलू 17 वर्ष की थीं तब नरैनी के विधायक पुरुषोत्तमनाथ द्विवेदी ने शीलू का रेप किया था. इस स्थिति से आगे बढ़कर महिलाओं के लिए इस क्षेत्र में काम कर रही थीं, लेकिन उनकी हार से महिलाओं के बीच एक गलत संदेश भी गया है.

महिलाओं की 44 प्रतिशत सीटों पर जीत से उनके अबला होने की बात अब पीछे छूट गई है, महिलाओं ने महिलाओं के लिए वोट किया. लेकिन महिलाओं के चुनावी पोस्टर्स और पर्चों पर उनके पति, ससुर, देवर या परिवार के अन्य किसी सदस्य की तस्वीर दिखाई देती रही. लेकिन जिस तरह से महिलाओं ने जीत दर्ज की है उससे प्रधान पति वाली परिपाटी कुछ हद तक टूटती दिखी. महिलाओं की भागीदारी और जीत से यह लगता है कि महिलाएं राजनीति में अपनी अलग जगह बनाने के लिए तैयार हैं. प्रदेश की सत्तारूढ़ समाजवादी सरकार केंद्र में महिला आरक्षण विधेयक या कहें संसद में महिलाओं के आरक्षण का विरोध करती रही है. ऐसे में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र सभी राजनीतिक दलों के पास यह संदेश गया है कि वे आधी आबादी को उसके राजनीतिक अधिकार से ज्यादा समय तक वंचित नहीं रख सकते. उन्हें उनके अधिकार देने होंगे नहीं तो वह अपना हक़ अपनी ताकत और एक जुटता के बल पर हासिल कर लेंगी. परिवार का राजनीतिक विचार महिला का भी विचार हो अब यह परिपाटी टूट रही है. इसकी एक झलक प्रधानी के चुनावों में दिखाई दी.

जहां गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले युवाओं और महिलाओं ने प्रधानी चुनाव में जीत हासिल की वहीं राज्य के कई बड़े नेताओं और रिश्तेदारों को भी हार का मुह देखना पड़ा. प्रदेश के खाद्य एवं रसद राज्यमंत्री लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद की पत्नी हेमवती निषाद चुनाव हार गईं. बहराइच में महसी से बसपा विधायक के के ओझा की मां मंशा देवी पिपरा ग्राम पंचायत से चुनाव हार गईं. सीतापुर के ब्लॉक खैराबाद की ग्राम पंचायत बनका जलालपुर से सूबे के कारागार राज्यमंत्री रामपाल राजवंशी की समधिन सुमरिता देवी चुनाव हार गईं. ■

feedback@chauthiduniya.com

21 साल में बने प्रधान

बस्ती में हरैया ब्लाक के डुहवा मिश्र ग्रामसभा से 21 वर्षीया रूपम शर्मा प्रधान बनीं. स्नातक तक शिक्षित रूपम का कहना है कि आवश्यक संसाधनों के अभाव में जूझ रही गांव की जनता को राहत पहुंचाने का प्रयास करूंगी.

चाय वाली बनीं प्रधान

एटा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरणा लेकर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाली बीएड शिक्षित पूजा ने भी राजनीति में कदम रखने का सपना देखा. पटियाली मजराजात से प्रधानी का चुनाव लड़ीं और विजयी रहीं. अब वह गांव की तकदीर बदलना चाहती हैं.

लाटरी तो कहीं टॉस से फैसला

मुकाबला बराबरी पर रहने पर बलरामपुर में रेहरा बाजार के सहजौरा में प्रधान पद का परिणाम लाटरी के जरिए किया गया. श्रावस्ती में विशेश्वरगंज ब्लॉक के उधरना सरहदी में टॉस के आधार पर परिणाम घोषित किया गया. हाथरस की ग्राम पंचायत वीरनगर में लाटरी से परिणाम घोषित किया गया. ■

112 वर्ष की सरपंच

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में वैसे तो लाखों ग्राम प्रधान और पंचायत सदस्य चुने गए, लेकिन आजमगढ़ जिले में 112 साल की बुजुर्ग महिला ने भारी मतों से ग्राम प्रधान का चुनाव जीत कर रिकॉर्ड कायम किया है. आजमगढ़ जिले के फुलपुर ब्लॉक के आदमामऊ गांव की जनता ने 112 वर्षीय नौराजी देवी को अपना मुखिया चुना है. नौराजी देवी ने अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी रूकैया को 545 मतों से पराजित किया. रूकैया को मजह 187 मत हासिल हुए. नौराजी देवी के ग्राम प्रधान चुने जाने के बाद गांव में ग्रामीणों ने चौपाल का आयोजन कर अपनी नई प्रधान का सम्मान किया. 112 वर्ष की होने की वजह से वह कम सुन पाती हैं लेकिन उनके होसले बुलंद हैं. वे गांव का विकास कराना चाहती हैं साथ ही महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काम करना चाहती हैं. इससे पहले उनके उनके पौत्र अमर सिंह पिछले 10 वर्षों से गांव प्रधान थे, लेकिन इस बार सीट महिला उम्मीदवार के लिए सुरक्षित होने की वजह से उन्होंने नौराजी देवी को चुनाव मैदान में उतार दिया और वे चुनाव जीत गईं. उनकी जीत का सबसे बड़ा कारण यह भी है कि इतनी उम्रदराज होने के बावजूद नौराजी देवी कभी घर पर नहीं बैठतीं. गांव में किसी के यहां कोई भी कार्यक्रम हो वह अपनी लाठी के सहारे वहां पहुंच जातीं और लोगों के सुख-दुख में शरीक होती हैं. इस वजह से गांव के हर घर में इनकी पहुंच है. इसका फायदा उन्हें हुआ और वह चुनाव जीतने में सफल हुईं. ■

पंचायत चुनावों के परिणामों की घोषणा के बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त सतीश अग्रवाल ने महिलाओं की बढ़ी भागीदारी और बढ़े जीत के प्रतिशत को महिला सशक्तिकरण माना, उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि महिलाएं भविष्य में राज्य की राजनीति में बड़ी भूमिका अदा करेंगी. महिलाओं की जीत की कहानी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में भी लिखी गई. संभल, रामपुर और मुरादाबाद जिलों में महिलाओं ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और 50 प्रतिशत से ज्यादा पदों पर महिलाएं चुनी गईं. महिलाओं के निर्वाचन के मामले में संभल जिला सबसे आगे रहा यहां 54.5 प्रतिशत महिलाएं प्रधान के रूप में निर्वाचित हुईं हैं, लेकिन इस मामले में सबसे पीछे मथुरा रहा, मथुरा में केवल 36.7 प्रतिशत गावों में महिलाएं प्रधान निर्वाचित हो सकीं.

फैशन डिजाइनर प्रधान

सरसईनावर की ग्राम पंचायत चंदरपुरा से युवा प्रियंका यादव 574 मतों से विजयी हुई. 23 वर्षीय प्रियंका बैंगलोर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नॉलॉजी (एनआईएफटी) से फैशन डिजाइनिंग कर चुकी हैं.

उम्र 97 वर्ष, आठवीं बार प्रधान

कुशीनगर के खड्डा विकास के ग्रामसभा रामपुर जंगल से प्रधान पद के अनारक्षित सीट पर 97 वर्षीय राजेश्वर दूबे उर्फ झक्कर दुबे आठवीं बार प्रधान निर्वाचित हुए. आज भी उनका परिवार झोपड़ी में रहता है.

डकैतों और माफियाओं के पारिवारिक सदस्यों की जीत

चित्रकूट में पूर्व डकैत खडग सिंह की पत्नी माया देवी चित्रकूट के मानिकपुर ब्लाक के मडैय्यन गांव से दोबारा प्रधान निर्वाचित हुई. पुलिस मुठभेड़ में मारे जा चुके डकैत चुन्नी पटेल के छोटे भाई की पत्नी उमा देवी भी चित्रकूट के सदर ब्लाक के घुरेटनपुर से प्रधानी का चुनाव जीत गईं. चित्रकूट के ददरीमाफी से चुनाव लड़ी डकैत गौरी यादव की मां राजरानी चुनाव जीत गईं. मेरठ में कुख्यात माफिया योगेश भदौड़ा के मृत भाई प्रमोद की पत्नी कविता दूसरी बार प्रधान बनीं. कविता के सामने योगेश के दुश्मनों की बीवियां भी मैदान में थीं. मेरठ के ही परीक्षित गढ़ ब्लॉक के ग्राम आलमगीरपुर बढ़ला में कुख्यात चीकू बढ़ला की पत्नी अर्चना चौधरी ने जीत दर्ज की. रोहटा क्षेत्र के दबंग विजेंद्र जिंजाखर की पत्नी अंजय ने भी एक तरफा जीत दर्ज की.

खुद को भी नहीं दिया वोट

बस्ती के बहादुरपुर ब्लॉक की गौसपुर पंचायत में चुनाव लड़ रहे प्रमोद कुमार को एक भी मत नहीं मिला है. यानी प्रमोद ने खुद को भी वोट नहीं दिया.